शुक्रवार, 13 फरवरी 2026

Epaper.samagya.in

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। यद् भद्रं तन्न आ सुव।।

समाज्ञा

कोलकाता, फाल्गुन कृष्णपक्ष एकादशी, वि.स. 2082, पृष्ठ 8, मूल्य 3.00 रुपये

मौसम

तापमान	16 – 28
आर्द्रता	66%
सूर्योदय: 06:10	सूर्यास्त: 17:32

इशान, पंड्या और चक्रवर्ती चमके, भारत ने नामीबिया को 93 रन से रौंदा पृष्ठ 8

स्थानीय खबरें पृष्ठ तीन, चार और पांच पर

सुविचार : समझ तब गहरी होती है, जब हम सुनना सीख जाते हैं।

114 नए राफेल खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी

50 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी उत्पादन होगा शामिल , 96 भारत में बनेंगे

फ्रेंच प्रेसिडेंट मैंक्रों के भारत आने पर हो सकता हैं सौंदा

नयी दिल्ली : रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान की खरीद के काफी समय से लंबित प्रस्ताव को बृहस्पतिवार को मंजूरी दे दी। आधिकारिक बयान के अनुसार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने सशस्त्र बलों की युद्धक तैयारी को मजबूत करने के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपये के सैन्य उपकरणों की पूंजीगत खरीद को मंजूरी दी। सूत्रों ने बताया कि इस परियोजना के तहत, राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन द्वारा 18 विमान सीधे 'उड़ान भरने की स्थिति' में आपूर्ति किए जाएंगे और शेष विमानों का निर्माण भारत में किया जायेगा, जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी उत्पादन शामिल होगा और यह उत्पादन चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। रक्षा मंत्रालय ने खरीद की लागत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन अनुमान है कि यह 2.90 लाख करोड़ रुपये से 3.15 लाख करोड़ रुपये के बीच होगी। राफेल विमानों की खरीद को मंजूरी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की भारत यात्रा से ठीक चार दिन पहले मिली। इस सौदे को हालांकि अंतिम रूप देने के लिए औपचारिक अनुबंध इस साल के अंत से पहले होने की संभावना नहीं है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय को अब हथियारों के पैकेज की लागत और बारीक विवरणों को अंतिम रूप देने के लिए दसॉल्ट एविएशन के साथ बातचीत करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) को भी अधिग्रहण कार्यक्रम को अंतिम मंजूरी देनी होगी। अप्रैल 2019 में, भारतीय वायुसेना ने लगभग 18 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत से 114 बहु-उद्देश्यीय लड़ाकू विमान (एमआरएफए) की खरीद के लिए एक आरएफआई (सूचना के लिए अनुरोध), या प्रारंभिक निविदा जारी की।

एचएएल से 2,312 करोड़ रुपए में 8 डोर्नियर विमान खरीदने की डील

रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के वास्ते आठ डोर्नियर विमानों की खरीद के लिए सरकारी स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ बृहस्पतिवार को 2,312 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में खरीद समझौते को अंतिम रूप दिया गया। यहां जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) के लिए परिचालन संबंधी उपकरणों सहित आठ डोर्नियर 228 विमानों की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ 2,312 करोड़ रुपये की लागत से 'बाइ (इंडियन) श्रेणी' के तहत एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।

हम किसी को अरावली को छूने की अनुमति नहीं देंगे : उच्चतम न्यायालय

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह ''किसी को भी अरावली की पहाड़ियों को छूने'' की अनुमति नहीं देगा। इसी के साथ विशेषज्ञों द्वारा ''अरावली पर्वतमाला'' की परिभाषा स्पष्ट किए जाने तक हरियाणा सरकार को जंगल सफारी पर विस्तृत योजना प्रस्तुत करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत,न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने कहा कि अरावली पहाड़ियों से संबंधित मुख्य मामले पर विचार करते समय 'जू सफारी' के मुद्दे पर भी संज्ञान लिया जाएगा। हरियाणा का पक्ष रखने के लिए पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने सफारी परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को 10,000 एकड़ से संशोधित करके 3,300 एकड़ से अधिक कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे केवल इतना चाहते हैं कि उन्हें डीपीआर को केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) के समक्ष समीक्षा के लिए प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। पीठ ने कहा, ''हम विशेषज्ञ नहीं हैं। अरावली की परिभाषा विशेषज्ञ तय करेंगे। जब तक अरावली पहाड़ियों की परिभाषा अंतिम रूप से तय नहीं हो जाती, हम किसी को भी अरावली को छूने की अनुमति नहीं देंगे।'' प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अरावली केवल हरियाणा या राजस्थान की ही नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी पर्वत शृंखला है जो कई राज्यों से होकर गुजरती है। उन्होंने हरियाणा सरकार के वकील से कहा, ''हम जू सफारी के मुद्दे पर मुख्य मामले के साथ ही विचार करेंगे।''इस पर हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि मुख्य मामला बिल्कुल अलग है और जंगल सफारी का मुद्दा अलग है। पीठ ने इसपर टिप्पणी की, ''कभी-कभी, सीईसी अनुमति देने में बहुत चुनिंदा रवैया अपनाता है। अगर हम इसकी अनुमति देते हैं, तो वे बहुत ही आकर्षक तस्वीर पेश करेंगे कि ये पेड़, वन्यजीव और जंगल हैं।'' सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि विशेषज्ञ समिति की राय आने के बाद वह सफारी परियोजना पर विचार करेगी।

RED-X
B.W.P. PLY,
BOARDS& DOORS
'X' Factor that Makes A Difference
Stockist :
GULAB CHAND
LAL CHAND& Co.
9831114555
9874415555

बांग्लादेश में हिंदू चाय बागान मजूदर की हत्या

ढाका : पूर्वोत्तर बांग्लादेश के मौलवीबाजार इलाके में एक युवा हिंदू चाय बागान मजदूर का खून से लथपथ शव मिला है और उसके हाथ-पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। स्थानीय मीडिया ने बृहस्पतिवार को यह खबर दी। बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को मतदान से पहले, यह लगातार दूसरे दिन किसी हिंदू व्यक्ति की हत्या किए जाने का मामला है। पुलिस ने बुधवार को ढाका से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित मौलवीबाजार के कमलगांज उपजिले के एक चाय बागान से 28 वर्षीय रतन शुवो कार का शव बरामद किया। 'द डेली स्टार' ने कमलगांज पुलिस थाने के प्रभारी अब्दुल अवाल के हवाले से खबर दी कि मृतक रतन शुवो कार इस्लामपुर यूनियन के अंतर्गत चंपारा चाय बागान में बतौर मजदूर काम करता था। खबर के मुताबिक स्थानीय लोगों ने बुधवार पूर्वाह्न करीब 10:00 बजे बागान में शव को देखा और अधिकारियों को सूचना दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक शव पर चोट के स्पष्ट निशान थे और वह खून से लथपथ था। रतन के बड़े भाई लक्ष्मण कार ने बताया कि परिवार मंगलवार रात से ही उसकी तलाश कर रहा था। उन्होंने बताया, ''बुधवार सुबह हमें सूचना मिली कि उसका शव बागान में पड़ा है। हम वहां गए और उसकी पहचान की। हमें नहीं पता कि उसकी हत्या क्यों की गई।''

निशिकांत दुबे ने राहुल के खिलाफ दिये नोटिस पर लोकसभा में चर्चा कराने की मांग की

नयी दिल्ली : भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दिये गए एक विशिष्ट नोटिस पर सदन में चर्चा कराने की बृहस्पतिवार को मांग की। शून्य काल के दौरान, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद ने राहुल पर सोरोस फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन के साथ संबंध रखने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया, ''नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का सोरोस फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन के साथ संबंध है।'' भाजपा सदस्य ने दावा किया कि राहुल गांधी केवल देशद्रोहियों से मिलने वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन और थाईलैंड जाते हैं। दुबे ने यह भी आरोप लगाया, ''वह (राहुल) कभी निर्वाचन आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी लोकसभा अध्यक्ष पर, उच्चतम न्यायालय पर...जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन पर आरोप लगाते हैं।'' उन्होंने कहा, ''मेरा आग्रह है कि एक विशिष्ट प्रस्ताव पर राहुल गांधी पर चर्चा होनी चाहिए। उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और वह कभी चुनाव नहीं लड़ पाएं।'' उन्होंने सदन की कार्यप्रणाली के नियम 352 (5) और 353 के तहत इस प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति देने का आसन से अनुरोध किया। कांग्रेस सदस्यों द्वारा इस पर कड़ा विरोध जताने और सदन में शोर-गुल होने के कारण पीठासीन सभापति कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। दुबे ने इससे पहले संसद परिसर में 'पीटीआई-वीडियो' से बातचीत में कहा था कि उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ ''विशिष्ट प्रस्ताव'' लाने के लिए एक नोटिस दिया है।

बांग्लादेश चुनाव- बीएनपी को बहुमत मिला, 159 सीटें जीतीं

तारिक रहमान का अगला पीएम बनना तय

ढाका : बांग्लादेश में गुरुवार को हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) को बहुमत मिल गया है। पार्टी ने 299 सीटों में से 159 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। रहमान ने दो सीटों पर चुनाव लड़ा था, दोनों सीटों पर जीत हासिल हुई है। वहीं जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 पार्टियों के गठबंधन को अब तक सिर्फ 45 सीटें मिली हैं। जमात चीफ शफीकुर रहमान ने ढाका-15 सीट से जीत दर्ज की है। 2 सीटों पर अन्य पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत हुई है। अब 206 सीटों के नतीजे सामने आए हैं। आम चुनाव के लिए दोपहर 2 बजे तक 48% वोटिंग हुईं। मतदान 4:30 तक चला। अभी कुल मतदान के आंकड़े आने बाकी हैं।

निपाह वायरस के संक्रमण से मुक्त हुई नर्स की हृदयगति रुकने से मौत

कोलकाता, समाज्ञा : पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के संक्रमण से उबर चुकी 25 वर्षीय एक नर्स की बारासात जिले के एक निजी अस्प-ताल में गुरुवार को हृदयगति रुकने से मौत हो गई। राज्य स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, नर्स लंबे समय तक कोमा में रही, जिससे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई और बाद में उसे फेफड़ों में संक्रमण हो गया। उन्होंने बताया कि नर्स को जनवरी के अंत में जीवन-रक्षक प्रणाली से हटाया गया था। अधिकारी ने बताया कि गुरुवार की दोपहर हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। वह निपाह संक्रमण से उबर चुकी थीं, लेकिन वह कई जटिलताओं से पीड़ित थीं। उन्होंने बताया कि नर्स पूर्व बर्दवान जिले के कटवा की रहने वाली थीं और लंबे समय से कोमा में थीं, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कमजोर हो गई थी। इलाज के दौरान उन्हें फेफड़ों का संक्रमण और अस्पताल से भी संक्रमण हो गया। अधिकारी ने बताया कि वह होश में आने, अपने अंगों को हिलाने और बोलने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन अचानक उनकी हालत बिगड़ गई। उनकी मौत शाम करीब 4:20 बजे हुई।

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार समझौते को 'ऐतिहासिक' बताया

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार समझौते को ''ऐतिहासिक'' बताते हुए कहा कि अमेरिका इस देश तथा अन्य उन देशों को कोयले के निर्यात में वृद्धि करेगा जिनके साथ उसने व्यापार समझौते किए हैं। ट्रंप ने 'चैंपियन ऑफ कोल' शीर्षक वाले एक कार्यक्रम के दौरान बुधवार को कहा, ''और हमारे नेतृत्व में, हम एक विशाल ऊर्जा निर्यातक बन रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में ही हमने जापान, कोरिया, भारत और अन्य के साथ ऐतिहासिक व्यापार समझौते किए हैं ताकि हमारे कोयला निर्यात को बढ़ाया जा सके।''

दिव्यांगता पेंशन राज्य की कृपा पर निर्भर कोई अनुग्रह राशि नहीं : न्यायालय

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिव्यांगता पेंशन न तो कोई इनाम है और न ही राज्य की कृपा पर निर्भर कोई अनुग्रह राशि है, तथा सरकार अपने दृष्टिकोण में चयनात्मक या असमान नहीं हो सकती है। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने पूर्व सैनिकों को दिव्यांगता पेंशन के भुगतान संबंधी सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की अपील को खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं। न्यायालय ने कहा कि दिव्यांगता पेंशन कोई दान-पुण्य का मामला नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा में किए गए बलिदान की मान्यता है। पीठ ने कहा, इस न्यायालय द्वारा विधिवत स्थापित सिद्धांत के अनुसार पेंशन न तो कोई अनुग्रह राशि है और न ही राज्य की कृपा पर निर्भर अनुग्रह भुगतान। यह पूर्व में दी गई सेवाओं का विलंबित हिस्सा है और निर्धारित शर्तों की पूर्ति होने पर यह एक निहित एवं विधिसम्मत रूप से प्रवर्तनीय अधिकार के रूप में परिवर्तित हो जाती है।

भारत की आर्थिक वृद्धि में पशु चिकित्सकों की अहम भूमिका है : मोहन भागवत

नागपुर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश के आर्थिक विकास में पशु चिकित्सकों की अहम भूमिका है और उन्होंने उनसे पारंपरिक जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर अपना नजरिया व्यापक करने की अपील की। भागवत ने सह-अस्तित्व की भावना पर जोर देते हुए कहा कि मनुष्यों, जानवरों और प्रकृति के बीच बेहतर सामंजस्य रहना चाहिए और समाज को इस बात पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि संतुलित सह-अस्तित्व कैसे सुनिश्चित किया जाए। भागवत यहां 'इंडियन सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ कैनाइन प्रैक्टिस' और महाराष्ट्र पशु एवं मत्स्य पालन विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। संघ प्रमुख ने कहा, ''पहले हम सोचते थे कि पशु चिकित्सक के तौर पर हमारी भूमिका सीमित है। लेकिन हमें अपनी सोच बदलने और अपने लिए एक व्यापक नजरिया और बड़ी भूमिका की कल्पना करने की जरूरत है।'' उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सक सिर्फ पशुओं के विशेषज्ञ ही नहीं हैं, बल्कि समाज में भी अहम हितधारक हैं और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं।

आत्मनिर्भर भारत: असम राइफल्स अपने श्वान दस्ते में अब भारतीय नस्ल के कुत्तों को शामिल करेगा

जोरहाट (असम) : केंद्र सरकार के स्वदेशीकरण के आह्वान को मजबूती प्रदान करते हुए असम राइफल्स अपने विभिन्न अभियानों को अंजाम देने के लिए अपने दस्ते में भारतीय नस्ल के कुत्तों को शामिल करने की योजना बना रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। 'असम राइफल्स श्वान प्रशिक्षण केंद्र' के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल आलोक पालेई ने यहां 'पीटीआई-भाषा' को दिए एक साक्षात्कार में बताया कि 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत सबसे पुराने अर्धसैनिक बल ने पहले ही एक प्रायोगिक परियोजना के तहत 'तंगखुल हुई' नस्ल के कुत्तो को अपने 'श्वान दस्ते' में शामिल कर लिया है।

अमेरिका के सिएटल ने भारतीय छात्रा की मौत के मामले में परिवार से 262 करोड़ में किया समझौता

सिएट : अमेरिका के सिएटल शहर ने 2023 में एक पुलिस अधिकारी की तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर लगने से जान गंवाने वाली भारत की 23 वर्षीय स्नातकोत्तर छात्रा जाह्नवी कंदुला के परिवार के साथ 262 करोड़ के समझौते पर सहमति जताई है। कंदुला को अधिकारी केविन डेव की गाड़ी ने उस समय टक्कर मारी थी, जब वह मादक पदार्थ संबंधी एक कॉल के बाद कार्रवाई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की सीमा वाले क्षेत्र में 119 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे थे। उनकी गाड़ी की आपातकालीन लाइट जल रही थीं और चौराहों पर सायरन का इस्तेमाल भी किया जा रहा था। सिटी अटॉर्नी एरिका इवांस ने बुधवार को जारी बयान में कहा, जाह्नवी कंदुला की मौत हृदयविदारक है और शहर को उम्मीद है कि यह वित्तीय समझौता कंदुला परिवार को कुछ हद तक संतोष प्रदान करेगा। जाह्नवी कंदुला का जीवन महत्वपूर्ण था। यह उनके परिवार, मित्रों और हमारे समुदाय के लिए मायने रखता था। कंदुला सिएटल स्थित नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी परिसर में सूचना प्रणाली (इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स) में मास्टर डिग्री के लिए पढ़ाई कर रही थीं।

आरबीआई की रिकवरी एजेंटों पर नकेल, कर्जदारों के लिए आए नए नियम

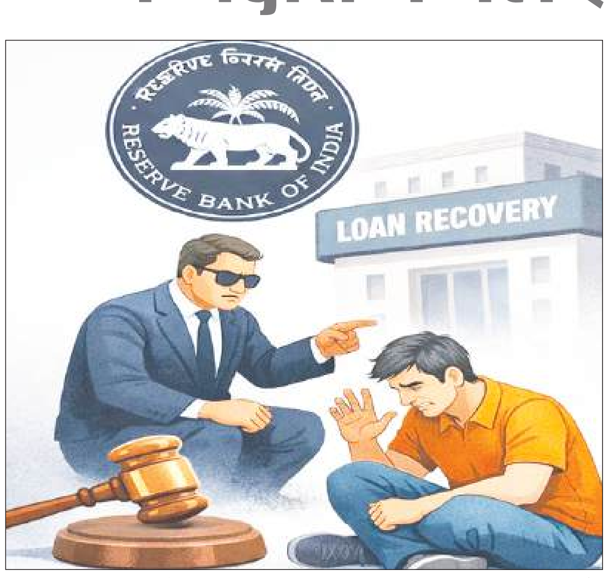

नई दिल्ली : अब बैंक या रिकवरी एजेंट मनमर्जी से कर्जदारों को परेशान नहीं कर पाएंगे। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि लोन रिकवरी की आड़ में न तो किसी की गरिमा से खिलवाड़ होगा और न ही निजता का उल्लंघन। 12 फरवरी 2026 को जारी नए ड्राफ्ट नियमों के जरिए केंद्रीय बैंक ने साफ संदेश दिया है कि पैसा वसूलने का मतलब यह कतई नहीं है कि आप किसी के घर जाकर बदतमीजी करें या बेवक्त फोन कर मानसिक तनाव दें। यह नई नियमावली 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होने जा रही है।सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक यह है कि अब रिकवरी एजेंटों के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस से सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना जरूरी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट के कोई भी व्यक्ति कर्ज वसूली की गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकेगा। इससे वसूली प्रक्रिया में पेशेवर व्यवहार आने की उम्मीद है।

ग्राहकों की सुविधा के लिए 3 नियम

1. गलत प्रोडक्ट नहीं बेच सकेंगे

* बैंक या वित्तीय संस्थान ग्राहकों को उनकी जरूरत या जोखिम क्षमता के हिसाब से गलत प्रोडक्ट नहीं बेच करेंगे।

* अगर वे ग्राहक को गलत प्रोडक्ट बेचेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी।

2. लोन रिकवरी एजेंट परेशान नहीं करेंगे

* रिजर्व बैंक का दूसरा दिशानिर्देश लोन की वसूली और वसूली एजेंटों के व्यवहार को लेकर होगा।

* इससे यह सुनिश्चित होगा कि लोन वसूलने के नाम पर ग्राहकों को परेशान न किया जाए।

3. फ्रॉड होने पर सीमित जिम्मेदारी

* तीसरा दिशानिर्देश अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देनदारी को सीमित करने पर होगा।

* अगर आपके खाते से बिना आपकी जानकारी के पैसे निकल जाते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी एक निश्चित सीमा तक ही होगी।

इसके तहत ग्राहकों को 25,000 रुपये तक की राशि का मुआवजा मिल सकता है।

रेरा दागी बिल्डरों को सुविधा प्रदान करने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है : उच्चतम न्यायालय

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि सभी राज्यों के लिए रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) के गठन पर पुनर्विचार करने का यह सही समय है क्योंकि यह संस्था दागी बिल्डरों को सुविधा प्रदान करने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि जिन लोगों के लिए रेरा बनाया गया था, वे ''पूरी तरह से निराश और हताश'' हैं। पीठ ने जोर देकर कहा कि अगर इस संस्था को समाप्त कर दिया जाए तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। पीठ ने हिमाचल प्रदेश सरकार को रेरा के कार्यालय को अपनी पसंद के स्थान पर स्थानांतरित करने की अनुमति देते हुए ये टिप्पणियां कीं। हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य द्वारा दायर याचिका पर पीठ ने नोटिस जारी किया, जिसमें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जो राज्य के रेरा कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने से संबंधित था। उच्च न्यायालय ने इससे पहले रेरा कार्यालय के स्थानांतरण से संबंधित जून 2025 की अधिसूचना पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। बाद में, 30 दिसंबर 2025 को अपने आदेश में, उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश को जारी रखने का निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय ने 30 दिसंबर के उच्च न्यायालय के निर्देश पर रोक लगा दी है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ''दागी बिल्डरों को सुविधा देने के अलावा यह संस्था (रेरा) कुछ नहीं कर रही है। बेहतर होगा कि इस संस्था को समाप्त कर दिया जाए, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है ...अब समय आ गया है कि सभी राज्य इस प्राधिकरण के गठन पर ही पुनर्विचार करें।''

सोशल मीडिया नियमन की जटिलताएं

डीपफेक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से झूठ को सच बनाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर केंद्र सरकार ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। इस तरह के भ्रमित करने वाली सामग्री प्रसारित करने वाले सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाले नियमों को सख्त बनाया जा रहा है। जिससे डिजिटल कंपनियों और प्लेटफॉर्मों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, खासकर डीपफेक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई से निर्मित सामग्री के संबंध में। दरअसल, ये नवीनतम बदलाव उन शिकायतों के बाद किए गए हैं जिसमें एआई बॉट द्वारा पथभ्रष्ट करने वाली उत्तेजक छवियों के निर्माण करने के आरोप लगे हैं। जिसके खिलाफ दुनिया के कई देशों ने भी सख्त कदम उठाए हैं। उल्लेखनीय है कि आईटी के नये नियम बीस फरवरी से लागू होंगे। इसके बाद एआई के जरिये निर्मित सामग्री पर इस बात का लेबल लगाना जरूरी होगा कि उसे कृत्रिम रूप से गढ़ा गया है। साथ ही प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को उपयोगकर्ताओं को भरोसा दिलाना होगा कि साझा की जा रही सामग्री एआई द्वारा निर्मित है या नहीं। ऐसे वक्त में जब लोगों की संवेदनाओं और भरोसे से खिलवाड़ का खेल द्रुत गति से जारी है, केंद्र सरकार की ओर से उठाया गया यह जरूरी कदम कहा जा सकता है। सरकार ने नये प्रावधानों में निर्देश दिया है कि किसी भी अवैध या भ्रामक एआई जनित सामग्री को तीन घंटे के भीतर हटाना होगा या फिर ब्लॉक करना होगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले यह हटाने की समय सीमा 36 घंटे थी। हालांकि, इस तरह सख्त नियमों के जरिये सोशल मीडिया का नियमन खासा जटिल कार्य है। इस आदेश की जटिल कार्यप्रणाली के अतिरिक्त,यह सवाल भी विवाद का विषय बना हुआ कि ऑनलाइन आपत्तिजनक सामग्री किसे माना जाए। साथ ही यह भी कि क्या स्वीकार्य है? यदि हां तो किस आधार पर? वहीं दूसरी ओर इसके बहाने सरकारों द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की चिंताएं भी बरकरार हैं। सही मायनों में, लोकतंत्र की अपरिहार्य शर्त स्वतंत्र अभिव्यक्ति से जुड़ी इन चिंताओं का निराकरण भी जरूरी है।

निस्संदेह दुनिया में जैसे-जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता डिजिटल क्षेत्र में अपना दायरा बढ़ाती जा रही है, वैसे-वैसे ही प्रभावी नियामक नियंत्रण स्थापित करना एक कठिन चुनौती बनता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर एआई उद्योग के लिये भी, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में अपनी तकनीकों के विस्तार के साथ-साथ नैतिक ढांचों को बनाये रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बनता जा रहा है। उल्लेखनीय है कि एक प्रमुख कंपनी के सुरक्षा शोधकर्ता का विवादास्पद परियोजनाओं की अनियंत्रित गति से असहमति जताते हुए त्यागपत्र देना तकनीकी प्रगति की छलांग लगाती गति के दुष्परिणामों को ही उजागर करता है। निर्विवाद रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता जनित स्पर्धा के दौर में नैतिक दुविधा स्पष्ट है। साथ ही इसका कोई कारगर समाधान शीघ्र नजर भी नहीं आता। इस संकट से विकासशील देश ही नहीं, विकसित देश भी गहरे तक जूझ रहे हैं। आस्ट्रेलिया व फ्रांस आदि देशों में बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने की न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका में इंस्टाग्राम और यूट्यूब के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच के लिये एक ऐतिहासिक मुकदमा शुरू हो गया है। सोशल मीडिया कारोबार में दोनों हाथों से मुनाफा बटोरने वाली कंपनियों के देश अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों पर लोगों को लत लगाने वाली मशीनें बनाने के आरोप लग रहे हैं। इस बाबत एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख विशेषज्ञ की टिप्पणी है- हम देख रहे हैं कि अधिकाधिक युवा न केवल मनोवैज्ञानिक बल्कि शारीरिक पीड़ा का भी अनुभव करते हैं, जब उनसे फोन आदि उपकरण ले लिए जाते हैं। कमोबेश यही स्थिति भारत समेत तमाम विकासशील देशों में भी बनी हुई है। इस संकट का कोई स्थायी समाधान विश्व भर के लिये प्रासंगिक हो सकता है। निस्संदेह, इस बेहद घातक तकनीक आक्रमण से निबटना लगातार बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। निर्विवाद रूप से असली-नकली के भ्रम से जूझते उपयोगकर्ताओं की संवेदनाओं से खिलवाड़ का सिलसिला नियंत्रित होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर डीपफेक से धोखाधड़ी-गलत सूचनाओं के बढ़ते खतरों को नियंत्रित करने के लिये सख्त नियम के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के संचालकों को जवाबदेह बनाना भी जरूरी है।

आज का पंचांग

कोलकाता : 13 फरवरी, शुक्रवार, 2026, विक्रम सम्वत् 2082, फाल्गुन कृष्णपक्ष एकादशी, 14:23 तक, नक्षत्र : मूल, 16:02 तक, योग : वज्र, 27:17 तक, सूर्योदय: 06:10, सूर्यास्त: 17:32, चन्द्रोदय : 03:01, चन्द्रास्त: 13:39, शक सम्वतः 1947 विश्वावसु, सूर्य राशि : कुम्भ, चन्द्र राशि : धनु, राहू काल : 10:26 से 11:50

राशिफल

मेष : मेष राशि के जातकों को आज के दिन हर नए काम के कानूनी पहलुओं पर अच्छी तरह से गौर करके चलना होगा। व्यापार के सिलसिले में किसी की सलाह लेने की जरूरत पड़ सकती है।

वृष : वृष राशि के जातकों के लिए आज दिन की शुरूआत व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं को हल करने से होगी। प्यार के मामले में आज का दिन ठीक है।

मिथुन : मिथुन राशि वालों को आज दूसरों की भावनाओं को पहचानना होगा। अगर उनके अनुसार चलेंगे तो आपको काफी आत्म संतोष होगा। दूसरों की बात सुनने में कोई परहेज नहीं है।

कर्क : आज के दिन कर्क राशि वालों के पास खुद को साबित करने के कई मौके आएंगे। उन मौके को पहचान कर उन पर खरा उतरना आपकी जिम्मेदारी है। आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा।

सिंह : सिंह राशि के जातकों को आज किसी जानकार को छोटा मोटा कर्ज देना पड़ सकता है। किसी कठिन समस्या का हल निकल आएगा। बड़ों से सलाह लेना अच्छा रहेगा।

कन्या : कन्या राशि के लोगों के ऊपर आज ढेर सारी जिम्मेदारियां आ सकती हैं। घर के सभी पुराने लटके हुए कामों को पूरा करने का मौका मिलेगा।

तुला : शुक्रवार का दिन तुला राशि वालों के लिए अपनी पुरानी देनदारी चुकाने का होगा। कुछ जरूरी सामान की शापिंग करनी पड़ सकती है। अपनी जेब का खास ख्याल रखें।

वृश्चिक : आज वृश्चिक राशि के जातकों का दिन बहुत बिजी रखेगा। दिन के पहले हिस्से में कुछ जरूरी फोन और ईमेल्स का जवाब देना जरूरी होगा। अपनी सेविंग्स पर जरूर नज़र डाल लें।

धनु : धनु राशि वालों को आज आपके कर्मक्षेत्र में कुछ नए अधिकार दिए जा सकते हैं। किसी क्रियेटिव काम में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। जरूरी सामान की खरीदारी में शाम का समय बीतेगा।

मकर : मकर राशि के जातक सुबह से ही किसी नए प्रोग्राम को लेकर आपके अन्दर नई शक्ति और एनर्जी रहेगी। किसी लव अफेयर को लेकर भी आप काफी एक्साइटेड रहेंगे।

कुम्भ : कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्रवार का दिन लाभ दिलाने वाला रहेगा। आज दिन के पहले हिस्से में आपको छुटपुट धन का लाभ होने की संभावना है।

मीन : मीन राशि के जातक आज अपने में मस्त रहेंगे। किसी भी विरोधी की आलोचना की तरफ बिल्कुल ध्यान न लगाएं। सफलता एक दिन जरूर आपके कदम चूमेगी।

उभरते भारत के लिए बजट : विकसित भारत के विकास इंजन के रूप में कपड़ा उद्योग

गिरिराज सिंह

विकसित भारत बजट 2026-27 वैश्विक अनिश्चितता के दौर में आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और स्पष्ट सुधारोन्मुख दृष्टिकोण की ओर इंगित करता है। भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है तथा निकट भविष्य में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में मजबूती से अग्रसर है। 4.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, 7.2 प्रतिशत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर, 750 बिलियन डॉलर से अधिक का एफडीआई प्रवाह और 2014 में 1.9 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2026 में 12.21 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच चुके पूंजीगत व्यय के साथ यह बजट अवसंरचना-आधारित विकास को सुदृढ़ रूप से स्थापित करता है। यह व्यापक आर्थिक स्थिरता और भारत की विकास यात्रा के प्रति निरंतर वैश्विक विश्वास को रेखांकित करता है। मुख्य आंकड़ों से परे, यह बजट एक स्पष्ट रणनीतिक दिशा प्रस्तुत करता है, जो समावेशी विकास और श्रम-प्रधान विनिर्माण के माध्यम से व्यापक रोजगार सृजन पर केंद्रित है, जिसमें वस्त्र क्षेत्र इसका मूल केंद्र है। पारंपरिक मजबूती से रणनीतिक बढ़त तक: विकसित भारत के विकास इंजन के रूप में कपड़ा क्षेत्र माननीय प्रधानमंत्री के रणनीतिक नेतृत्व में, बीता वर्ष वस्त्र क्षेत्र के लिए एक निर्णायक मोड़ रहा है। 18 एफटीए के माध्यम से, भारत को अब 800 बिलियन डॉलर के वैश्विक आयात बाज़ार में से लगभग 466 बिलियन डॉलर मूल्य के कपड़े बाज़ारों तक विशेष पहुँच प्राप्त है, जिसे 110 बिलियन डॉलर के अमेरिकी बाज़ार तक नए सिरे से पहुँच मिलने से और विस्तार मिला है। हाल ही में घोषित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से निर्यात के पिछले वर्ष की तुलना में काफी बढ़ने की उम्मीद है।

बाज़ार तक पहुँच को सुदृढ़ करने के साथ-साथ, क्यूसीओ को हटाए जाने से अनुपालन संबंधी बोझ में कमी आई है, जबकि जीएसटी सुधारों ने लंबे समय से चली आ रही उलटी शुल्क संरचना की समस्या का समाधान किया है, जिससे यह क्षेत्र निर्णायक रूप से फाइबर-न्यूट्रल ढाँचे की ओर अग्रसर हुआ है। इन उपायों ने एक मजबूत आधार तैयार किया। बजट 2026 को महत्वपूर्ण बनाने वाली बात इसकी निरंतरता और व्यापकता है। कपास उत्पादकता मिशन जैसी पहलें और व्यापक आर्थिक सुधार अब पायलट चरण से आगे बढ़कर स्थायी मंचों में परिवर्तित किए जा रहे हैं, जो संरचनात्मक सुधारों के वास्तविक स्वरूप को दर्शाता है। दशकों तक वस्त्र क्षेत्र को मुख्यतः कल्याणकारी दृष्टिकोण से देखा जाता रहा। यह बजट वस्त्र क्षेत्र को अब विस्तार, प्रतिस्पर्धात्मकता और दीर्घकालिक राष्ट्रीय विकास के लिए एक मुख्य औद्योगिक रणनीति के रूप में पुनः स्थापित करते हुए उस सोच में एक निर्णायक परिवर्तन का संकेत देता है।

इस प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता पूरी तरह स्पष्ट है। भारत का वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र देश के जीडीपी में लगभग 2.3 प्रतिशत का योगदान देता है, औद्योगिक उत्पादन का लगभग 12 प्रतिशत हिस्सा है और 5.2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जिससे यह अर्थव्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ बन जाता है। हालाँकि वैश्विक वस्त्र एवं परिधान निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 4 प्रतिशत है, जो इस क्षेत्र में विस्तार की अपार संभावनाओं को रेखांकित करती है। सरकार ने इस दिशा में एक स्पष्ट और महत्वाकांक्षी मध्यम अवधि का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2030 तक वस्त्र क्षेत्र का आकार 350 बिलियन डॉलर तक पहुँचाना और निर्यात को 100 बिलियन डॉलर तक विस्तारित करना।

सुधार रणनीति का पहला स्तंभ मूल्य श्रृंखला का एकीकरण है, जिसका स्पष्ट उद्देश्य वर्ष 2030 तक वस्त्र क्षेत्र की अनुमानित 23 एमएमटी कच्चे माल की आवश्यकता को पूरा करना है-जिसमें प्राकृतिक तथा मानव-निर्मित, दोनों प्रकार के रेशे शामिल हैं। वर्तमान में रेशों की लागत में अस्थिरता कुल इनपुट अनिश्चितता का लगभग 25 से 30 प्रतिशत तक हिस्सा है, जो विशेष रूप से एमएसएमई इकाइयों के लिए मार्जिन, उत्पादन योजना और निर्यात मूल्य निर्धारण को सीधे प्रभावित करती है। बढ़ती जनसंख्या और कच्चे माल की बढ़ती मांग को देखते हुए, बजट 2026 राष्ट्रीय फाइबर योजना के माध्यम से इस चुनौती का समाधान करता है। ये पहलें कपास, मानव-निर्मित रेशे और उभरते हुए नए युग के रेशों के क्षेत्र में घरेलू उपलब्धता को सुदृढ़ करती हैं, जिससे रेशे से लेकर तैयार उत्पाद तक पूरी मूल्य श्रृंखला मजबूत होती है। कच्चे माल की आपूर्ति को स्थिर बनाकर, यह बजट मार्जिन की स्पष्टता को बेहतर बनाता है, योजना निर्माण में निश्चितता बढ़ाता है और निर्माताओं की निर्यात मूल्य निर्धारण क्षमता को सशक्त करता है, जिससे भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र का टिकाऊ रूप से विस्तार करना सुनिश्चित होता है ।

वस्त्र क्षेत्र की प्रगति को लंबे समय से बाधित करने वाला एक प्रमुख कारण पुराने उत्पादन क्लस्टरों पर इसकी निर्भरता रहा है, जो उत्पादकता और विस्तार को सीमित करता है। विनिर्माण संबंधी दक्षता बढ़ाने और लॉजिस्टिक्स लागतों को कम करने के लिए इकोसिस्टम का आधुनिकीकरण अनिवार्य है। बजट 2026 देशभर में 200 औद्योगिक क्लस्टरों के आधुनिकीकरण का प्रावधान करते हुए इस आवश्यकता का सीधे तौर पर समाधान करता है। साक्ष्य दर्शाते हैं कि क्लस्टर-आधारित विनिर्माण से श्रम उत्पादकता में 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है और प्रति इकाई लॉजिस्टिक्स लागत में 30 प्रतिशत तक की कमी लाई जा सकती है। मेगा टेक्सटाइल पार्कों, साझा प्रसंस्करण सुविधाओं तथा प्लग-एंड-प्ले इकोसिस्टम में किए गए निवेश बड़े पैमाने पर स्थायी लागत को कम करते हैं, जिससे छोटे उत्पादकों को विस्थापित किए बिना विस्तार संभव होता है-जो एक श्रम-प्रधान क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

वस्त्र क्षेत्र के रूपांतरण के केंद्र में रोज़गार सृजन और कार्यबल की तैयारी हैं। वस्त्र उद्योग, पूंजी-प्रधान उद्योगों की तुलना में प्रति करोड़ रुपये के निवेश पर लगभग तीन गुना अधिक रोजगार सृजित करता है, और क्रमिक पहलों के माध्यम से पूरी मूल्य श्रृंखला में कौशल विकास और रोजगार-योग्यता को सुदृढ़ करने पर निरंतर ध्यान दिया गया है। इस क्लस्टर-आधारित विकास के समर्थन से, वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना के तहत अगले पाँच वर्षों में 2 से 3 करोड़ अतिरिक्त आजीविकाओं को सहारा मिलने की संभावना है। इस गति को समर्थ 2.0 के माध्यम से और बल दिया गया है, जिसके अंतर्गत 2026 से 2031 के बीच 2,800 करोड़ रुपये का प्रावधान कर 15 लाख उद्योग-तैयार श्रमिकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। एनआईएफटी, आईआईटी, आईआईएचटी, आईटीआई और एसवीपीआईएसटीएम के साथ साझेदारी को और गहरा कर, हम कौशल विकास को वास्तविक उत्पादन, प्रौद्योगिकी और डिज़ाइन आवश्यकताओं के अनुरूप बनाएंगे, जिसका उद्देश्य 2030 तक महत्वपूर्ण कौशल अंतर को 50 प्रतिशत तक कम करना है।

इस रोज़गार और कौशल वृद्धि को सतत विकास में बदलने के लिए, वस्त्र मूल्य श्रृंखला में काम करने वाली सभी इकाइयों के पास विस्तार और प्रतिस्पर्धा करने की वित्तीय क्षमता होना आवश्यक है। वस्त्र इकोसिस्टम की रीढ़ एमएसएमई को पहचानना - बजट 2026 का मुख्य फोकस है, जो उनकी सबसे बड़ी रुकावट -तरलता को सीधे तौर पर दूर करता है। 10,000 करोड़ रुपये का एसएमई ग्रोथ फंड, मजबूत टीआरईडीएस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से विस्तारित चालान वित्तपोषण, और सरकारी भुगतान चक्रों में तेजी कार्यशील पूंजी पर दबाव को कम करते हैं, क्योंकि अकेला विलंबित भुगतान ही प्रति वर्ष लगभग 15 प्रतिशत एमएसएमई पूंजी को अवरुद्ध कर देते हैं।

महत्वपूर्ण रूप से, यह संरचनात्मक परिवर्तन केवल कारखानों तक सीमित नहीं है, बल्कि हथकरघा और हस्तशिल्प तक व्याप्त है, जो ग्रामीण और अर्ध-शहरी भारत में लगभग 65 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करते हुए, इसे महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल और ओडीओपी विजन के अनुरूप बनाया जाएगा, जिससे यह क्षेत्र जीविकोपार्जन सहायता से कौशल विकास, ब्रांडिंग और सतत वैश्विक बाजार पहुँच की दिशा में बढ़ेगा, तथा रोजगार वृद्धि समावेशी, भविष्य के लिए तैयार और राष्ट्रीय स्तर पर वितरित होगी। बजट 2026 में मूल्य श्रृंखला में पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार प्रथाओं का समावेश करते हुए और स्थिरता को भविष्य में निर्यात प्रतिस्पर्धा के प्रमुख चालक के रूप में स्वीकार करते हुए टेक्स ईको पहल के ज़रिए वस्त्र क्षेत्र में स्थिरता को एक डिज़ाइन सिद्धांत के रूप में भी शामिल किया गया है।

बजट के गणित से राष्ट्रीय दिशा तक – विकसित भारत का मार्ग

पहली बार, वस्त्र क्षेत्र को केवल एक पारंपरिक उद्योग के रूप में नहीं, बल्कि भविष्य के रोजगार और उद्यमिता इंजन के रूप में स्थापित किया जा रहा है। 2020 से 2030 के बीच लगभग 5 करोड़ नए रोजगार सृजित करने की क्षमता के साथ, यह क्षेत्र भारत की श्रम-प्रधान विकास रणनीति के केंद्र में है। विकसित भारत बजट नए दौर के वस्त्र स्टार्टअप्स और विस्तारित कंपनियों के लिए ठोस नींव तैयार करता है। रोजगार, कौशल और स्थिरता को केंद्र में रखकर, यह बजट समावेशी विकास के लिए स्पष्ट और डेटा-आधारित मार्गदर्शन प्रस्तुत करता है। यह बजट विकसित भारत 2047 और उससे आगे के स्वरूप को आकार देते हुए भारत को उत्पादक रोजगार और प्रतिस्पर्धात्मक उद्यमिता के क्षेत्र में सोने की चिड़िया के रूप में लौटने का आधार देता है। (लेखक केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं: व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं)

डीपफेक का धोखा और डिजिटल सख्त नियमों की अनिवार्यता

ललित गर्ग

डिजिटल युग में सूचना की गति जितनी तीव्र हुई है, उतनी ही तेजी से भ्रम, छल और दुष्प्रचार की संभावनाएँ भी बढ़ी हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डीपफेक तकनीक ने इस चुनौती को और जटिल बना दिया है। अब केवल शब्दों से नहीं, बल्कि चेहरों, आवाजों और भाव-भंगिमाओं से भी झूठ को सच की तरह प्रस्तुत किया जा सकता है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने डीपफेक और एआई जनित सामग्री के नियमन के लिए आईटी नियमों को सख्त करने का निर्णय लिया है। बीस फरवरी से लागू होने जा रहे नए प्रावधानों के अनुसार एआई द्वारा निर्मित सामग्री पर स्पष्ट लेबल लगाना अनिवार्य होगा और किसी भी अवैध या भ्रामक सामग्री को तीन घंटे के भीतर हटाना या ब्लॉक करना होगा। पहले यह समयसीमा 36 घंटे थी। यह बदलाव केवल तकनीकी संशोधन नहीं, बल्कि डिजिटल नैतिकता और लोकतांत्रिक जवाबदेही की दिशा में एक गंभीर हस्तक्षेप है।

पिछले कुछ वर्षों में डीपफेक तकनीक का दुरुपयोग भयावह रूप से सामने आया है। राजनीतिक नेताओं के फर्जी वीडियो, अभिनेत्रियों की अश्लील रूप से परिवर्तित तस्वीरें, सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाले ऑडियो क्लिप और आर्थिक धोखाधड़ी के लिए बनाए गए कृत्रिम संदेश-ये सब इस बात के प्रमाण हैं कि तकनीक तटस्थ नहीं रहती, उसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों संभव हैं। जब सत्य को जूता जा रहा हो और झूठ को परिष्कृत तकनीक के सहारे प्रमाणिकता का आवरण पहनाकर प्रस्तुत किया जा रहा हो, तब समाज में अविश्वास का वातावरण बनना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा नियंत्रण की पहल आवश्यक प्रतीत होती है, क्योंकि यह केवल अभिव्यक्ति का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक सौहार्द, राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की प्रतिष्ठा से जुड़ा विषय है।

नए नियमों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से बढ़ाई गई है। अब उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उपयोगकर्ता को यह जानकारी मिले कि साझा की जा रही सामग्री एआई से निर्मित है या नहीं। इससे पारदर्शिता का एक न्यूनतम मानक स्थापित होगा। साथ ही, तीन घंटे की समयसीमा यह संकेत देती है कि सरकार डिजिटल अपराधों की गंभीरता को समझ रही है। डीपफेक वीडियो के वायरल होने के बाद उसका खंडन अक्सर प्रभावहीन हो जाता है, इसलिए त्वरित कार्रवाई ही नुकसान को सीमित कर सकती है। परंतु यह भी सच है कि इतनी कम समय सीमा में सामग्री की सत्यता की जांच करना तकनीकी और प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत जटिल कार्य है। इससे प्लेटफॉर्मों पर निगरानी तंत्र को अत्यधिक सुदृढ़ करना पड़ेगा, जो लागत और संचालन दोनों के स्तर पर चुनौतीपूर्ण होगा।

यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि आपत्तिजनक या भ्रामक सामग्री की परिभाषा कौन और किस आधार पर तय करेगा। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मूलाधिकार है। यदि नियमन की प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायसंगत नहीं होगी, तो इसके दुरुपयोग की आशंकाएँ जन्म लेंगी। अतीत में भी यह देखा गया है कि जब-जब सोशल मीडिया पर नियंत्रण के प्रयास हुए, तब कुछ वर्गों ने इसे सरकारी अतिक्रमण के रूप में प्रस्तुत किया। इसलिए नियमन और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि नियमों का प्रयोग असहमति को दबाने के लिए नहीं, बल्कि स्पष्ट रूप से दुष्प्रचार और अपराध को रोकने के लिए हो। इस दिशा में स्वतंत्र निगरानी तंत्र, न्यायिक समीक्षा और पारदर्शी शिकायत निवारण प्रणाली अनिवार्य घटक हो सकते हैं।

वैश्विक परिदृश्य भी इसी संकट की ओर संकेत करता है। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देशों ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग की न्यूनतम आयु निर्धारित करने जैसे कदम उठाए हैं। अमेरिका में इंस्टाग्राम और यूट्यूब के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभावों की जांच के लिए ऐतिहासिक मुकदमे चल रहे हैं। वहाँ की बड़ी तकनीकी कंपनियों पर युवाओं को लत लगाने वाली संरचनाएँ विकसित करने के आरोप लगे हैं। विशेषज्ञों का मत है कि कई युवा जब अपने फोन से दूर किए जाते हैं तो वे मनोवैज्ञानिक ही नहीं, शारीरिक असहजता भी अनुभव करते हैं। यह स्थिति केवल विकसित देशों तक सीमित नहीं, भारत सहित विकासशील देशों में भी सोशल मीडिया का अनियंत्रित विस्तार सामाजिक और मानसिक संकट का कारण बन रहा है।

एआई उद्योग स्वयं भी एक नैतिक दुविधा के दौर से गुजर रहा है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में कंपनियाँ तकनीकी श्रेष्ठता की दौड़ में लगी हैं। इस दौड़ में सुरक्षा और नैतिकता के प्रश्न अक्सर पीछे छूट जाते हैं। हाल ही में एक प्रमुख कंपनी के सुरक्षा शोधकर्ता द्वारा विवादास्पद परियोजनाओं की अनियंत्रित गति पर असहमति जताते हुए त्यागपत्र देना इस तनाव का संकेत है। तकनीक की प्रगति जितनी तेज होगी, नियामक ढाँचे उतनी ही तेजी से अप्रासंगिक होते जाएँगे, यदि उन्हें समयानुकूल अद्यतन न किया जाए। इसलिए नियमन को केवल दंडात्मक नहीं, बल्कि दूरदर्शी और सहभागी होना चाहिए।

भारत के संदर्भ में यह विषय और भी संवेदनशील है। यहाँ डिजिटल क्रांति ने अभूतपूर्व विस्तार पाया है। करोड़ों नए उपयोगकर्ता प्रतिवर्ष ऑनलाइन आ रहे हैं। ऐसे में यदि असली और नकली के बीच का फर्क स्पष्ट न रहे तो लोकतांत्रिक विमर्श ही संदिग्ध हो जाएगा। चुनावी प्रक्रिया, सामाजिक सद्भाव, आर्थिक लेन-देन और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा-सभी पर डीपफेक का खतरा मंडरा सकता है। इसलिए एआई जनित सामग्री पर लेबलिंग का प्रावधान केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि सूचना साक्षरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। परंतु यह भी ध्यान रखना होगा कि लेबलिंग तभी प्रभावी होगी जब आम उपयोगकर्ता डिजिटल साक्षर हो। अन्यथा वह लेबल को समझे बिना ही सामग्री साझा करता रहेगा।

आगामी ई-समिट और भारत के 'इंडिया एआई मिशन' के संदर्भ में यह और भी प्रासंगिक हो जाता है कि तकनीक का विकास पारदर्शिता, शुद्धता और प्रमाणिकता के मूल्यों के साथ हो। यदि भारत वैश्विक एआई नेतृत्व का दावा करना चाहता है, तो उसे नैतिक मानकों की स्थापना में भी अग्रणी भूमिका निभानी होगी। केवल स्टार्टअप्स और नवाचार की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं, यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि एआई मानव गरिमा, गोपनीयता और लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करे। नियमन का उद्देश्य तकनीकी प्रगति को रोकना नहीं, बल्कि उसे उत्तरदायी बनाना होना चाहिए।

अंततः यह समझना होगा कि डीपफेक और एआई का संकट केवल तकनीकी नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक भी है। कानून आवश्यक है, परंतु पर्याप्त नहीं। डिजिटल कंपनियों की जवाबदेही, सरकार की पारदर्शिता, न्यायपालिका की सतर्कता और नागरिकों की जागरूकता-इन सबका समन्वय ही इस चुनौती का स्थायी समाधान दे सकता है। यदि नियमन संतुलित और निष्पक्ष होगा तो वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने के बजाय उसे सुरक्षित करेगा, क्योंकि स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब वह सत्य और जिम्मेदारी के साथ जुड़ी हो। झूठ को सच में बदलने की तकनीकी क्षमता जितनी बढ़ रही है, उतनी ही दृढ़ता से सत्य की रक्षा के लिए सामूहिक संकल्प भी आवश्यक है। यही डिजिटल युग की सबसे बड़ी नैतिक परीक्षा है, और यही लोकतांत्रिक समाज की अगली कसौटी भी।

-लेखक, पत्रकार, स्तंभकार

वर्ग पहेली नं. 3350

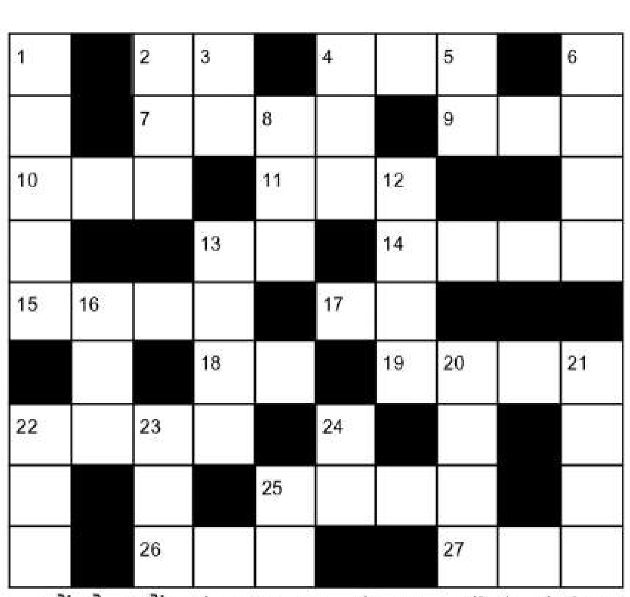

ऊपर से नीचे:- 1) काम की देखभाल करने-वाला, 2) चने का आटा, 3) मक्कायात्रा, 4) नेत्रांजन, 5) ख्यात, 6) बिनबुलाया, 8) सफ़ेद, 12) बुद्ध की पत्नी, 13) चमत्कार, 16) झोपड़ा, 20) समालोचक, 21) अद्वितीय, 22) जवानी, 23) धनवान और प्रतिष्ठित, 24) आतप; सूर्यप्रकाश, 25) सूर्य.
(उत्तर: अगले अंक में)

बायें से दायें:- 2) अच्छा; भला, 4) गुज़ारना *(दिन)*, 7) सिंगार, 9) बंद करना *(आँखें)*, 10) तनख़्वाह, 11) गोल घेरा, 13) बीता हुआ दिन, 14) प्रसिद्धि, 15) बड़ा पिंजड़ा, 17) धृतराष्ट्र की तरह *(महाभारत)*, 18) परिमाण, 19) कृष्ण और गोपियों की प्रेममयी लीलाएँ, 22) पाजीपन, 25) सामने, 26) सावधान, 27) पराकाष्ठा ; करतब.

पिछली पहेली का उत्तर

प	■	म	र	ज़ी	■	द	ल	द	ल
त्थ	■	घ	■	ना	म	र्द	■	म	ग्न
र	ख	वा	ला	■	द	ना	द	न	■
दि	■	■	चा	ल	■	क	ल	■	आ
ल	ल	का	र	■	बौ	■	ह	रा	म
■	गा	■	■	स	ना	त	न	■	र
च	म	क	दा	र	■	न्म	■	प्रा	ण
पा	■	श्री	■	स	म	य	सू	ची	■
ती	रं	दा	ज़	■	र्ज़	■	त	न	या

सुडोकू-पहेली-3308

		9				2		6
2	3	5	4					
7				8				
					2	1		
3	1						8	
			1	5		7		4
	5			4			1	
			9					
				6				3

प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरना आवश्यक है। इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है।

••••

आड़ी और खड़ी में एवं 3-3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका ध्यान जरूर रखें।

सूडोकू पहेली - 3307 का उत्तर

7	8	9	5	2	6	4	1	3
4	3	6	7	8	1	9	5	2
2	1	5	4	3	9	6	7	8
5	4	3	9	6	8	1	2	7
1	6	7	2	5	3	8	9	4
9	2	8	1	4	7	5	3	6
8	7	2	6	1	5	3	4	9
3	5	4	8	9	2	7	6	1
6	9	1	3	7	4	2	8	5

राष्ट्रव्यापी बंद का बंगाल में मिला-जुला असर

सड़कों पर आम दिनों की तरह रही आवाजाही, कुछ जगहों पर हुआ प्रदर्शन

कोलकाता, समाज्ञा : केंद्रीय श्रमिक संगठनों की गुरुवार को बुलाई गई देशव्यापी हड़ताल का पश्चिम बंगाल में मिला-जुला असर दिखा तथा कुछ बैंकों और औद्योगिक क्षेत्रों में कामकाज प्रभावित हुआ। इस दिन, 'बंगाल बचाओ' का नारा देने वाले सीआईटीयू, एआईटीयूसी और यूटीयूसी सहित अन्य श्रमिक संगठनों के सदस्यों ने दुर्गापुर और हल्दिया के औद्योगिक क्षेत्रों में कारखानों के बाहर प्रदर्शन किया। श्रमिक संगठन के नेताओं ने बताया कि हड़ताल के कारण राज्य के कई सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों में बैंकिंग परिचालन प्रभावित हुआ। हालांकि, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) में सामान्य कामकाज जारी रहा। बैंक इंप्लॉईज फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव देबाशीष बसु चौधरी ने दावा किया कि राज्य भर में बैंकिंग क्षेत्र में हड़ताल सफल रही। उन्होंने कहा कि अधिकतर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों में सेवाएं प्रभावित हुईं, हालांकि एसबीआई कर्मचारियों ने सीधे तौर पर इसमें भाग नहीं लिया। एसबीआई सूत्रों ने बताया कि राज्य भर में उसकी शाखाओं में कामकाज बिना किसी रुकावट के सामान्य रूप से जारी रहा। राज्य में हालांकि, सार्वजनिक परिवहन पर हड़ताल का असर नहीं दिखा। इस दिन, राज्य बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा का पहला दिन होने के मद्देनजर यह सुनिश्चित किया गया कि विद्यार्थियों को उनके परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए अलग-अलग मार्ग पर पर्याप्त संख्या में बसें उपलब्ध हों।

कलकत्ता उच्च न्यायालय की 150 साल पुरानी इमारत का पता बदला

कोलकाता, समाज्ञा : कोलकाता उच्च न्यायालय की 150 साल पुरानी इमारत का पता बृहस्पतिवार को बदल गया, जब नगर निगम ने उस सड़क का नाम बदल दिया, जिसपर इमारत स्थित है। सड़क का नाम अब एस्प्लेनेड रो (वेस्ट) से बदलकर जस्टिस राधाबिनोद पाल सरणी कर दिया गया है। अब देश के इस सबसे पुराने उच्च न्यायालय का नया पता 3, जस्टिस राधाबिनोद पाल सरणी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, पिन - 700001 होगा। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार नियो-गॉथिक शैली में बना यह भवन 1872 में स्थापित किया गया था। इसका डिजाइन उस समय के सरकारी आर्किटेक्ट वाल्टर ग्रानविल ने तैयार किया था। यह डिजाइन बेल्जियम के यप्रेस शहर में स्थित 13वीं सदी के क्लॉथ हॉल से प्रेरित था। न्यामूर्ति राधाबिनोद पाल (1886 - 1967) एक प्रमुख भारतीय न्यायविद थे। वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 'इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल फॉर फार ईस्ट' में 'तोक्यो ट्रायल्स' पर निर्णय में अकेले असहमति जताने के लिए प्रख्यात थे।

विधानसभा चुनाव कितने चरणों में होगा, यह बलों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा : निर्वाचन अधिकारी

कोलकाता, समाज्ञा : विधानसभा चुनाव के लिए चरणों की संख्या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की उपलब्धता के आधार पर तय की जाएगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को यह बात कही। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय एक ही चरण में चुनाव कराने के पक्ष में है और उसने यह प्रस्ताव निर्वाचन आयोग को भेज दिया है। अधिकारी ने बताया कि इस मामले पर अंतिम निर्णय लेने के लिए नयी दिल्ली स्थित निर्वाचन आयोग मुख्यालय में गहन विचार-विमर्श जारी है। अधिकारी ने कहा कि राज्य में मतदान के चरणों की संख्या इस बात पर निर्भर करेगी कि केंद्रीय बलों की कितनी कंपनियां उपलब्ध कराई जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के अधिकारी बलों की आवश्यकता और उपलब्धता का आकलन कर रहे हैं। बता दें कि वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में राज्य में केंद्रीय बलों की लगभग 1,100 कंपनियां तैनात की गई थीं। अधिकारी ने बताया कि आयोग ने राज्य प्रशासन को संवेदनशील मतदान केंद्रों और संवेदनशील क्षेत्रों की तत्काल पहचान करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों से संवेदनशील बूथों और क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कहा है। इससे संबंधित सूची के प्राप्त होने के बाद ही चरणों की संख्या पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि पूरी प्रक्रिया संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की संख्या पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है, लेकिन अशांति को रोकने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त कर्मियों की आवश्यकता है।

राज्यपाल ने निष्पक्ष ढंग से चुनाव संपन्न होने की उम्मीद जताई

कोलकाता, समाज्ञा : राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बृहस्पतिवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद एसआईआर अब एक 'बंद अध्याय' बन चुका है और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि निर्वाचन आयोग राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव निष्पक्ष रूप से कराएगा। बोस ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का अध्याय समाप्त हो चुका है। यदि इस प्रक्रिया के संचालन में कोई खामी पाई जाती है, तो निश्चित रूप से उसे संतुलित तरीके से दूर किया जायेगा। विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने उम्मीद व्यक्त की कि निर्वाचन आयोग अपनी जिम्मेदारी निष्पक्ष और सकारात्मक रूप से निभायेगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि बंगाल में चुनाव निष्पक्ष तरीके से संपन्न हों। राज्यपाल ने चुनावी प्रक्रिया और इसे संचालित करने के लिए जिम्मेदार संस्थानों में जनता के भरोसे को बनाये रखने के महत्व पर जोर दिया।

पुणे में बांग्ला भाषा बोलने के कारण प्रवासी मजदूर की हत्या की गयी : ममता

- **मुख्यमंत्री ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और न्याय की मांग की**

कोलकाता, समाज्ञा : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि बंगाल के 24 वर्षीय एक प्रवासी मजदूर की महाराष्ट्र में बांग्ला भाषा बोलने के कारण हत्या कर दी गई। ममता ने इसे 'घृणा अपराध' करार दिया और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। इस दिन, मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा कि मैं पुरुलिया में बंदवान के रहने वाले 24 वर्षीय प्रवासी मजदूर सुखेन महतो की महाराष्ट्र के पुणे में बर्बर हत्या से स्तब्ध, क्रोधित और बेहद दुखी हूं। वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। उन्होंने कहा कि यह घृणा अपराध से कम नहीं है। एक युवक को उसकी भाषा, उसकी पहचान, उसकी जड़ों के कारण निशाना बनाया गया, प्रताड़ित किया गया और उसकी हत्या कर दी गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उस माहौल का सीधा परिणाम है जिसमें बाहरी लोगों के प्रति नफरत को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जाता है। उन्होंने आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करके दंड दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सुखेन के परिवार से मैं कहना चाहती हूं कि इस असहनीय दुख की घड़ी में पश्चिम बंगाल आपके साथ है। न्याय दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

बेलडांगा हिंसा : पुलिस एस्कॉर्ट की कमी से दूसरी बार नहीं हो सकी आरोपियों की कोर्ट में पेशी

- **परीक्षाओं का हवाला देकर पुलिस ने नहीं मुहैया कराई सुरक्षा**
- **31 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 19 फरवरी तक बढ़ी**

कोलकाता, समाज्ञा : मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में हुई 'संगठित हिंसा' मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को गुरुवार को एक बार फिर प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पर्याप्त पुलिस एस्कार्ट न मिलने के कारण एजेंसी लगातार दूसरी बार 36 गिरफ्तार आरोपितों को कोलकाता के विचार भवन स्थित विशेष एनआईए अदालत में भौतिक रूप से पेश करने में विफल रही। हालांकि, अदालत ने एनआईए की अर्जी को स्वीकार करते हुए 31 आरोपितों की जेल हिरासत 19 फरवरी तक बढ़ा दी है। सूत्रों के अनुसार, एनआईए ने आरोपितों की पेशी के लिए मुर्शिदाबाद जिला पुलिस से सुरक्षा एस्कॉर्ट का औपचारिक अनुरोध किया था। लेकिन पुलिस प्रशासन ने उच्च माध्यमिक परीक्षा का हवाला देते हुए पर्याप्त बल उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई। पुलिस का तर्क था कि परीक्षाओं के कारण बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी ड्यूटी पर तैनात हैं। बता दें कि इससे पहले पांच फरवरी को भी सुरक्षा कारणों से ही आरोपितों को कोर्ट नहीं लाया जा सका था। नतीजतन, गुरुवार को 31 आरोपितों की उपस्थिति वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए दर्ज की गई, जबकि पांच अन्य आरोपित नाबालिग होने के कारण इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बने।

चुनाव से पहले मुश्किल में वाम मोर्चा, कांग्रेस ने छोड़ा साथ, दूसरे दलों ने भी बनाई दूरी

एआईएसएफ ने सीट बंटवारे के लिए रविवार तक की समय सीमा दी

- **वाममोर्चा के अन्य सहयोगी भी अधिक सीटों की मांग कर रहे**

कोलकाता, समाज्ञा : विधानसभा चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे को लेकर माकपा के नेतृत्व वाले वाममोर्चा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद अब ऑल इंडियन सेक्युलर फ्रंट (एआईएसएफ) भी वाममोर्चा का साथ छोड़ने की तैयारी में है। सीट बंटवारे में देरी से नाराज एआईएसएफ ने वाममोर्चा से स्पष्ट कहा है कि वह जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का प्रस्ताव बताएं। इसके लिए उन्होंने रविवार तक की समय सीमा (डेडलाइन) तय कर दी है। एआईएसएफ ने यह कदम राज्य में कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद उठाया है। यानी, कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया है कि वह इस बार के चुनाव में वाममोर्चा के साथ गठबंधन नहीं करेगी।

एआईएसएफ के सूत्रों ने कहा कि माकपा नेतृत्व को पहले ही साफ संदेश भेज दिया गया है कि वे रविवार तक अपनी तरफ से सीट शेयरिंग का प्रस्ताव बता दें, ऐसा न होने पर पार्टी अपनी पसंद की विधानसभा सीटों पर चरणवार अपने उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर देगा। पार्टी का स्पष्ट कहना है कि हम अनिश्चित समय तक इंतजार नहीं कर सकते।

दूसरी ओर, वाममोर्चा के अंदर भाकपा, फॉरवर्ड ब्लॉक और आरएसपी जैसे पुराने सहयोगी भी सीट शेयरिंग फार्मूले पर फैसले में देरी को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं। माकपा की केंद्रीय कमेटी के एक सदस्य ने भी माना कि सीट- शेयरिंग फार्मूले को लेकर उसके साथियों के बीच मतभेद हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि, इस बार कांग्रेस गठबंधन से बाहर है, इसलिए माकपा, आल इंडिया फारवर्ड ब्लाक और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) जैसे वाममोर्चा के दूसरे साथी भी 2021 के विधानसभा चुनाव की तुलना में अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं। एआईएसएफ ने भी अधिक सीटों की मांग की है, जिसको लेकर पेंच फंसा हुआ है। हालांकि माकपा केंद्रीय कमेटी के सदस्य ने कहा कि हमें भरोसा है कि आखिरकार वाममोर्चा के भीतर के दलों के साथ-साथ एआईएसएफ के साथ भी सीट-शेयरिंग का समझौता जल्द हो जाएगा।

राष्ट्रीय चुनाव आयोग की सीईओ कार्यालय के साथ आज होगी वर्चुअल बैठक

कोलकाता, समाज्ञा : राष्ट्रीय चुनाव आयोग शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) और जिला अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करेगा। आयोग सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में चुनाव तैयारियों की स्थिति, एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) के सुनवाई चरण की प्रगति और प्रमाणपत्र सत्यापन से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की जाएगी। बताया गया है कि शुक्रवार को वर्चुअल माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अधिकारी बैठक करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर चुनाव तैयारियों की स्थिति का आकलन करना है। साथ ही, एसआईआर प्रक्रिया समाप्त होने के बाद यदि चुनाव की घोषणा होती है तो जिला स्तर पर तैयारियों की स्थिति कैसी है, इसका भी मूल्यांकन किया जाएगा। आयोग सूत्रों के अनुसार, एसआईआर कार्य के तहत प्रमाणपत्र सत्यापन प्रक्रिया पर भी इस बैठक में विस्तार से चर्चा होने की संभावना है।

मुचीबाजार में लगी आग

कोलकाता, समाज्ञा : कोलकाता के उल्टाडांगा के मुचीबाजार इलाके में बृहस्पतिवार को कूड़ा स्थल में आग लग गई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि एक घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया और किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि भीड़भाड़ वाले इलाके में एक गोदाम के पास स्थित इस कूड़ा स्थल में शाम करीब पांच बजे आग लगी। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है।

आज केएमसी का पेश होगा बजट, नई परियोजनाओं और सुधारों के घोषणाओं की संभावना

कोलकाता, समाज्ञा : कोलकाता नगर निगम का बजट शुक्रवार यानी आज पेश किया जाएगा। शहर के मेयर फिरहाद हाकिम दोपहर 2:30 बजे बजट पेश करेंगे। बजट सत्र की चर्चा और समीक्षा 16 फरवरी और 17 फरवरी को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगी। राजनीतिक दृष्टि से यह बजट विशेष महत्व रखता है, क्योंकि 2026 का विधानसभा चुनाव पास है और अगर योजना अनुसार सब ठीक रहा तो दिसंबर के मध्य में कोलकाता नगर निगम का चुनाव होना है। इस कारण विशेषज्ञ इस बजट को नगर की राजनीति और प्रशासनिक रणनीति के लिहाज से अहम मान रहे हैं। नगर निगम सूत्रों के अनुसार, शहरवासियों का मन जीतने के लिए इस बजट में कुछ सरप्राइज घोषणाएं हो सकती हैं। इसमें बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने की योजना है ताकि शहर सेवाएं और अधिक प्रभावी और आकर्षक बन सकें। विशेष ध्यान बस्ती विकास, सड़क सुधार, जल निकासी प्रणाली, नए पेयजल प्रोजेक्ट, आधुनिक पार्किंग सुविधाएं, होर्डिंग और विज्ञापन प्रणाली का आधुनिकीकरण, तथा प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरणीय पहल पर दिया जा सकता है। इसके अलावा पूरे शहर में हरित क्षेत्र विस्तार, आधुनिक वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम और अन्य पर्यावरण-अनुकूल परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट आवंटित किए जाने की संभावना है। साथ ही, कठोर अपशिष्ट प्रबंधन, विभिन्न व्यावसायिक परियोजनाओं और शहर के सामुदायिक विकास योजनाओं पर भी फोकस किया जा सकता है।

पूर्व रेलवे

निविदा सूचना संख्या: ईएल/एचडब्ल्यूएच/25/21 (सूचना)/740, दिनांक 11.02.2026, मंडल रेल प्रबंधक, पूर्व रेलवे, हावड़ा मंडल, नई डीआरएम बिल्डिंग, चतुर्थ तल, रेल म्यूजियम के पास, हावड़ा-711101 द्वारा निम्नलिखित विद्युत कार्यों के लिए ओपन ई-टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं: **निविदा संख्या: ईएल-एचडब्ल्यूएच-25-21-3416, कार्य का नाम:** "हावड़ा मंडल के तहत नए ओएफसी रूम से पुराने एवं जीर्ण-शीर्ण ओएफसी कंटेनर का प्रतिस्थापन" के संबंध में विद्युत (सामान्य) कार्य (फेज-I)। **निविदा मूल्य:** रु. 37,96,095/-, **बोली सुरक्षा (जमा धन राशि):** रु. 75,900/-, **पूर्णता अवधि:** 180 दिन। **समापन तिथि एवं समय:** दिनांक 04.03.2026 को 15.00 बजे। यदि किसी कारणवश उपर्युक्त समापन तिथि को अवकाश/बंद/हड़ताल घोषित किया जाता है, तो ऑनलाइन निविदा जमा करने की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, क्योंकि आईआरईपीएस वेबसाइट पर समापन तिथि और समय के बाद कोई निविदा जमा नहीं की जा सकती। हालांकि, निविदाओं का ऑनलाइन उद्घाटन समापन तिथि के बाद किसी भी सुविधाजनक दिन किया जा सकता है। निविदा का पूर्ण विवरण वेबसाइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। निविदाकारों से अनुरोध है कि उपरोक्त वेबसाइट पर अपनी निविदा ऑनलाइन प्रस्तुत करें। HWH-612/2025-26

निविदा सूचना वेबसाइट: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है

हमें यहाँ देखें: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

पूर्व रेलवे

निविदा सूचना सं.: 222-एस/1/डब्ल्यू-II, दिनांक 10.02.2026, मंडल रेल प्रबंधक, पूर्व रेलवे, सियालदह, दूसरी मंजिल, कंट्रोल बिल्डिंग, डीआरएम बिल्डिंग, काइजर स्ट्रीट, कोलकाता-700014 द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिए निम्नलिखित ई-निविदा ऑनलाइन आमंत्रित की जाती है: **निविदा सं.: टीएन-182-25-26, कार्य का नाम:** मंडल अभियंता (मुख्यालय)/सियालदह के अधीन सहायक अभियंता/बालीगंज के कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ शाखा अभियंता (पी.वे)/चितपुर के अधीन रेल्स, फिटिंग्स, स्लीपर्स के आकस्मिक नवीनीकरण, टीटीआर, डीप स्क्रीनिंग, पैकिंग, एसकेवी वेल्डिंग, रेल पेंटिंग, कीचड़ निकासी, वाशिंग पिट लाइन की मरम्मत एवं अन्य सहायक कार्यों द्वारा कोलकाता यार्ड का उन्नयन। **निविदा मूल्य:** रु. 81,98,050.85, **बयाना राशि:** रु.1,64,000/-, **कार्य की समापन अवधि:** 12 (बारह) माह। **निविदा की अंतिम तिथि और समय:** दिनांक 10.03.2026 को 15.00 बजे। **निविदा के खुलने की तिथि और समय:** दिनांक 10.03.2026 को 15.30 बजे। निविदा कागजात एवं अन्य विवरण वेबसाइट: www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा के लिए बोली उपर्युक्त वेबसाइट पर ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से जमा की जाएगी। मैनुअल प्रस्ताव तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। भारतीय रेलवे मानक अनुबंध 2022 की सामान्य शर्तों के अनुसार, ई-निविदा प्रपत्र की लागत शून्य है। SDAH-390/2025-26

निविदा सूचना वेबसाइट: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है

हमें यहाँ देखें: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

मेट्रो रेलवे, कोलकाता

उप मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार अभियंता/सिग्नल, मेट्रो रेलवे, कोलकाता, भारत के राष्ट्रपति की ओर से और उनके लिए, खुली निविदा के लिए ई-निविदा आमंत्रित करता है, जो 05.03.2026 को दोपहर 3:00 बजे खुलेगी। इस निविदा के लिए मैन्युअल प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है और प्राप्त किसी भी मैन्युअल प्रस्ताव को अनदेखा कर दिया जाएगा। **कार्य का नाम:** मेट्रो रेलवे, कोलकाता की ब्लू लाइन के KKVS से KCWC खंड में, जिसमें KSCS और KMUK यार्ड शामिल हैं, सिग्नल, पॉइंट मशीन, केबल, लोकेशन बॉक्स और संबंधित कार्यों जैसे विभिन्न सिग्नलिंग गियर का पुनर्वास और पुनःस्थापन। **निविदा मूल्य:** ₹8185491.52। बयाना राशि: ₹163700। **पूर्णता अवधि:** 12 माह। निविदा वेबसाइट https://www.ireps.gov.in पर देखी जा सकती है। निविदाकर्ता/बोलीदाताओं के पास श्रेणी-III डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र होना चाहिए और वे IREPS पोर्टल पर पंजीकृत होने चाहिए। ई-टेंडरिंग में केवल पंजीकृत निविदाकर्ता/बोलीदाता ही भाग ले सकते हैं। ई-टेंडर में भाग लेने के समय सभी संबंधित दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है।

खुली निविदा सूचना संख्या: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/कार्य/10-2026

हमें फ़ॉलो करें: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

OFFICE OF THE
DASPUR-II PANCHAYAT SAMITY
SONAKHALI :: PASCHIM MEDINIPUR
RE-TENDER
NOTICE INVITING E– TENDER No. WBPMID/DASP2/EO/NIT-42(25-26)

For and on behalf of Panchayats and Rural Development Department, Govt. of West Bengal, Executive Officer, Daspur-II Panchayat Samity invites E-Tender for total 3(Three) Nos. similar works. Bid Submission End Date(online) **13/02/2026 12:00 Hrs**. Bid Opening Date (Technical) **16/02/2026 11:00 Hrs**. For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Daspur-II Panchayat Samity

दक्षिण पूर्व रेलवे-निविदा

भारत के राष्ट्रपति के लिए तथा उनकी ओर से मुख्य अभियंता (निर्माण)/II/गार्डनरीच, दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। नीचे उल्लिखित निविदाएं वेबसाइट www.ireps.gov.in पर अपलोड कर दी गई है। निविदा नियत तारीख को दोपहर 12.00 बजे बंद कर दी जाएगी। **क्रमांक एवं ई-निविदा सूचना सं., कार्य का संक्षिप्त विवरण, अनुमानित लागत, बोली सुरक्षा** क्रमशः निम्नलिखित है: **(1) 4598-जीआरसी-सीई-सी-II-28-2025, दिनांक 11.02.2026;** डेपुटी सीई/कॉन/आद्रा के अधीन चाण्डिल-बर्नपुर तृतीय लाइन परियोजना के संबंध में चाण्डिल एवं दामोदर में 04 अदद टाइप-III क्वार्टरों, 08 अदद टाइप-II क्वार्टरों, कैम्प कार्यालय, पुरुलिया में अधिकारी विश्राम गृह अकमोडेशन का निर्माण; रु. 20.81 करोड़; रु. 11,90,600। **(2) 4613-जीआरसी-सीई-सी-II-02-2026, दिनांक 11.02.2026;** दक्षिण पूर्व रेलवे के निर्माण संस्थान के डेपुटी सीई/कॉन/टाटानगर के अधिकार क्षेत्र के अधीन डंगोवापोसी-जरोली स्टेशन के बीच प्रस्तावित तृतीय एवं चौथी लाइन के निर्माण के संबंध में मुर्गा महादेव रोड, बांसपानी एवं जरोली के यार्ड रिमॉडलिंग कार्य तथा फॉर्मेशन का निर्माण, छोटे पुलों, फुट ओवर ब्रिज, प्लेटफॉर्म, ई1 बिल्डिंग, पहुंच सड़क, साइड ड्रेन, रिटेनिंग वॉल इत्यादि का विस्तार साथ में ट्रैक जोड़ना, बैलास्ट की आपूर्ति एवं फैलाना, अन्य विविध कार्यों का निष्पादन; रु. 85.82 करोड़; रु. 44,41,200। **(3) 4614-जीआरसी-सीई-सी-II-03-2026, दिनांक 11.02.2026;** दक्षिण पूर्व रेलवे के निर्माण संस्थान के डेपुटी सीई/कॉन/टाटानगर के अधिकार क्षेत्र के अधीन डंगोवापोसी-जरोली स्टेशन के बीच प्रस्तावित तृतीय एवं चौथी लाइन के निर्माण के संबंध में डंगोवापोसी, पदापहाड़, जामकुंडिया एवं देवझर के यार्ड रिमॉडलिंग कार्य तथा फॉर्मेशन का निर्माण, छोटे पुलों, फुट ओवर ब्रिज, प्लेटफॉर्म, ई1 बिल्डिंग, पहुंच सड़क, साइड ड्रेन इत्यादि का विस्तार साथ में ट्रैक जोड़ना, बैलास्ट की आपूर्ति एवं फैलाना, अन्य विविध कार्यों का निष्पादन; रु. 88.21 करोड़; रु. 45,60,700। **समापन अवधि:** प्रत्येक हेतु 24 महीने। **बंद होने की तारीख:** प्रत्येक हेतु 11.03.2026। निविदाओं के परिपूर्ण विवरण/ब्यौरा/विनिर्देश के लिए इच्छुक निविदादातागण वेबसाइट www.ireps.gov.in देख सकते हैं तथा अपनी बोलियां ऑनलाइन जमा करें। इन मदों के लिए कोई भी मैनुअल निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएगी। **वि.द्र:** प्रत्याशित बोलीदाताओं से अन्य सभी निविदाओं में भाग लेने हेतु नियमित रूप से www.ireps.gov.in देख सकते हैं। (PR-1180)

अंतर्गत न्यायलय,
श्रीमान सिविल जज, सीनियर डिवीज़न, प्रथम, समस्तीपुर।
बँटवारा वाद संख्या 177 / 2024.
गुलाम मोहम्मद नूर अहमद एवं अन्य .... वादीगण।
बनाम
समीना खातून एवं अन्य .... प्रतिवादीगण।

नोटिस बनाम

(1). समीना खातून जौजे गुलाम अब्दुल कादिर (2). गुलाम अब्दुल कादिर पे० स्व० अब्दुल राशिद दोनों साकिन ग्राम बिक्रमपुर बांदे, वार्ड नं० 7, थाना-कर्पूरीग्राम, जिला- समस्तीपुर। वर्तमान पता-। 207 पहाड़पुर रोड, पोस्ट वो थाना गार्डन रीच, जिला-कोलकाता, पश्चिम बंगाल, पिनकोड- 700024

................प्रतिवादी प्रथम एवं प्रतिवादी द्वितीय पक्ष

बजरिये आपलोगों को इस प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वाद के वादीगण ने आपलोगों के खिलाफ बंटवारा वाद दाखिल किया है जिसमें विद्वान् न्यायलय द्वारा आपलोगों को नजारत वो डाक रजिस्ट्री के माध्यम से सम्मन नोटिस भेजा गया परन्तु आप उपस्थित नहीं हो रहे हैं।अतः आपलोगों को इस प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि दिनांक 24-2-26 को 10.30 बजे दिन में आप स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर जो कुछ भी ऊज़ूर वो ऐतराज करना हो तो करें अन्यथा आपलोगों के खिलाफ एक पक्षीय सुनवाई कर ली जाएगी।

इसे ताकिद जानें।

आदेश से
सिविल जज
सीनियर डिवीज़न
प्रथम समस्तीपुर।
19-1-26

पूर्व रेलवे

ई-निविदा सूचना सं.: ईएलडी-300-डब्ल्यूसी-34-2025-26, दिनांक: 09.02.2026, वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता/कर्षण वितरण, सियालदह, पूर्व रेलवे, कंट्रोल बिल्डिंग, प्रथम तल, डीआरएम कार्यालय, काइजर स्ट्रीट, कोलकाता-700014 द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती है: **निविदा सं. ईएलडी-300-डब्ल्यूसी-34-2025-26, कार्य का नाम :** "सियालदह मंडल के तहत एसएई/टीआर-डी/नारकेलडांगा कोचिंग यार्ड के कार्यक्षेत्र में ब्रिज नं. 7, ब्रिज नं. 14सीसीआर, ब्रिज नं. 20, ब्रिज नं. 17 और ब्रिज नं. 1सीपी का रि-गर्डरिंग" के संबंध में 25 केवी ओएचई और संबंधित विद्युत कार्य। **निविदा मूल्य:** रु. 89,74,799.80, **बयाना राशि:** रु. 1,79,500/-, **निविदा कागजात का मूल्य:** शून्य। **समापन अवधि:** स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 12 (बारह) माह। **अंतिम तिथि:** 10.03.2026 को 15.00 बजे। निविदा सूचना एवं समय-समय पर जारी संशोधनी का विवरण वेबसाइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। SDAH-392/2025-26

निविदा सूचना वेबसाइट: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है

हमें यहाँ देखें: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

पूर्व रेलवे

निविदा सूचना सं. एसजी.निविदा/डीएसटीई/एसडीएएच/595, दिनांक 11.02.2026, वरिष्ठ डीएसटीई, पूर्व रेलवे, सियालदह, दूसरी मंजिल, कंट्रोल बिल्डिंग, डीआरएम बिल्डिंग, काइजर स्ट्रीट, सियालदह, कोलकाता-700014 द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती है: **ई-निविदा सं. : एसडीएसटीई/एसआईजी/टी/45/25-26/आरआरएसके। कार्य का नाम एवं इसका स्थान:** सियालदह मंडल के दक्षिण खंड पर सर्ज प्रोटेक्शन उपकरण सहित अर्थिंग सिस्टम का पुनरुद्धार। **निविदा मूल्य :** रु.2,28,65,308.23, **बयाना राशि/बोली प्रतिभूति जमा की जाएगी :** रु.2,64,300/-, **निविदा कागजात का मूल्य :** शून्य। **कार्य की समापन अवधि:** 09 माह। **निविदा जमा देने की प्रारंभिक तिथि:** 24.02.2026, **निविदा जमा देने की अंतिम तिथि:** 10.03.2026 को 14.00 बजे तक। **निविदा बोली के खोलने की तिथि:** 10.03.2026 को 14.30 बजे। **विवरण यहाँ से देखा जा सकता है:** www.ireps.gov.in **तकनीकी पात्रता मानदंड:** निविदाकार ने निविदा आमंत्रण से पूर्व महीने के अंतिम दिन को समाप्त, पिछले 07 (सात) वर्षों के दौरान, निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक कार्य का सफलतापूर्वक पूरा या पर्याप्त रूप से निष्पादन किया है: (i) तीन समरूप कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत निविदा के विज्ञापित मूल्य के 30% की समान राशि से कम न हो, या (ii) दो समरूप कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत निविदा के विज्ञापित मूल्य के 40% की समान राशि से कम न हो, या (iii) एक समरूप कार्य जिसकी लागत निविदा के विज्ञापित मूल्य के 60% की समान राशि से कम न हो। **वित्तीय पात्रता मानदंड:** निविदाकार का न्यूनतम औसत वार्षिक ठेकाजनित कारोबार V/N या 'V' होना चाहिए, जो भी कम हो, जहाँ V = निविदा का विज्ञापित मूल्य करोड़ रुपये में, N = कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित वर्षों की संख्या जिसके लिए बोलियाँ आमंत्रित की गई हैं। औसत वार्षिक ठेकाजनित कारोबार की गणना लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों में "कुल ठेकाजनित भुगतान" के औसत के रूप में की जाएगी। तथापि, यदि पिछले वर्ष का तुलन-पत्र अभी तैयार किया जाना है/लेखापरीक्षित नहीं है, तो औसत वार्षिक ठेकाजनित कारोबार की गणना के लिए चौथे पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र को विचार में लिया जाएगा। निविदाकार जीसीसी 2022 के अनेक्सर-VIबी (मौजूदा निविदा कागजात का फॉर्म-6) के अनुसार आवश्यक जानकारी के साथ सनदी लेखापाल द्वारा यथा प्रमाणित लेखापरीक्षित तुलन पत्र की प्रतियाँ/लेखापरीक्षित तुलन पत्र द्वारा यथा समर्थित सनदी लेखापाल से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। **जमा किए जाने वाले अन्य कागजात:** निविदा कागजात में उल्लिखित अनुसार। **समरूप कार्य की प्रकृति:** सिग्नल या टेलीकम का कोई भी कार्य जिसमें सिग्नल या टेलीकम केबलों की खुदाई, बिछाने और परीक्षण या कोई अन्य विविध आउटडोर एस एंड टी कार्य शामिल है। **टिप्पणी:** निविदाकार अपने निविदा प्रस्ताव के साथ निविदा कागजात में उल्लिखित पात्रता मानदंड को पूरा करने के अपने दावे के समर्थन में कागजात प्रस्तुत करेंगे। निविदाकार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्रों के समर्थन में कागजातों/प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपि का प्रत्येक पृष्ठ निविदाकार या निविदाकारी फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्व-सत्यापित/डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होगा। स्व-सत्यापन में हस्ताक्षर, मुहर और तिथि (प्रत्येक पृष्ठ पर) शामिल होंगे। SDAH-393/2025-26

निविदा सूचना वेबसाइट www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है

हमें यहाँ देखें: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

स्पेशल ट्रेनें

सियालदह एवं मधुबनी, हावड़ा एवं रक्सौल तथा कोलकाता एवं मधुबनी के बीच

आगामी **होली उत्सव** के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ से निपटने के लिए **सियालदह एवं मधुबनी, हावड़ा एवं रक्सौल, कोलकाता एवं मधुबनी** के बीच **स्पेशल ट्रेनें** निम्नलिखित संक्षिप्त समय-सारणी, ठहराव, यात्रा के दिन एवं गठन के अनुसार चलाई जाएंगी :-

03183/03184 सियालदह-मधुबनी-सियालदह स्पेशल ट्रेन

सियालदह-मधुबनी			(03183)(03184)	मधुबनी-सियालदह		
यात्रा के दिन	आगमन	प्रस्थान	स्टेशन	आगमन	प्रस्थान	यात्रा के दिन
शनिवार	-	23.50	↓ सियालदह	06.25	-	
	01.12	01.14	बैण्डेल	04.28	04.30	सोमवार
	03.38	03.41	आसनसोल	01.02	01.07	
रविवार	05.10	05.12	जसीडीह	23.08	23.10	
	11.25	11.30	समस्तीपुर	18.25	18.30	रविवार
	14.30	-	मधुबनी ↑	-	15.30	

उपरोक्त स्पेशल ट्रेनें यात्रा के दौरान दोनों दिशाओं में मार्ग में नैहाटी, बर्द्धमान, दुर्गापुर, चित्तरंजन, मधुपुर, झाझा, किऊल, बरौनी, दरभंगा एवं सकरी जंक्शन स्टेशनों में भी ठहरेंगी। **यात्रा की तारीख/दिन: सियालदह से - 03183** दिनांक 28.02.2026 एवं 07.03.2026 (शनिवार) = 02 ट्रिप तथा **मधुबनी से - 03184** दिनांक 01.03.2026 एवं 08.03.2026 (रविवार) = 02 ट्रिप। **गठन:** वातानुकूलित 3-टीयर-04, शयनयान श्रेणी - 10, साधारण द्वितीय श्रेणी (जीएस)-06 एवं एसएलआरडी - 02 = 22 कोच। **श्रेणी:** मेल/एक्सप्रेस।

03185/03186 कोलकाता-मधुबनी-कोलकाता स्पेशल ट्रेन

कोलकाता-मधुबनी			(03185)(03186)	मधुबनी-कोलकाता		
यात्रा के दिन	आगमन	प्रस्थान	स्टेशन	आगमन	प्रस्थान	यात्रा के दिन
शुक्रवार	-	23.50	↓ कोलकाता	06.25	-	
	01.12	01.14	बैण्डेल	04.28	04.30	रविवार
	03.38	03.41	आसनसोल	01.02	01.07	
शनिवार	05.10	05.12	जसीडीह	23.08	23.10	
	11.25	11.30	समस्तीपुर	18.25	18.30	शनिवार
	14.30	-	मधुबनी ↑	-	15.30	

उपरोक्त स्पेशल ट्रेनें यात्रा के दौरान दोनों दिशाओं में मार्ग में नैहाटी, बर्द्धमान, दुर्गापुर, चित्तरंजन, मधुपुर, झाझा, किऊल, बरौनी, दरभंगा एवं सकरी जंक्शन स्टेशनों में भी ठहरेंगी। **यात्रा की तारीख/दिन: कोलकाता से - 03185** दिनांक 27.02.2026 (शुक्रवार) = 01 ट्रिप तथा **मधुबनी से - 03186** दिनांक 28.02.2026 (शनिवार) = 01 ट्रिप। **गठन :** वातानुकूलित 3-टीयर-03, शयनयान श्रेणी - 05, वातानुकूलित कुर्सी यान-01, कुर्सी यान-07, साधारण द्वितीय श्रेणी (एलएस)-04, एलएसएलआरडी - 01 एवं पावर कार-01 = 22 कोच। **श्रेणी:** मेल/एक्सप्रेस।

03043/03044 एवं 03045/03046 हावड़ा-रक्सौल-हावड़ा स्पेशल ट्रेन

हावड़ा-रक्सौल			(03043)(03044) (03045)(03046)	रक्सौल-हावड़ा		
यात्रा के दिन	आगमन	प्रस्थान	स्टेशन	आगमन	प्रस्थान	यात्रा के दिन
शनि, रवि, सोम	-	23.05	↓ हावड़ा	10.50	-	
	23.53	23.55	बैण्डेल	09.42	09.44	सोम, मंगल, बुध
	03.00	03.05	आसनसोल	05.45	05.50	
रवि, सोम, मंगल	04.58	05.00	जसीडीह	03.36	03.38	
	11.20	11.25	समस्तीपुर	22.10	22.15	रवि, सोम, मंगल
	16.15	-	रक्सौल ↑	-	17.45	

उपरोक्त स्पेशल ट्रेनें यात्रा के दौरान दोनों दिशाओं में मार्ग में बर्द्धमान, दुर्गापुर, चित्तरंजन, मधुपुर, झाझा, किऊल, बरौनी, दलसिंह सराय, दरभंगा, कमतौल, जनकपुर रोड, सीतामढ़ी एवं बैरगनिया स्टेशनों में भी ठहरेंगी। **यात्रा की तारीख/दिन: हावड़ा से - 03043** दिनांक 28.02.2026, 07.03.2026 एवं 14.03.2026 (**शनिवार**) = 03 ट्रिप एवं **03045** दिनांक 01.03.2026 (**रविवार**) एवं 02.03.2026 (**सोमवार**) = 02 ट्रिप। **रक्सौल से - 03044** दिनांक 01.03.2026, 08.03.2026 एवं 15.03.2026 (**रविवार**) = 03 ट्रिप एवं **03046** दिनांक 02.03.2026 (**सोमवार**) एवं 03.03.2026 (**मंगलवार**) = 02 ट्रिप। **गठन: 03043/03044 के लिए** - वातानुकूलित 2-टीयर-01, वातानुकूलित 3-टीयर-02, शयनयान श्रेणी - 09, साधारण द्वितीय श्रेणी (एलएस)-04, एलएसएलआरडी - 01 एवं पावर कार-01 = 18 कोच तथा **03045/03046 के लिए** - वातानुकूलित 3-टीयर-04, शयनयान श्रेणी - 10, साधारण द्वितीय श्रेणी (जीएस)-06, एसएलआरडी - 02 = 22 कोच। **श्रेणी:** मेल/एक्सप्रेस।

03187/03188 कोलकाता-मधुबनी-कोलकाता स्पेशल ट्रेन

कोलकाता-मधुबनी			(03187)(03188)	मधुबनी-कोलकाता		
यात्रा के दिन	आगमन	प्रस्थान	स्टेशन	आगमन	प्रस्थान	यात्रा के दिन
मंगलवार	-	23.50	↓ कोलकाता	06.25	-	
	01.12	01.14	बैण्डेल	04.28	04.30	गुरुवार
	03.38	03.41	आसनसोल	01.02	01.07	
बुधवार	05.10	05.12	जसीडीह	23.08	23.10	
	11.25	11.30	समस्तीपुर	18.25	18.30	बुधवार
	14.30	-	मधुबनी ↑	-	15.30	

उपरोक्त स्पेशल ट्रेनें यात्रा के दौरान दोनों दिशाओं में मार्ग में नैहाटी, बर्द्धमान, दुर्गापुर, चित्तरंजन, मधुपुर, झाझा, किऊल, बरौनी, दरभंगा एवं सकरी जंक्शन स्टेशनों में भी ठहरेंगी। **यात्रा की तारीख/दिन: कोलकाता से - 03187** दिनांक 03.03.2026 (मंगलवार) = 01 ट्रिप तथा **मधुबनी से - 03188** दिनांक 04.03.2026 (बुधवार) = 01 ट्रिप। **गठन :** वातानुकूलित 3-टीयर-04, शयनयान श्रेणी - 10, साधारण द्वितीय श्रेणी (जीएस)-06 एवं एसएलआरडी - 02 = 22 कोच। **श्रेणी:** मेल/एक्सप्रेस।

मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक

पूर्व रेलवे

हमें अनुसरण करें : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

राज्य सरकार केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन में जानबूझकर रुकावट डाल रही : सामिक भट्टाचार्य

नई दिल्ली/कोलकाता : भाजपा सांसद सामिक भट्टाचार्य ने गुरुवार को राज्यसभा में पश्चिम बंगाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार केंद्रीय सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में जानबूझकर रुकावट डाल रही है। इस कारण जनता आवश्यक लाभों से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग केंद्रीय बजट की आलोचना कर रहे हैं, उन्हें पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति पर भी नजर डालनी चाहिए। उन्होंने भूमि अधिग्रहण और रेलवे लाइनों से जुड़ी समस्याओं का भी उल्लेख किया। बजट पर चर्चा के दौरान सामिक भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य से पूंजी, छात्रों, श्रमिकों और प्रतिभा का पलायन क्यों हो रहा है। यह बजट विकासोन्मुखी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसान खुश हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के किसान असंतुष्ट हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे राज्य से आता हूं जो वृद्धाश्रम बनता जा रहा है। पश्चिम बंगाल से पूंजी, छात्र, श्रमिक और प्रतिभा का पलायन हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि इस समय देशव्यापी समावेशी विकास हासिल करना है तो मजबूत संघीय ढांचे की आवश्यकता है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए।

तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने बजट को खास आदमी का बजट बताया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत में हर 10 में से 5 लोगों के पास पर्याप्त इंटरनेट सुविधा नहीं है। ऐसे में न्यूनतम डिजिटल पहुंच के बावजूद मनरेगा श्रमिकों से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने, ऐप का उपयोग करने, बैंक खातों के माध्यम से भुगतान लेने और ई-केवाईसी कराने की अपेक्षा की जा रही है। उन्होंने लोगों से भाषण में 'मिडिल क्लास' शब्द खोजने को कहा और दावा किया कि 5 में से 4 भारतीय प्रतिदिन 117 रुपये से कम कमाते हैं, जबकि घरेलू बचत पिछले 50 वर्षों के निचले स्तर पर पहुंच गई है। दूसरा शब्द, उन्होंने 'बेरोजगारी' खोजने को कहा। उन्होंने कहा कि हर 3 में से 1 युवा शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण में नहीं है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री चर्चा का जवाब देंगी, लेकिन असली जवाब दो महीने बाद तमिलनाडु और केरल से तथा फरवरी 2027 में उत्तर प्रदेश से मिलेगा।

उच्च माध्यमिक : परीक्षा से पूर्व परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों को गुलाब का फूल देकर हौंसला अफजाई करते पुलिस अधिकारी

स्वास्थ्य साथी योजना में अब निजी अस्पतालों में भी होंगे ये चार ऑपरेशन, जारी हुई नई गाइडलाइन

कोलकाता, समाज्ञा : स्वास्थ्य साथी योजना के तहत अब निजी अस्पतालों में भी हर्निया, हाइड्रोसील, फिशरेक्टॉमी और आर्थोस्कोपिक सर्जरी कराई जा सकेगी। इस संबंध में राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने नई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। योजना लागू होने के बाद अब तक इन चार प्रकार के ऑपरेशनों की सुविधा निजी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं थी। स्वास्थ्य विभाग का तर्क था कि सरकारी अस्पतालों में इन सर्जरियों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा मौजूद है। हालांकि, अब स्वास्थ्यसाथी कार्ड का उपयोग कर निजी अस्पतालों में भी ये चारों ऑपरेशन कराए जा सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, यदि किसी सरकारी अस्पताल में हर्निया, हाइड्रोसील या फिशरेक्टॉमी सर्जरी कराने में समस्या हो और संबंधित चिकित्सक इसकी लिखित अनुशंसा करें, तभी मरीज को निजी अस्पताल में ऑपरेशन की अनुमति मिलेगी। वहीं, किसी दुर्घटना में घायल मरीज को आर्थोस्कोपिक सर्जरी की आवश्यकता होने पर ही इसे स्वास्थ्यसाथी योजना के तहत निजी अस्पताल में कराया जा सकेगा। लेकिन 'कोल्ड ओटी' यानी ऐसी सर्जरी जिसे बाद में भी किया जा सकता है, उसके लिए निजी अस्पताल में आर्थोस्कोपी की अनुमति नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गेटकीपिंग व्यवस्था में कुछ ढील दी गई है। नई गाइडलाइन के अनुसार, निजी अस्पतालों में केवल वहां के स्थायी सर्जन ही ये ऑपरेशन कर सकेंगे, जबकि उस अस्पताल से जुड़े किसी सरकारी डॉक्टर को इसकी अनुमति नहीं होगी।

संसद में उठे सवाल, रेल मंत्री ने पश्चिम बंगाल के अमृत भारत स्टेशन योजना पर दी जानकारी

कोलकाता, समाज्ञा : संसद में सांसद कीर्ति आजाद ने पश्चिम बंगाल में अमृत भारत स्टेशन योजना की प्रगति के संबंध में सवाल पूछा। इस पर रेल मंत्री ने जानकारी दी कि वर्तमान बजट आवंटन पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया है, जबकि 2009–2014 की यूपीए सरकार के दौरान यह मात्र 4,300 करोड़ रुपये था। रेल मंत्री ने बताया कि परियोजनाओं में देरी का मुख्य कारण भूमि अधिग्रहण है। आवश्यक 4,662 हेक्टेयर भूमि में से केवल 57% भूमि का अधिग्रहण हो पाया है। कुछ परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण अभी तक शून्य है। उन्होंने सांसद से अनुरोध किया कि वे मुख्यमंत्री से इन परियोजनाओं को सुगम बनाने के लिए सहयोग करने का आग्रह करें। इसी बीच, भाजपा सांसद प्रताप सारंगी (बालासोर, ओडिशा) ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बालेश्वर स्टेशन के पुनर्विकास कार्य की स्थिति के बारे में प्रश्न किया। रेल मंत्री ने बताया कि बालेश्वर स्टेशन का विकास परामर्शात्मक डिजाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें सांसदों के सुझाव और जनता की भागीदारी शामिल है। उन्होंने कहा कि कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है और योजना के अंतर्गत क्षेत्र के अन्य स्टेशनों पर भी कार्य जारी है।

गृहिणी का स्नान का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग का आरोप, जांच में जुटी पुलिस

पूर्व बर्दवान : जिले के पूर्वस्थली के नादनघाट थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक विवाहिता के नहाते समय की तस्वीरें और वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर दस लाख रुपये की मांग किए जाने का आरोप लगा है। घटना के बाद पीड़िता और उसका परिवार सदमे में है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, पीड़िता पूर्वस्थली-(एक) ब्लॉक के श्रीरामपुर इलाके की रहने वाली है। उसके पति टोटो चालक हैं। बुधवार को किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके घर के सामने एक मोबाइल फोन और एक चिट्ठी फेंक दी। घर की सफाई के दौरान जब महिला ने वह मोबाइल देखा और प्लास्टिक हटाकर खोला, तो वह स्तब्ध रह गई। चिट्ठी में लिखा था कि दीदी, मोबाइल में तुम्हारी तस्वीरें हैं, देख लो। इसके बाद, जब महिला ने मोबाइल की फोटो गैलरी खोली, तो उसमें उसके नहाते समय की कई तस्वीरें और वीडियो मौजूद थे। महिला का आरोप है कि इन्हीं तस्वीरों और वीडियो के आधार पर उससे दस लाख रुपये की मांग की गई है और पैसे न देने पर उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी गई है। पीड़िता का यह भी दावा है कि धमकी देने वालों ने खुद को महिला बताया है। चिट्ठी में लिखा गया है कि हम महिलाएं हैं। गुप्त रूप से वीडियो बनाकर बेचते हैं। तुम्हारी तस्वीरें बेचने से पहले तुम्हें बता दिया। दस लाख रुपये दोगी तो नहीं बेचेंगे। साथ ही, किसी को इस बारे में बताने पर गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई है। इस घटना के बाद गृहवधू ने अपने पति को पूरी बात बताई। इसके बाद शाम को दंपती ने नादनघाट थाने में शिकायत दर्ज कराई और वह मोबाइल फोन व धमकी भरी चिट्ठी पुलिस को सौंप दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है कि तस्वीरें कैसे ली गईं और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं।

कांकसा में नर्स की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत

आसनसोल : कांकसा थाना अंतर्गत गोपालपुर में एक युवा नर्स की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत को लेकर बुधवार की रात भारी तनाव फैल गया। मृत नर्स का नाम मंदिरा पाल (24) है। वह मोलानदिघि स्थित एक निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कार्यरत थीं। स्थानीय लोगों ने बुधवार की रात एक बहुमंजिला आवासीय भवन के नीचे मंदिरा पाल का शव पड़ा हुआ देखा। यह खबर फैलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही कांकसा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, मंदिरा पाल का घर बांकुड़ा जिले के विष्णुपुर के लोहारपाड़ा इलाके में है, लेकिन नौकरी के सिलसिले में वह मोलानदिघि में रहकर काम कर रही थीं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह मामला आत्महत्या का है या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर दुर्गापुर महकमा अस्पताल भेज दिया है, जहां पोस्टमार्टम किया जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा होने की उम्मीद है। वहीं, मामले की कड़ियां जोड़ने के लिए मृत नर्स के परिजनों और सहकर्मियों से भी पूछताछ की जा सकती है।

सुरटेक में नया एआईसीटीई आइडिया लैब का शुभारंभ, स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास को नई दिशा

कोलकाता, समाज्ञा : जेआईएस ग्रुप की शैक्षणिक पहल के तहत कोलकाता स्थित डॉ. सुधीर चंद्र सुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स (सुरटेक) परिसर में एक नए एआईसीटीई आईडिया लैब का उद्घाटन जेआईएस ग्रुप के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर सरदार हरनजीत सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर सुरटेक के प्रिंसिपल प्रो. (डॉ.) सरदिंदु पांडा; जेआईएस यूनिवर्सिटी के प्रो-चांसलर प्रो. नीरज सक्सेना; वाइस-चांसलर प्रो. भास्कर गुप्ता; साथ ही वरिष्ठ शिक्षाविद्, संकाय सदस्य और उद्योग प्रतिनिधि उपस्थित थे। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे राष्ट्रीय अभियानों के अनुरूप, यह लैब छात्रों को अनुभवात्मक और बहु-विषयक शिक्षण के माध्यम से अपने विचारों को प्रोटोटाइप और स्केलेबल समाधानों में बदलने में सक्षम बनाती है। इस सुविधा में उन्नत निर्माण और विकास अवसंरचना शामिल है, जैसे लेजर कटिंग लैब, थ्रीडी प्रिंटिंग लैब, आईओटी एवं रोबोटिक्स लैब, और पीसीबी डिजाइन लैब। इस अवसर पर जेआईएस ग्रुप के डायरेक्टर सरदार सिमरप्रीत सिंह ने कहा, सुरटेक में एआईसीटीई आईडिया लैब का उद्घाटन एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां नवाचार को केवल प्रोत्साहित ही नहीं, बल्कि व्यवस्थित रूप से विकसित किया जाता है।

अजीमगंज और नशीपुर अब होंगे एकजुट, नए पैसेंजर हॉल्ट को मिली मंजूरी

कोलकाता, समाज्ञा : रेलवे बोर्ड ने मुर्शिदाबाद जिले में नशीपुर के लिए नए पैसेंजर हॉल्ट स्टेशन की स्वीकृति प्रदान की है। यह कदम अजीमगंज और नशीपुर के बीच लंबे समय से चली आ रही आवागमन संबंधी समस्याओं को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भागीरथी नदी के कारण एक ही जिले के ये दोनों क्षेत्र अब तक व्यवहारिक रूप से अलग-थलग रहे हैं, जिससे स्थानीय निवासियों को दैनिक यात्रा में काफी परेशानी उठानी पड़ती थी।

नए हॉल्ट के निर्माण से हावड़ा और सियालदह रेल डिवीजनों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। अब तक हावड़ा डिवीजन के यात्रियों को नशीपुर या मुर्शिदाबाद पहुंचने के लिए लंबा मार्ग अपनाना पड़ता था, जिसमें अतिरिक्त समय और संसाधन लगते थे। प्रस्तावित स्टेशन चालू होने के बाद नशीपुर क्षेत्र सीधे हावड़ा रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा, जिससे यात्रा सुगम और समय की बचत होगी।

कृष्णानगर-लालगोला रेल खंड पर स्थित यह नया हॉल्ट भागीरथी नदी पार करने की मौजूदा जल परिवहन निर्भरता को भी कम करेगा। इस परियोजना से कृषि क्षेत्र को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। भागीरथी के दोनों तट उपजाऊ कृषि क्षेत्र हैं, जहां उत्पादित फसलों को बाजार तक पहुंचाने में अब तक परिवहन संबंधी बाधाएं थीं। रेल सुविधा मिलने से किसानों को दोनों ओर के बाजारों तक शीघ्र पहुंच मिलेगी और लागत में कमी आएगी। इसके अलावा, अजीमगंज क्षेत्र के लोगों के लिए मुर्शिदाबाद और बहरमपुर स्थित प्रमुख चिकित्सा संस्थानों तक पहुंचना आसान होगा, जिससे आ-पातकालीन स्थितियों में समय की बचत हो सकेगी। मुर्शिदाबाद और जियागंज के बीच प्रस्तावित यह हॉल्ट नशीपुर ब्रिज से गुजरने वाली ट्रेनों के यात्रियों को भी सुविधा देगा। स्थानीय यात्रियों को अब लंबी दूरी तय कर अन्य बड़े स्टेशनों तक जाने की आवश्यकता कम होगी। रेलवे बोर्ड की यह मंजूरी क्षेत्रीय संपर्क सुधारने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

वैलेंटाइन्स डे धमाका: क्रोमा में आईफोन 17, डायसन एयररैप और मार्शल स्पीकर्स पर तगड़ी छूट

कोलकाता, समाज्ञा : टाटा समूह से जुड़ी भारत की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल चेन क्रोमा ने वैलेंटाइन्स डे के मौके पर विशेष सेल की घोषणा की है, जिसमें 699 से शुरू होने वाले गिफ्टिंग विकल्प उपलब्ध हैं। यह ऑफर 15 फरवरी तक देशभर के सभी क्रोमा स्टोर्स पर मान्य है। सेल में स्मार्टफोन, टैबलेट, ऑडियो डिवाइस, वियरेबल्स और पर्सनल केयर उत्पादों पर विशेष कीमतें, कैटेगरी डिस्काउंट, बंडल डील्स और बैंक ऑफर्स शामिल हैं। प्रमुख ऑफर्स में आईफोन 17 पर एक्सचेंज और बैंक ऑफर्स के साथ प्रभावी कीमत, मार्शल ब्लूटूथ स्पीकर पर बड़ी छूट और चुनिंदा सोनी हेडफोन्स पर लगभग आधी कीमत शामिल है। रेडमी और वन प्लस स्मार्टफोन्स के साथ ऐपल आईपैड पर भी आकर्षक रियायत दी जा रही है। वियरेबल्स और ग्रूमिंग उत्पादों पर भी भारी छूट उपलब्ध है, जबकि एचडीएफसी टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड से अतिरिक्त बचत का लाभ मिल सकता है। सभी ऑफर्स स्टॉक और शर्तों के अधीन हैं।

एमएसएमई के लिए एक्सिस बैंक की नई गोल्ड लोन सुविधा, उसी दिन मिलेगा ऋण

कोलकाता, समाज्ञा : निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंक एक्सिस बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए उच्च लोन-टू-वैल्यू (एलटीवी) और उसी दिन वितरण वाली गोल्ड लोन सुविधा शुरू की है। यह सुरक्षित ओवरड्राफ्ट योजना छोटे कारोबारियों को स्वर्ण आभूषणों के बदले त्वरित और न्यूनतम दस्तावेज़ी प्रक्रिया के साथ ऋण उपलब्ध कराएगी। यह सुविधा देशभर की 3,300 से अधिक गोल्ड-लोन सक्षम शाखाओं में उपलब्ध है। योजना के तहत पात्र ग्राहक 50,000 से 1 करोड़ तक का ऋण काउंटर पर ही प्राप्त कर सकेंगे, जिसकी राशि सीधे उनके खाते में जमा होगी। बैंक 82% तक एलटीवी की पेशकश कर रहा है। उधारकर्ताओं को केवल मासिक ब्याज का भुगतान करना होगा। एक्सिस बैंक के ग्रुप एग्जीक्यूटिव बिपिन सराफ ने कहा कि यह पहल एमएसएमई को त्वरित कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने और सुरक्षित ऋण समाधान प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

कोलकाता में शुरू होगा इंडिका फेस्टिवल- 2026

कोलकाता, समाज्ञा : कोलकाता में इंडिका फेस्टिवल 2026 का आयोजन होने जा रहा है। इस दो दिवसीय उत्सव का उद्देश्य भारतीय सभ्यता की ज्ञान परंपरा, संस्कृति और मानवीय मूल्यों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना है। इस फेस्टिवल का आयोजन इंडस बैंड फाउंडेशन की पहल पर और भक्तिवेदांत रिसर्च सेंटर के सहयोग से किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम 21 और 22 फरवरी को कोलकाता के पार्क स्ट्रीट स्थित एलन पार्क में आयोजित होगा। कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ गुरुवार को कोलकाता प्रेस क्लब में किया गया। लॉन्च कार्यक्रम के दौरान मानवता सम्मान ग्लोबल 2026 और ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद अवॉर्ड से पद्मश्री से सम्मानित संतूर वादक पंडित तरुण भट्टाचार्य को नवाजा गया।

अमेजन प्राइम ने 2025 में भारत में ग्राहकों के लिए बचत के साथ सबसे तेज़ डिलीवरी दी

कोलकाता, समाज्ञा : अमेजन ने गुरुवार को घोषणा की कि 2025 प्राइम सदस्यों के लिए अब तक का सबसे तेज़ डिलीवरी वाला साल रहा। इस दौरान 55 करोड़ से अधिक प्रोडक्ट्स की डिलीवरी उसी दिन या अगले दिन की गई, जो साल-दर-साल आधार पर 40% की बढ़ोतरी है। भारत में प्राइम सदस्यों ने 2025 में औसतन अपनी सालाना प्राइम मेंबरशिप की कीमत से दो गुना से अधिक की बचत की, जिससे यह साफ होता है कि प्राइम देशभर के ग्राहकों को कितना ज्यादा फायदा देता है।

समाजसेवी सुशील चौधरी को मातृ शोक

कोलकाता, समाज्ञा : कोलकाता की अनेकों सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थाओं से संलग्न सक्रिय समाजसेवी, अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के प्रांतीय अध्यक्ष सुशील कुमार चौधरी की माताजी श्रीमती द्रौपदी देवी चौधरी का स्वर्गवास गुरुवार को रायसिंहनगर (राजस्थान) में हो गया। नब्बे वर्षीया श्रीमती चौधरी ने प्रातः साढ़े दस बजे अंतिम सांस ली। वे अपने पीछे पुत्र, पुत्रवधु, पौत्र-पौत्री, प्रपौत्र सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गई हैं। कुछ अर्सा पहले ही दिवंगत हुए महानगर के विशिष्ट समाजसेवी भानीराम सुरेका की सबसे बड़ी बहन के तौर पर श्रीमती द्रौपदी चौधरी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की एक कर्त्तव्यपरायण महिला थीं।

पूर्व रेलवे चलाएगा 6 होली स्पेशल ट्रेनें, 20 हजार से अधिक अतिरिक्त बर्थ उपलब्ध

कोलकाता, समाज्ञा : पूर्व रेलवे ने होली के अवसर पर यात्रियों की भारी भीड़ को संभालने के लिए विशेष तैयारी की है। त्योहार के दौरान घर लौटने और यात्रा करने वाले लोगों की सुविधा के लिए नियमित ट्रेनों के अतिरिक्त छह होली स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन विशेष ट्रेनों के जरिए यात्रियों के लिए 20,400 अतिरिक्त बर्थ और 1200 से अधिक सीटों की व्यवस्था की गई है। ये विशेष ट्रेनें हावड़ा-रक्सौल, सियालदह-मधुबनी, कोलकाता-मधुबनी और हावड़ा-खाटीपुरा मार्गों पर चलाई जाएंगी।

इसके तहत, हावड़ा-रक्सौल स्पेशल (03043/03044), ट्रेन संख्या 03043 हावड़ा से 28 फरवरी, 7 मार्च और 14 मार्च 2026 को रात 23:05 बजे रवाना होकर अगले दिन 16:15 बजे रक्सौल पहुंचेगी। वापसी में 03044 रक्सौल से 1 मार्च, 8 मार्च और 15 मार्च 2026 को 17:45 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 10:50 बजे हावड़ा पहुंचेगी। हावड़ा-रक्सौल स्पेशल (03045/03046), 03045 हावड़ा से 1 और 2 मार्च को 23.05 बजे चलेगी जो अलगे दिन 16.45 बजे रक्सौल पहुंचेगी और 03046 रक्सौल से 2 और 3 मार्च को 17.45 बजे चलेगी जो अगले दिन 10.50 बजे हावड़ा पहुंचेगी। सियालदह-मधुबनी स्पेशल (03183/03184), ट्रेन संख्या 03183 सियालदह से 28 फरवरी और 7 मार्च 2026 को 23:50 बजे रवाना होकर अगले दिन 14:30 बजे मधुबनी पहुंचेगी। वापसी ट्रेन 03184 मधुबनी से 1 मार्च और 8 मार्च 2026 को मधुबनी से 15.30 बजे चलेगी जो अगले दिन 06.25 बजे सियालदह पहुंचेगी।

कोलकाता-मधुबनी स्पेशल (03185/03186), 03185 27 फरवरी को रात 23:50 बजे कोलकाता से चलेगी और अगले दिन 14:30 बजे मधुबनी पहुंचेगी। वहीं, 03186 स्पेशल 28 फरवरी को 15:30 बजे मधुबनी से रवाना होगी और अगले दिन 06:25 बजे कोलकाता पहुंचेगी। 03187 कोलकाता-मधुबनी होली स्पेशल 3 मार्च 2026 को रात 23:50 बजे कोलकाता से चलेगी और अगले दिन 14:30 बजे मधुबनी पहुंचेगी। 03188 मधुबनी-कोलकाता होली स्पेशल 4 मार्च को 15:30 बजे मधुबनी से चलेगी और अगले दिन 06:25 बजे कोलकाता पहुंचेगी। 03007 हावड़ा-खाटीपुरा होली स्पेशल 25 फरवरी और 11 मार्च को रात 23:55 बजे हावड़ा से रवाना होगी और तीसरे दिन 11:30 बजे खाटीपुरा पहुंचेगी। वापसी में 03008 खाटीपुरा-हावड़ा होली स्पेशल 27 फरवरी और 13 मार्च को 17:00 बजे खाटीपुरा से रवाना होगी और तीसरे दिन 05:15 बजे हावड़ा पहुंचेगी।

यात्रियों के लिए अपडेट, कटवा-वर्दवान लोकल 15 फरवरी से नए समयानुसार चलेगी

कोलकाता, समाज्ञा : हावड़ा मंडल के अंतर्गत कटवा-वर्दवान खंड पर चलने वाली 35018 कटवा-वर्दवान ईएमयू लोकल तथा 35023 वर्दवान-कटवा ईएमयू लोकल के समय में 15 फरवरी से संशोधन किया गया है। 35018 कटवा-वर्दवान ईएमयू लोकल अब कटवा से 16:00 बजे के बजाय 15:55 बजे प्रस्थान करेगी और 17:15 बजे के स्थान पर 17:10 बजे वर्दवान पहुंचेगी। संशोधित समयानुसार यह ट्रेन श्रीपत श्रीखंडा (16:04/16:05), श्रीखंडा (16:06/16:07), बांकापासी (16:11/16:12), कैचर (16:16/16:17), निगान (16:21/16:22), साओता (16:24/16:25), बलगोना (16:30/16:31), भातार (16:37/16:38), अमरून (16:42/16:43), कर्जानाग्राम (16:45/16:46), कर्जाना (16:47/16:48), चमारदिघी (16:49/16:50), खेतिया (16:52/16:53) और कामनारा (16:55/16:56) स्टेशनों पर रुकेगी।

इसी प्रकार, 35023 वर्दवान-कटवा ईएमयू लोकल अब वर्दवान से 16:00 बजे के बजाय 15:55 बजे प्रस्थान करेगी और 17:20 बजे के स्थान पर 17:15 बजे कटवा पहुंचेगी। संशोधित समयानुसार यह ट्रेन कामनारा (16:00/16:01), खेतिया (16:03/16:04), चामारदिघी (16:06/16:07), कर्जाना (16:08/16:09), कर्जानाग्राम (16:10/16:11), अमरून (16:13/16:14), भातार (16:18/16:19), बलगोना (16:27/16:32), साओता (16:36/16:37), निगन (16:39/16:40), कैचर (16:44/16:45), बांकापासी (16:49/16:50), श्रीखंडा (16:54/16:55) और श्रीपत श्रीखंडा (16:56/16:57) स्टेशनों पर ठहरेगी।

पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक मिलिंद देउस्कर ने तीनों डिवीजन का किया व्यापक निरीक्षण

कोलकाता, समाज्ञा : पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक मिलिंद देउस्कर ने गुरुवार को हावड़ा, आसनसोल और मालदह डिवीजन में व्यापक उच्चस्तरीय निरीक्षण किया। इस दौरे की शुरुआत रामपुरहाट से दुमका तक हुई, जिसमें उन्होंने स्टेशनवार निरीक्षण करते हुए चल रही अवसंरचना परियोजनाओं, परिचालन सुरक्षा और अमृत भारत स्टेशन योजना की प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण में विभिन्न विभागों के प्रमुख, डिविजनल रेलवे मैनेजर और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। दुमका स्टेशन पर महाप्रबंधक ने रनिंग रूम और क्रू बुकिंग लॉबी का निरीक्षण किया और क्रू के साथ संवाद किया। उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा में लोकोपायलट और गार्ड्स की भूमिका पर जोर देते हुए उच्चतम स्वच्छता और आराम सुविधाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। देवघर स्टेशन और जसीडीह बायपास का दौरा करते हुए महाप्रबंधक ने बायपास की डबलिंग कार्य को तेज करने के निर्देश दिए, जिससे ट्रैफिक की भीड़ और विलंब कम हो सके। बांका स्टेशन पर उन्होंने अमृत भारत योजना के तहत चल रहे पुनर्विकास कार्य का निरीक्षण किया और स्टाफ को निर्माण के दौरान माल और यात्री संचालन में किसी भी तरह की देरी से बचने के लिए समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। भागलपुर स्टेशन में यार्ड पुनर्विन्यास, क्रू लॉबी और रनिंग रूम का निरीक्षण करते हुए उन्होंने भविष्य में बढ़ती ट्रेन आवृत्ति के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने पर जोर दिया। गोड्डा स्टेशन पर कोचिंग डिपो और स्टेशन के आधुनिकीकरण का निरीक्षण किया गया। इस दौरान हंसडीहा स्टेशन और मालदह डिवीजन के साझा हॉल्ट स्टेशन का भी निरीक्षण किया गया। महाप्रबंधक ने यात्रियों की प्रतीक्षा क्षेत्रों और स्टेशन के बाहरी सौंदर्य सुधार को विश्वस्तरीय बनाए रखने के निर्देश दिए।

रेलवे बोर्ड ने डानकुनी-सूरत समर्पित मालवाहक कॉरिडोर के त्वरित क्रियान्वयन के निर्देश दिए

कोलकाता, समाज्ञा : भारतीय रेलवे ने केंद्रीय बजट 2026 में घोषित डानकुनी-सूरत डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माल-वाहक कॉरिडोर को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। लगभग 2,100 किमी लंबा प्रस्तावित कॉरिडोर डानकुनी से सूरत तक जाएगा और पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरेगा। इससे पूर्वी और पश्चिमी भारत के बीच माल परिवहन तेज, अधिक कुशल और समय की बचत वाला होगा, साथ ही मौजूदा रेल मार्गों पर भीड़भाड़ कम होगी। डीएफसीसीआईएल अधिकारियों को नवीनतम माल-लॉजिस्टिक्स तकनीकों के अनुरूप उच्च स्तरीय तकनीकी मानक तय करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रस्तावित विशेषताओं में उच्च क्षमता वाली विद्युतीकरण प्रणाली, शून्य लेवल क्रॉसिंग और 'कवच' जैसी उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली शामिल हैं। कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अद्यतन लागत और समयसीमा के साथ संशोधित किया जाएगा। परियोजना को विभिन्न खंडों में विभाजित कर समानांतर कार्य शुरू किए जाएंगे और प्रत्येक खंड के लिए समर्पित टीम तैनात होगी। रेलवे बोर्ड ने निर्माण-पूर्व सभी गतिविधियों को तेज करने और अनुबंध दस्ता-वेजों की तैयारी साथ-साथ शुरू करने के निर्देश दिए हैं। परियोजना की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा भी की जाएगी।

आईपीईएमए-पोल्ट्री इंडिया की नोवाकॉन 2026 और 12वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पोल्ट्री मेले में सक्रिय भागीदारी

कोलकाता, समाज्ञा : आईपीईएमए-पोल्ट्री इंडिया ने 10 से 13 फरवरी, 2026 तक आयोजित 12वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पोल्ट्री मेले (केआईपीएफ) 2026 के साथ-साथ आयोजित नोवाकॉन 2026 - 'पोल्ट्री में नवाचार' सम्मेलन में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। आईपीईएमए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अध्यक्ष उदय सिंह बायस ने किया, जिन्होंने विशेष रूप से पूर्वी भारत में उद्योग सहयोग को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता दोहराई। 10 फरवरी को आयोजित नोवाकॉन 2026 में अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने जैव सुरक्षा, स्थिरता, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और भविष्य उन्मुख विकास रणनीतियों पर विचार साझा किए। मेले का उद्घाटन पश्चिम बंगाल सरकार के पशु संसाधन विकास मंत्री सपन देबनाथ ने किया। आयोजन पश्चिम बंगाल पोल्ट्री फेडरेशन (डब्ल्यूबीपीएफ) ने राज्य सरकार के पशु संसाधन विकास विभाग के सहयोग से किया। आईपीईएमए ने एक विशेष पवेलियन स्थापित किया। स्टॉल का उद्घाटन मदन मोहन मैती, समीर अग्रवाल, रणपाल डंडा, डॉ. जितेंद्र वर्मा, वसंत कुमार शेट्टी, संतोष इरे और संजीव गुप्ता की उपस्थिति में हुआ। कुल 12 सदस्य कंपनियों ने अपनी उन्नत तकनीकों का प्रदर्शन किया। उदय सिंह बायस ने सभी गणमान्य व्यक्तियों का आभार व्यक्त करते हुए 25-27 नवंबर, 2026 को हैदराबाद के एचआईटीईएक्स में आयोजित पोल्ट्री इंडिया एक्सपो 2026 में भाग लेने का आमंत्रण दिया।

एसआईआर : कोलकाता में चार विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी से अधिक तार्किक विसंगतियों के मामले

कोलकाता, समाज्ञा : हाल में प्रकाशित एक अध्ययन ने कोलकाता की मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में एक चौंकाने वाली विसंगति की ओर इशारा किया है, जिसमें दावा किया गया है कि मौजूदा एसआईआर के दौरान चार विधानसभा सीटों पर तार्किक विसंगति (एलडी) संबंधी सूचियों में मुसलमानों की संख्या आनुपातिक रूप से अधिक पाई गई है। बालीगंज, कोलकाता पोर्ट, मटियाब्रुज और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर में एलडी सूचियों के अध्ययन से पता चलता है कि इस श्रेणी के तहत चिह्नित मुस्लिम-पहचान योग्य नामों का प्रतिशत इन निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या में उनके अनुमानित हिस्से से कहीं अधिक है। यह शोध कोलकाता स्थित साबर इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया है, जो सामाजिक असमानताओं को दूर करने पर काम करता है। ये निष्कर्ष मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की कवायद की पृष्ठभूमि में आए हैं, जिसके परिणामस्वरूप राज्य भर में अनुपस्थित, स्थायी रूप से स्थानांतरित, मृत और नाम के दोहराव (एएसडीडी) श्रेणी के तहत 58.2 लाख से अधिक नाम पहले ही बाहर कर दिए गए हैं, जिससे राज्य के मतदाताओं की संख्या 7.66 करोड़ से घटकर 7.08 करोड़ हो गई है। एसआईआर का दूसरा चरण वर्तमान में जारी है और इसमें जांच के दायरे में आए 1.67 करोड़ मतदाताओं की सुनवाई शामिल है, जिनमें एलडी के लिए चिह्नित 1.36 करोड़ मतदाता और लगभग 31 लाख ऐसे मतदाता शामिल हैं जिनके सत्यापन रिकॉर्ड में कमी है।

शोधकर्ता आशिन चक्रवर्ती ने कहा कि संस्थान ने सबसे पहले 16 दिसंबर की एएसडीडी की नाम हटाने वाली सूची का विश्लेषण किया, जिसमें लगभग 58 लाख नाम शामिल थे। यह इस आरोप के बीच हुआ है कि मुस्लिम मतदाताओं को असंगत रूप से मतदाता सूची से बाहर किया जा रहा था। चक्रवर्ती ने वरिष्ठ शोधकर्ता साबिर अहमद के साथ मिलकर यह अध्ययन किया। चक्रवर्ती ने बताया कि दिसंबर में जारी की गई हटाए गए नाम की सूची में मुस्लिम नामों का अनुपात उन निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी के लगभग बराबर था। उस समय हमें मुस्लिमों के अत्याधिक नाम हटाने का कोई सबूत नहीं मिला। 'असत्यापित मतदाताओं' की सूची में भी इसी तरह का पैटर्न देखने को मिला, जहां मुस्लिम प्रतिनिधित्व काफी हद तक जनसांख्यिकीय अनुपात के अनुरूप था।

भवानीपुर में मुस्लिम आबादी लगभग 20 प्रतिशत है। अध्ययन के अनुसार, एएसडीडी और असत्यापित मतदाता सूचियों में उनकी हिस्सेदारी क्रमशः लगभग 23 प्रतिशत और 26 फीसदी थी, जबकि एलडी सूची में मुस्लिम की हिस्सेदारी लगभग 52 प्रतिशत है। बालीगंज में, जहां अनुमानित तौर पर 50 प्रतिशत मतदाता मुस्लिम हैं, एएसडीडी और असत्यापित मतदाता सूचियों में उनकी हिस्सेदारी क्रमशः 42 प्रतिशत और 44 प्रतिशत रही। हालांकि, एलडी की सूची में यह हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 77.5 प्रतिशत हो जाती है। कोलकाता पोर्ट और मटियाब्रुज, दोनों मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में यह पैटर्न स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अध्ययन के अनुसार, कोलकाता पोर्ट में मतदाताओं का लगभग 50 प्रतिशत मुस्लिम हैं, लेकिन एलडी के अंतर्गत पंजीकृत मतदाताओं में से 82 प्रतिशत मुस्लिम हैं। मटियाब्रुज में, जहां मुसलमानों की आबादी लगभग 60 प्रतिशत है, एलडी सूची में उनकी हिस्सेदारी 87 फीसदी तक बताई जाती है। तार्किक विसंगतियों में माता-पिता के नाम में कथित विसंगतियां या मतदाता और माता-पिता के बीच उम्र का असामान्य अंतर शामिल है।

विधानसभा चुनाव बाद हिंसा मामले में पांच साल से फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार

कोलकाता, समाज्ञा : विधानसभा चुनाव 2021 के बाद राज्य में हुई राजनीतिक हिंसा मामले में सीबीआई ने 5 साल से फरार चल रहे आरोपी नजीर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी गुरुवार को उत्तर 24 परगना जिले में उसके ससुर के घर से हुई है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 मई 2021 को आये थे। इसके बाद, राज्य के कई हिस्सों में हिंसा भड़क गयी। हत्या, दुष्कर्म और दुष्कर्म की कोशिश जैसे गंभीर मामले दर्ज हुए। इन्हीं मामलों में एक केस में नजीर हुसैन की गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया है कि नजीर हुसैन ने अन्य लोगों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची। 2 मई 2021 की सुबह हसनुर जमां को घेरकर उनकी हत्या कर दी गयी। बताया गया है कि राजनीतिक दुश्मनी और मस्जिद की जमीन पर क्लब हाउस बनाने को लेकर विवाद इस हत्या की वजह बना। यह मामला उन केसों में एक है, जिनकी जांच कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी गयी थी। इस केस में नजीर हुसैन समेत कुल 12 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र यानी चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। मामला फिलहाल बारासात कोर्ट में चल रहा है। गिरफ्तारी के बाद नजीर हुसैन को बारासात अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

केंद्र ने बंगाल समेत पांच राज्यों को ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 3,324 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की

कोलकाता, समाज्ञा : केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई)/ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 15वें वित्त आयोग के अप्रतिबंधित अनुदान की दूसरी किस्त स्वीकृत एवं जारी की है ताकि जमीनी स्तर पर शासन को और ज्यादा सशक्त एवं आवश्यकता आधारित स्थानीय विकास को सक्षम बनाया जा सके। इस किश्त के अंतर्गत, बिहार को 80,240.00 लाख रुपये (802.40 करोड़ रुपये) प्राप्त हुए हैं, जिससे सभी 38 जिला पंचायतों (डीपी), 533 ब्लॉक पंचायतों (बीपी) और 8,053 ग्राम पंचायतों (जीपी) को लाभ हुआ है, साथ ही 3 ब्लॉक पंचायतों और 7 ग्राम पंचायतों के लिए पहली किश्त के रोके गए हिस्से से 139.10 लाख रुपये (1.39 करोड़ रुपये) की अतिरिक्त राशि जारी की गई है, जो अब इसका पात्र बन चुकी हैं। इसी प्रकार, हरियाणा में पात्र 19 डीपी, 138 बीपी और 6,194 जीपी को कवर करते हुए 19,762.70 लाख रुपये (197.627 करोड़ रुपये) जारी किए गए हैं, साथ ही पहले रोकी गई राशि से अतिरिक्त पात्र 1 डीपी, 4 बीपी और 30 जीपी को 249.80 लाख रुपये (2.50 करोड़ रुपये) जारी किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए, सभी 12 जिला पंचायतों, पात्र 80 ब्लॉक पंचायतों और 3,602 ग्राम पंचायतों के लिए 6,830.03 लाख रुपये (68.30 करोड़ रुपये) जारी किए गए, साथ ही 26 अतरिक्त पात्र ग्राम पंचायतों को 34.53 लाख रुपये (0.35 करोड़ रुपये) भी जारी किए गए। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिला पंचायतों, 826 ब्लॉक पंचायतों और 57,694 ग्राम पंचायतों के लिए 1,55,940.00 लाख रुपये (1,559.40 करोड़ रुपये) जारी किए गए, इसके अलावा, रोके गए हिस्से से 2 डीपी, 13 बीपी और 61 जीपी को 1,101.64 लाख रुपये (11.016 करोड़ रुपये) भी जारी किए गए, जो पात्रता प्राप्त कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल को इसी किस्त के अंतर्गत पात्र 21 डीपी, 335 बीपी और 3,225 ग्राम पंचायतों के लिए 68,085.79 लाख रुपये (680.86 करोड़ रुपये) जारी किए गए हैं।

गोघाट में 'लापता' विधायक के पोस्टर, टॉर्च लेकर तलाश का अनोखा प्रदर्शन

हुगली, समाज्ञा : विधानसभा चुनाव से पहले गोघाट के भाजपा विधायक विश्वनाथ कारक के पिछले पांच वर्षों से 'लापता' होने के आरोप लगाते हुए इलाके में अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने विधायक लापता हैं लिखे पोस्टर लेकर दिन के उजाले में हाथ में टॉर्च थामकर उनकी प्रतीकात्मक तलाश की। इतना ही नहीं, गोघाट थाने में विधायक के नाम से एक 'मिसिंग डायरी' भी दर्ज कराई गई। यह विरोध प्रदर्शन गोघाट के बकुलतला से शुरू होकर जुलूस के रूप में गोघाट थाने तक पहुंचा। हालांकि यह कार्यक्रम किसी पार्टी के आधिकारिक बैनर तले नहीं था, लेकिन जुलूस का नेतृत्व तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय वरिष्ठ नेताओं ने किया। तृणमूल का आरोप है कि आम लोगों ने विश्वनाथ कारक को वोट देकर विधायक चुना, लेकिन चुनाव जीतने के बाद से वे क्षेत्र में नजर नहीं आए और लोगों को न्यूनतम सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। इसी के विरोध में यह अनोखा प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले लंबे समय तक वाम मोर्चा से जुड़े रहे विश्वनाथ कारक ने फॉरवर्ड ब्लॉक छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। गोघाट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ते हुए उन्होंने तृणमूल के मानस मजूमदार को हराया था। वहीं, भाजपा विधायक विश्वनाथ कारक का कहना है कि तृणमूल चुनाव से पहले घबराकर इस तरह के 'राजनीतिक नाटक' कर रही है। आगामी चुनाव से पहले इस मुद्दे को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक तनातनी तेज हो गई है।

प्रशासनिक समीक्षा में जवाबदेही और विकास योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर दिया गया जोर

हुगली, समाज्ञा : हुगली के सर्किट हाउस में जिला मजिस्ट्रेट खुर्शीद अली कादरी की अध्यक्षता में एक व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सभी उप-मंडलाधिकारी तथा हुगली जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित वरिष्ठ जिला अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में राज्य सरकार की प्रमुख विकास योजनाओं जैसे 'आमादेर पाड़ा, आमादेर समाधान', 'पथश्री', 'बांग्लार बाड़ी', विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं तथा मुख्यमंत्री के सीएमआरओ पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों एवं शिकायत निवारण की स्थिति की प्रगति और प्रभावी क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही, विभिन्न विकास संकेतकों के आधार पर जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन किया गया तथा जिन क्षेत्रों में तेजी लाने की आवश्यकता है, उनकी पहचान की गई। जिला मजिस्ट्रेट ने सभी चल रही परियोजनाओं और योजनाओं को समय पर पूरा करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सरकारी दिशा-निर्देशों के पालन और प्रक्रियात्मक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को निर्बाध क्रियान्वयन, सतत निगरानी और सक्रिय समस्या -समाधान की व्यवस्था अपनाने को कहा गया, ताकि किसी भी प्रकार की देरी से बचा जा सके। बैठक में विकास मानकों पर कड़ी नजर बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने पर बल दिया गया कि योजनाओं का लाभ बिना किसी प्रशासनिक बाधा के आम लोगों तक पहुंचे।

राष्ट्रगान से पहले 'वंदे मातरम्' गाने के केंद्र के निर्देश पर बंगाल में सियासी घमासान शुरू

कोलकाता, समाज्ञा : आधिकारिक समारोह में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के सभी छह छंद को राष्ट्रगान जन गण मन से पहले गाए जाने के केंद्र के निर्देश के बाद राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले तीखी राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। तृणमूल कांग्रेस ने इस आदेश को रवींद्रनाथ टैगोर को 'कमतर दिखाने' और चुनावी लाभ के लिए प्रतीकवाद बढ़ाने का प्रयास बताया, वहीं कांग्रेस ने इसे 'विभाजनकारी हथकंडा' करार दिया। भाजपा का कहना है कि यह केवल ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के गीत को पूरा सम्मान वापस दिलाने का प्रयास है।

तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने कहा कि पार्टी को बंकिमचंद्र के योगदान को उजागर करने में 'कोई आपत्ति नहीं' है, लेकिन आरोप लगाया कि यह कदम टैगोर को 'कमतर' दिखाने का प्रयास है। बसु ने कहा कि इस बात पर जोर देकर कि वंदे मातरम् को जन गण मन से पहले गाया जाना चाहिए, वे एक श्रेणी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में रवींद्रनाथ का अपमान किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि 'कुछ सांप्रदायिक ताकतें' ऐतिहासिक रूप से टैगोर के समावेशी और धर्मनिरपेक्ष विश्वदृष्टिकोण से असहज हैं। वहीं, राज्य की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए याद दिलाया कि उन्होंने एक बार संसद में बंकिमचंद्र को 'बंकिम-दा' कहा था। उन्होंने कहा कि क्या यह उस घाव पर मरहम लगाने का प्रयास है? बसु ने आदेश के समय को आगामी विधानसभा चुनावों से भी जोड़ा और दावा किया कि ममता बनर्जी के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद निर्देश को भुला दिया जाएगा।

कांग्रेस ने भी इस आरोप को दोहराया और कहा कि इस कदम का उद्देश्य चुनाव से पहले राजनीतिक लाभ हासिल करना है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इसे विभाजन की रणनीति करार दिया। हालांकि, भाजपा ने आलोचना को राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस पर सांप्रदायिक तुष्टीकरण के दबाव में वंदे मातरम् को ऐतिहासिक रूप से छोटा किए जाने का आरोप लगाया। भट्टाचार्य ने कहा कि उनकी पार्टी का रुख सुसंगत है और चुनाव से प्रेरित नहीं है।

महर्षि दयानंद के जीवन मूल्यों से समाज का कल्याण संभव : विद्वानों का मत

आर्य समाज स्थापना के 150 वर्ष पूर्ण होने पर चार दिवसीय 'महर्षि महिमा पर्व एवं ऋषि बोधोत्सव' का शुभारंभ

कोलकाता, समाज्ञा : आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 'आर्य समाज स्थापना समारोह समिति' द्वारा आयोजित चार दिवसीय 'महर्षि महिमा पर्व एवं ऋषि बोधोत्सव' का शुभारंभ गुरुवार को विवेकानंद रोड स्थित रामकृष्ण मंच में गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। 12 से 15 फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन का उद्देश्य महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन, विचार एवं समाज-सुधार संबंधी योगदान को जन-जन तक पहुंचाना है। कार्यक्रम का प्रारंभ प्रातः 8 बजे सामूहिक 'चतुर्वेद शतकम यज्ञ' से हुआ। आचार्य राहुल देव शास्त्री एवं पंडित योगेशराज उपाध्याय के पौरोहित्य में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ संपन्न किया गया। यज्ञ के माध्यम से विश्व शांति, सामाजिक सद्भाव एवं राष्ट्र कल्याण की कामना की गई। तत्पश्चात मुख्य मंच पर दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन सत्र का विधिवत शुभारंभ किया गया।

उद्घाटन अवसर पर समिति के प्रधान आनंद देव आर्य, मंत्री दीपक आर्य, कोषाध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल, आचार्य डॉ. ज्वलंत शास्त्री तथा भजनोपदेशक प्रदीप आर्य सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। प्रारंभिक सत्र में भजनोपदेशक प्रदीप आर्य ने भजनों के माध्यम से महर्षि दयानंद के आदर्शों को भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया। इसके पश्चात मुख्य वक्ता आचार्य डॉ. ज्वलंत शास्त्री एवं प्रो. विनय विद्यालंकार ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि महर्षि दयानंद ने समाज को अंधविश्वास, कुरीतियों एवं रूढ़ियों से मुक्त कर वेदों की ओर लौटने का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने सत्य, तर्क एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने पर बल दिया तथा नारी शिक्षा, सामाजिक समता एवं राष्ट्रीय चेतना के क्षेत्र में उनके योगदान को ऐतिहासिक बताया। सत्र का सफल संचालन आचार्य योगेश जी द्वारा किया गया। सांध्य सत्र में 'सर्वधर्म सम्मेलन' का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता रमेश नांगलिया ने की। कार्यक्रम संयोजक प्रमोद अग्रवाल के नेतृत्व में आयोजित इस सम्मेलन में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के प्रतिनिधियों ने धर्म के मूल स्वरूप पर अपने विचार रखे। ईसाई मत से रेवरेंड अर्पण मखाल, नाखुदा मस्जिद से मोहम्मद कासिम, ब्रह्मकुमारी संस्था से बी.के. सुप्रिया कुमारी तथा जैन संप्रदाय से डॉ. प्रेमलता जैन ने सहभागिता करते हुए धर्म की मानवीय एवं नैतिक अवधारणाओं को रेखांकित किया। रामकृष्ण मिशन की ओर से स्वामी रामभद्राचार्य ने आध्यात्मिक एकता एवं मानव सेवा को धर्म का आधार बताया। अंत में आर्य विद्वान डॉ. ज्वलंत शास्त्री एवं प्रो. विनय विद्यालंकार ने सभी वक्तव्यों की समन्वित समीक्षा प्रस्तुत करते हुए धर्म की सार्वभौमिकता एवं समन्वयकारी स्वरूप को स्पष्ट किया। कार्यक्रम के समापन पर समिति के मंत्री दीपक आर्य ने सभी अतिथियों, विद्वानों एवं उपस्थित जनों के प्रति आभार व्यक्त किया। शांति पाठ के साथ प्रथम दिवस का कार्यक्रम संपन्न हुआ।

श्रीरामपुर वाल्स अस्पताल में शुरू हुई संध्या ओपीडी सेवा

रोगी सेवाओं को उन्नत बनाने के लिए उठाया गया महत्वपूर्ण कदम

हुगली, समाज्ञा : रोगी सेवाओं उन्नत बनाने के लिए राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में नए-नए विभाग शुरू किए जा रहे हैं। इसी के तहत जिला और महकमा अस्पतालों के साथ-साथ जिन सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की स्थापना हुई है, वहां संध्या ओपीडी शुरू किया गया है। अब इस सूची में हुगली के श्रीरामपुर वाल्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का नाम भी जुड़ गया है। यहां शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक संध्या ओपीडी सेवा शुरू की जा रही है। मंगलवार को बाल रोग और गुरुवार को स्त्री रोग विभाग में, सप्ताह में दो दिन यह सेवा उपलब्ध होगी। हालांकि अस्पताल में 24 घंटे आपातकालीन सेवा पहले की तरह जारी रहेगी।

श्रीरामपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अस्पताल अधीक्षक प्रणबेश हलदार ने डॉक्टरों के साथ बैठक की। इस बैठक में अन्य चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी भी मौजूद थे। शाम के समय बच्चों और महिलाओं की चिकित्सा सेवाओं में किसी तरह की कमी न रहे, इसे सुनिश्चित करने के लिए यह बैठक की गई। इसके अलावा, शाम की ओपीडी में इलाज के बाद मरीजों को आवश्यक दवाइयां अस्पताल से ही मिलें, इस पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।

दिन के समय मरीजों की भीड़ कम करने और शाम को ओपीडी शुरू करने के सरकारी फैसले का आम लोगों ने स्वागत किया है। अस्पताल में इलाज कराने आए एक मरीज के परिजन आलोक कुमार नंदी ने कहा हमारा घर चंडीतला में है। मैं निजी संस्था में काम करता हूं। दिन में अस्पताल आने के लिए काम से छुट्टी लेनी पड़ती है। शाम की ओपीडी शुरू होने से हमारे जैसे दूर से आने वाले लोगों को काफी सुविधा होगी। रीना पासवान ने कहा बाल रोग विभाग में दिन के समय बहुत ज्यादा भीड़ होती है। इस दृष्टि से यह अच्छा कदम है।

रोगी कल्याण समिति के सदस्य संतोष कुमार सिंह ने कहा, कई लोग खेती-बाड़ी और दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। वे काम छोड़कर अस्पताल नहीं आ पाते। इसी कारण सरकार ने संध्या ओपीडी शुरू करने की पहल की है। श्रीरामपुर के विधायक सुदीप्त राय ने कहा कि हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार हुआ है। संध्या ओपीडी शुरू होने से सभी को लाभ होगा।

ब्रह्मानंद अग्रवाल बने सीकर नागरिक परिषद (कोलकाता) के नए अध्यक्ष

सचिव श्री रवि शंकर सिकरिया

अध्यक्ष एमिरेट्स श्री घनश्याम प्रसाद सोभासरिया

श्री ब्रह्मानंद जी अग्रवाल

कोलकाता, समाज्ञा : सीकर नागरिक परिषद (कोलकाता) के वर्ष 2026-27 हेतु अध्यक्ष पद पर ब्रह्मानंद अग्रवाल (सुपुत्र पद्मश्री स्वर्गीय मामराज अग्रवाल) को मनोनीत किया गया। गुरुवार को सीकर भवन में आयोजित एक गरिमामय सुसज्जित समारोह में श्री अग्रवाल ने विधिवत अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया। समारोह में परिषद के ट्रस्टीगण, पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण उपस्थित रहे। सभी ने नवनियुक्त अध्यक्ष का पुष्पगुच्छ एवं माल्यार्पण कर अभिनंदन किया तथा हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित कीं। इस अवसर पर परिषद की गतिविधियों को और अधिक सशक्त, सक्रिय एवं व्यापक बनाने के साथ-साथ भावी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं समाज सेवा संबंधी योजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। अपने उद्बोधन में ब्रह्मानंद अग्रवाल ने परिषद को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने हेतु पूर्ण समर्पण एवं सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने सभी सदस्यों से समाजहित में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। अध्यक्ष एमेरिटस घनश्यामप्रसाद सोभासरिया ने इस निर्णय को परिषद के लिए गौरव एवं उत्साह का विषय बताया। सचिव रविशंकर सिकरिया ने विश्वास व्यक्त किया कि परिषद अब और अधिक तीव्र गति से सामाजिक सेवा और संस्कार एवं संस्कृति जैसे कार्यों को संपादित करेगी। समारोह का संचालन पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मी कुमार बियानी ने किया। नई कार्यकारिणी (वर्ष 2026-27) में अध्यक्ष एमेरिटस घनश्यामप्रसाद सोभासरिया, अध्यक्ष ब्रह्मानंद अग्रवाल, उपाध्यक्ष अनिल कुमार पोद्दार, उपाध्यक्ष दामोदर प्रसाद बिदावतका, उपाध्यक्ष विनोद कुमार अग्रवाल, सचिव रवि शंकर सिकरिया, सह-सचिव नवनीत सोढ़ानी, सह-सचिव केशव कुमार सोमानी, कोषाध्यक्ष श्रीमोहन चौधरी हैं। वहीं, कार्यकारिणी सदस्य आदित्य विक्रम बियानी, जगदीश प्रसाद सिंघी, कमल प्रसाद चौधरी, काशी प्रसाद धेलिया, प्रदीप कुमार चौधरी, रजनीश कुमार बजाज, राजकुमार अग्रवाल, राम गोपाल सराफ, रामोतार अग्रवाल, रतन कुमार सीकरिया, रवि लोहिया, संजय कुमार शर्मा और सुशील कुमार अग्रवाल हैं।

जेनरेशन लार्ज की मूल आवाज़ के साथ लौट आया सीग्राम्स रॉयल स्टैग बूमबॉक्स पहले से अधिक भव्य

मुंबई/कोलकाता : बॉलीवुड के सदाबहार संगीत का हिप-हॉप की जोशीली धुनों से मेल करवाने वाला आइकॉनिक म्यूज़िक फेस्टिवल सीग्राम्स रॉयल स्टैग बूमबॉक्स अपने बहुप्रतीक्षित चौथे सीज़न के साथ लौट आया है। पिछले तीन सीज़न की अभूतपूर्व कामयाबी को आगे बढ़ाते हुए, इस साल रॉयल स्टैग बूमबॉक्स नया इतिहास रचने के लिए तैयार है। नए सीज़न में देश-विदेश की सबसे प्रसिद्ध संगीत प्रतिभाओं की असाधारण लाइन-अप होगी और देश के चार जीवंत युवा केंद्रों - विशाखापत्तनम, कोलकाता, मुंबई और मोहाली में चकाचौंध करने वाले आयोजन होंगे। रॉयल स्टैग बूमबॉक्स अपने उन दर्शकों को अनूठा अनुभव देने के लिए मशहूर है। यह आज के युवाओं, यानी 'द जेनरेशन ऑफ लार्ज' - में जुनून जगाने वाले बिंदुओं - म्यूजिक, फैशन, फूड और गेमिंग को साथ लाकर उप-सांस्कृतिक तत्वों को समाहित करता है।

नि:शुल्क चिकित्सा कैंप आयोजित

कोलकाता, समाज्ञा : श्री शिव देव प्रयाग मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट ने गत रविवार को एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का सफल आयोजन किया। डॉ. अविनाश दत्त शर्मा के नेतृत्व में, किडनी, कैंसर, लीवर, और स्टोन के 250 से अधिक रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज किया गया। यह शिविर अतीन्द्र मेडिकेयर नर्सिंग होम, मेट्रोपोलिटन में आयोजित किया गया। शिविर में रोगियों के लिए ऑपरेशन भी बुक किए गए।

सीडा आयोजित करेगा 'इलेक्ट्रा 2026' का 8वां संस्करण, 20 फरवरी को नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप का भव्य लॉन्च

कोलकाता, समाज्ञा : कलकत्ता इलेक्ट्रिक डीलर्स एसोसिएशन (सीडा) 19 से 21 फरवरी 2026 तक 'इलेक्ट्रा 2026' के 8वें संस्करण का आयोजन करेगा। वर्ष 1986 में स्थापित और देश की सबसे बड़ी विद्युत व्यापारिक संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त यह संगठन कोलकाता के विद्युत थोक बाजार के केंद्र कच्छी जैन भवन, एजरा स्ट्रीट में तीन दिवसीय इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड फेयर का आयोजन करेगा, जिसमें उद्योग से जुड़े निर्माता, वितरक और व्यापारिक पेशेवर भाग लेंगे। इस व्यापार मेले में दो मंजिलों पर 46 से अधिक चयनित स्टॉल लगाए जाएंगे, जो निर्माताओं, वितरकों और व्यापारिक पेशेवरों के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करेंगे। कार्यक्रम को लाइट्स का गोल्ड स्पॉन्सर, ट्रू पावर लिमिटिड का सिल्वर स्पॉन्सर तथा 91.9 फ्रेंड्स एफएम का रेडियो पार्टनर के रूप में समर्थन प्राप्त है। सीडा 20 फरवरी को अपने नवीनीकृत आधिकारिक वेबसाइट और एंड्रॉयड व आईओएस के लिए पहली मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ करेगा। यह ऐप डिजिटल सदस्यता निर्देशिका के रूप में कार्य करेगी और संगठन के भीतर संचार तथा संचालन समन्वय को सुगम बनाएगी। सीडा के अध्यक्ष अभिषेक वर्मा ने कहा कि यह एक्सपो 1,600 से अधिक सदस्यों की सामूहिक शक्ति और संगठित व्यापारिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ट्रेड फेयर समिति के चेयरमैन सत्य प्रकाश शाव ने बताया कि 8वां संस्करण उद्योग संबंधों को मजबूत करने और व्यापारिक सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। इन्फोटेक संयोजक आशीष अग्रवाल ने नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप के विकास के माध्यम से संगठन के डिजिटल परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मानद सचिव गगन दीप मुंधड़ा के मार्गदर्शन में सीडा अपने संस्थागत ढांचे का विस्तार करते हुए कोलकाता को एक प्रमुख विद्युत व्यापार केंद्र के रूप में और सुदृढ़ कर रहा है। यह प्रदर्शनी प्रतिदिन सुबह 11:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खुली रहेगी। व्यापारिक आगंतुकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। इस अवसर पर चंद्रेश मेघाणी , उमाकांत अग्रवाल , मिनेश ठकरार एवं अन्य उपस्थित रहे

न्यूज इन ब्रीफ

पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की प्रकिया जारी: उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय से कहा

लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ को उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि वह राज्य में आगामी पंचायत चुनाव कराने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने में जुटी है। न्यायमूर्ति राजन राय एवं न्यायमूर्ति ए के चौधरी की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से यह वक्तव्य आने के बाद याचिका को निस्तारित कर दिया। एक जनहित याचिका दाखिल कर अनुरोध किया गया था कि उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल करीब पांच महीने पहले ही पूरा गया लेकिन सरकार ने अबतक आयोग का गठन नहीं किया है। जनहित याचिका में कहा गया है कि यदि आयोग का गठन नहीं किया जाता है और 2021 की आरक्षण सूची के आधार पर पंचायत चुनाव कराए जाते हैं, तो यह उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन होगा। याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया है कि वह सरकार के निर्देश दे कि वह इस आयोग का गठन करे। याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने राज्य सरकार की ओर अदालत को सूचित किया कि सरकार उक्त आयोग का गठन करने में जुटी है।

राजस्थान: ट्रेलर ने बाइक टक्कर मारी, तीन बच्चों की मौत

कोटा: राजस्थान के बूंदी जिले में एक ट्रेलर ट्रक के बाइक को टक्कर मारने से छह से 12 साल आयुवर्ग के तीन बच्चों की मौत हो गई जबकि उनके पिता गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, यह घटना जिले के डाबी थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर बुधवार देर शाम हुई। इस घटना के बाद परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और शवों को सड़क पर रख दिया तथा आरोपी ट्रक चालक की गिरफ्तारी की मांग की, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग एक घंटे तक यातायात बाधित रहा। पुलिस के अनुसार, मदन बंजारा बुधवार रात को मोटरसाइकिल से अपने गांव प्राणाना जा रहे थे। उनके साथ उनके तीन बच्चे – सुमन (6), अंकित बंजारा (8), करण बंजारा (12) भी थे। तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने कथित तौर पर उनकी मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया कि टक्कर भीषण थी और चारों पीड़ित सड़क पर घिसटते चले गए।

बिहार: प्रेशर हॉर्न और हूटर लगाने पर होगी सख्त कार्रवाई, उपकरण जब्त करने का आदेश

पटना: बिहार के परिवहन विभाग ने प्रेशर हॉर्न व हूटर लगे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने और इस तरह के उपकरणों को जब्त करने का निर्देश दिया। बृहस्पतिवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। अधिकारियों को प्रेशर हॉर्न और हूटर की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का भी निर्देश दिया गया है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बृहस्पतिवार को विधान परिषद में एक प्रश्न के जवाब में कहा कि मौजूदा नियमों में वाहन के हॉर्न समेत सभी साउंड सिस्टम के लिए सख्त डेसीबल सीमा तय है और इससे अधिक आवाज को हानिकारक माना जाता है। उन्होंने बताया, परिवहन विभाग ने राज्यभर के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रेशर हॉर्न व हूटर लगे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करें और ऐसे उपकरणों को जब्त करें। प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने वाणिज्यिक और निजी चार पहिया वाहनों में काले शीशों से जुड़े उल्लंघनों का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, यह मौजूदा नियमों का उल्लंघन है। वाहन के शीशों पर ब्लैक फिल्म या किसी भी अन्य सामग्री का उपयोग अनुमत नहीं है। इसलिए सभी वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि अगर उनके वाहनों में टिंटेड ग्लास या अन्य सामग्री लगी है, तो उसे तुरंत हटा दें। उल्लंघन पर चालान और मौके पर फिल्म हटाने की कार्रवाई की जाएगी। पिछले वर्ष बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से पटना में हर रविवार 'नो हॉन्किंग डे' मनाने की अपील भी की थी।

देवरिया जेल से रिहा हुए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर

देवरिया (उप्र): देवरिया जिले में दस दिसंबर से जिला कारागार में निरुद्ध पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के आदेश के बाद रिहा कर दिया। देवरिया के जेल अधीक्षक आशीष रंजन ने बताया कि जमानतदारों का सत्यापन कराने के बाद सीजेएम अदालत ने पूर्व आइपीएस की रिहाई का आदेश दिया तथा फिर उन्हें बुधवार शाम जेल से रिहा कर दिया गया। सूत्रों ने बताया कि जेल से निकलने के बाद पूर्व आइपीएस रिश्तेदारों के साथ चले गये। पूर्व आइपीएस को धोखाधड़ी से जमीन हड़पने के आरोप में जेल भेजा गया था। जिला उद्योग केंद्र (देवरिया) में 1999 में औद्योगिक भूखंड आवंटन से जुड़े एक गंभीर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया था।

पप्पू यादव की कई मामलों में जमानत याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई होगी

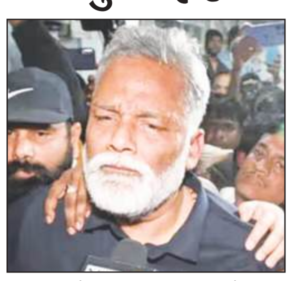

पटना: निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की विभिन्न मामलों में दायर जमानत याचिकाओं पर यहां की एक अदालत में शुक्रवार को सुनवाई होगी। उनके वकील ने यह जानकारी दी। वकील ने बताया कि यादव की जमानत याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को पूर्वाह्न लगभग 11 बजे सुनवाई होनी थी, लेकिन पटना दीवानी अदालत को बम की धमकी मिलने के कारण वह भोजनावकाश के बाद ही अदालत पहुंच सके। हालांकि यह धमकी बाद में फर्जी निकली। अदालत ने उन्हें मंगलवार को जालसाजी के तीन दशक पुराने एक मामले में जमानत दे दी थी, लेकिन पुलिस कार्यवाही में बाधा डालने समेत अन्य मामलों में उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया है।

सपा विधायकों को अपने क्षेत्र की जनता की चिंता हो या न हो, सरकार को उनकी चिंता है: दिनेश प्रताप सिंह

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने विधानसभा में कहा कि समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायकों को अपने क्षेत्र की जनता की चिंता हो या न हो लेकिन प्रदेश सरकार को उनके क्षेत्र की जनता की चिंता है। बजट सत्र के चौथे दिन बृहस्पतिवार को प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्य डॉ. आरके वर्मा के प्रश्न के जवाब में मंत्री ने कहा, ''माननीय विधायक, जिनका सवाल है और सभी सदस्यों से कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के विधायकों को अपने क्षेत्र की चिंता हो या न हो, राज्य सरकार को आपके क्षेत्र की जनता की चिंता है।' दरअसल, पूरक प्रश्न के दौरान वर्मा ने शुरुआत में कहा 'भारत पूछता है और आज किसान जब खाद मांगता है तो आपकी पुलिस का जवान लाठी मारता है। पूछता है भारत का किसान दसवां बजट पेश हो गया लेकिन उसकी आमदनी नहीं बढ़ी।' वर्मा ने प्रश्न किया कि प्रदेश के किसानों के कृषि उपज से संबंधित रोजगार, व्यापार उद्योग और विपणन बढ़ाने संबंधित कोई कार्ययोजना सरकार ने बनाई है। उन्होंने पूरक प्रश्न किया कि प्रयागराज के सोरांव में जो औद्योगिक गलियारा बना रहे हैं, क्या उसे कृषि गलियारा बनाने का कार्य करेंगे। दिनेश प्रताप सिंह ने जवाब देते हुए कहा, 'भारत पूछता है, पता नहीं किससे पूछता है, मुझे नहीं मालूम... माननीय विधायक जी से आपकी विधानसभा आलापुर की जनता अगर सवाल पूछती तो बहुत अच्छा लगता, काश, विधायक जी, आलापुर को पता होता कि सवाल किस विभाग से किया जा रहा है, लिखित रूप से किस विभाग से पूछा जा रहा है और उसकी विषय वस्तु कहां ले जा रहे हैं।'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'एक्स' पर अपने एकाउंट में बदला 'कवर फोटो'

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को 'एक्स' पर अपने अकाउंट में 'कवर इमेज' बदल दिया। मुख्यमंत्री ने ब्रह्मोस संग अपनी फोटो लगाकर 'हार्ड पावर' विजन का संदेश दिया। एक बयान के मुताबिक 'एक्स' पर मुख्यमंत्री ने जो फेरबदल किया है उससे यह यह संदेश देने की कोशिश की गयी है कि लखनऊ में ब्रह्मोस निर्माण के जरिए उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पादन का उभरता वैश्विक हब हो गया है। उन्होंने इस बदलाव से 9.12 लाख करोड़ रुपये का बजट और सामरिक शक्ति के संगम का भी संकेत प्रदेशवासियों के समक्ष प्रस्तुत किया है। बजट के जरिए योगी आदित्यनाथ ने संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था फर्श से अर्श तक पहुंच गई है, जो राज्य के विकास, सुरक्षा और निवेश के त्रिवेणी मॉडल को प्रदर्शित करता है। मुख्यमंत्री का यह सुपरसोनिक केसरिया' संदेश बताता है कि उत्तर प्रदेश विकास का इंजन और प्रदेशवासियों की सुरक्षा का कवच भी बन गया है।

पटना में छात्रावास में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले को सीबीआई ने अपने हाथ में लिया

नयी दिल्ली: पटना में 'राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा' (नीट) की तैयारी कर रही एक छात्रा की रहस्यमय परिस्थितियों मे हुई मौत के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मामला दर्ज करके स्थानीय पुलिस से जांच अपने हाथ में ले ली है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। जहानाबाद की रहने वाली और नीट परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा छह जनवरी को पटना के चित्रगुप्त नगर स्थित एक महिला छात्रावास में बेहोश पाई गई थी। बाद में वह कोमा में चली गई और पांच दिन बाद एक निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। छात्रा की मौत के बाद मचे राजनीतिक हंगामे के कारण बिहार सरकार ने 31 जनवरी को मामला सीबीआई को सौंप दिया।

समाज को सही दिशा देने में में पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका : सतीश महाना

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने बृहस्पतिवार को कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और समाज को सही दिशा देने में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार कानुपर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के विद्यार्थियों ने शैक्षणिक भ्रमण के अंतर्गत बृहस्पतिवार को विधानसभा का भ्रमण कर सदन की कार्यवाही देखी। इस दौरान विद्यार्थियों को विधानसभा की कार्यप्रणाली, विधायी प्रक्रिया तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका की विस्तृत एवं प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान की गई। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने सेंट्रल हॉल, दर्शक दीर्घा, मीडिया गैलरी तथा विभिन्न समिति कक्षों का अवलोकन किया। विधानसभा अधिकारियों ने विद्यार्थियों को बताया कि किस प्रकार विधेयक सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं, उन पर चर्चा होती है और तत्पश्चात वे अधिनियम का स्वरूप ग्रहण करते हैं। इस अवसर पर महाना ने विद्यार्थियों से कहा, 'पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और समाज को सही दिशा देने में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।' उन्होंने कहा, ''पत्रकार का दायित्व केवल समाचार देना नहीं, बल्कि सत्य, निष्पक्षता और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए समाज की आवाज बनना है।'

न्यूज अपडेट

झारखंड: रांची जिलाधिकारी कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली, तलाशी अभियान जारी

रांची: झारखंड के रांची जिलाधिकारी कार्यालय को बृहस्पतिवार को प्राप्त एक ईमेल में परिसर को उड़ाने की धमकी दी गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह ईमेल उपायुक्त की आधिकारिक आईडी पर भेजा गया था। रांची के उपमंडल अधिकारी (एसडीओ) उत्कर्ष कुमार ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, 'इस संबंध में जांच जारी है। अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है।' एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बम का पता लगाने और उसे निष्क्रिय करने वाली टीम (बीडीडीएस) को तैनात कर दिया गया है और परिसर में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईमेल के स्रोत का पता लगाने के लिए साइबर प्रकोष्ठ टीम को भी सक्रिय कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि छह फरवरी को रांची दीवानी अदालत को ईमेल के जरिए इसी तरह की धमकी मिली थी, जो बाद में झूठी साबित हुई क्योंकि तलाश अभियान में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला था।

कानपुर लैंबॉर्गिनी हादसा मामले में तंबाकू कारोबारी के बेटे को अदालत से जमानत मिली

कानपुर (उप्र): कानपुर की एक अदालत ने 'हाई-प्रोफाइल' लैंबॉर्गिनी दुर्घटना मामले में आरोपी शिवम मिश्रा को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी। इस मामले से जुड़े एक अधिवक्ता ने यह जानकारी दी। पुलिस ने इस सप्ताह के आरंभ में यहां वीआईपी रोड पर हुई 'हाई-प्रोफाइल' लैंबॉर्गिनी दुर्घटना के मामले में स्थानीय तंबाकू कारोबारी के. के. मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा को बृहस्पतिवार को ही गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए थे। आरोपी के अधिवक्ता अनंत शर्मा ने बताया कि पुलिस ने मामले में उसकी 14 दिन की हिरासत मांगी थी, लेकिन अदालत ने इसकी इजाजत नहीं दी और इसके बजाय उसे 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।

राजस्थान में गौशालाओं को 784 करोड़ रूपये से अधिक की सहायता

जयपुर: राजस्थान में 3,174 गौशालाओं को 2025-26 में 784.43 करोड़ रूपये की सहायता दी गई है। राज्य सरकार ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में यह जानकारी दी। गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम के तहत पात्र गौशालाओं को गोवंश के वास्ते चारा-पानी, पशु आहार की व्यवस्था करने और आधारभूत परिसम्पतियों के निर्माण के लिए सहायता राशि दी जाती है। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत वित्त वर्ष 2025-26 में 2024-25 के द्वितीय चरण के तहत 3,174 पात्र गौशालाओं को गौवंश के लिए 784.43 करोड़ रूपये की सहायता दी गई है। मंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक हंसराज पटेल द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पंचायत समिति नंदीशाला जन सहभागिता योजना के तहत निराश्रित या नर गौवंश को आश्रय प्रदान करने के लिए प्रत्येक पंचायत समिति में आधारभूत परिसंपतियों के निर्माण हेतु एक करोड़ 57 लाख रुपए का प्रावधान है तथा इस सिलसिले में राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त और तीन साल का अनुभव रखने वाली गौशालाएं आवेदन कर सकती हैं। इससे पहले सदस्य के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में गोपालन मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी एवं शराब पर अधिभार से प्राप्त राजस्व से पंजीकृत गौशालाओं को अनुदान दिया जाता है।

परिमार्जन से जुड़ी 40 लाख शिकायतें लंबित: मंत्री

पटना: बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बृहस्पतिवार को कहा कि जन संवाद कार्यक्रम के दौरान प्राप्त कुल 46 लाख शिकायतों में से 40 लाख केवल परिमार्जन, यानी नाम तथा खसरा-खाता संख्या से जुड़ी त्रुटियों से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि इन शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश दिया गया है। सिन्हा विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के विधायक मंजीत सिंह के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने एक अन्य प्रश्न के जवाब में कहा कि विशेष सर्वेक्षण के बाद सभी अंचलों की असर्वेक्षित भूमि का भी सर्वेक्षण कराया जाएगा।

समीक्षा CINE मंत्र

सलमान ने दिए पैसे तो सोनू सूद ने ऑफर की फिल्म, जानिए किसने किस तरह की राजपाल यादव की मदद?

अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव चेक बाउंस मामले में जेल में हैं। मामला करीब 9 करोड़ रुपये की देनदारी से जुड़ा हुआ है, जिन्हें वे तय समय सीमा पर चुका नहीं पाए। इसी वजह से उन्होंने बीते दिनों तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया था। ऐसे वक्त में इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे राजपाल की मदद को सामने आए हैं।

सोनू सूद ने शुरू की मदद की पहल

सबसे पहले 10 फरवरी को सोनू सूद ने एक पोस्ट शेयर करते हुए राजपाल की मदद करने की बात कही थी। उन्होंने राजपाल को फिल्म ऑफर करने की भी बात कही थी। साथ ही पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री से अपील की थी कि सब लोग राजपाल की मदद के लिए आगे आएं।

सोनू की इस पहल के बाद जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप ने भी मदद का हाथ बढ़ाया था और 11 लाख की मदद का वादा किया था।

एक्टर और प्रोड्यूसर मदद को आए आगे

इसके बाद टीवी एक्टर गुरमीत चौधरी ने द पर पोस्ट कर राजपाल को हर संभव मदद देने का वादा किया था। साथ ही सभी एक्टर्स से अपील की थी कि वे मदद के लिए आगे आएं। वहीं संगीत कंपनी के मालिक राव इंद्रजीत सिंह यादव ने भी बड़ी मदद की पेशकश की। उन्होंने राजपाल यादव को 1.11 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की बात कही है।

इसके बाद मंगलवार को अभिनेता और फिल्म क्रिटिक केआरके ने राजपाल को 10 लाख रुपये देने की बात कही। उन्होंने बॉलीवुड के सभी लोगों से कहा कि मिलकर उन्हें 5 करोड़ देते हैं। अगर वह सिर्फ 5 करोड़ वापस कर देते हैं, तो वह तुरंत जेल से बाहर आ सकते हैं। चलो सब उनकी मदद करते हैं।

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने चुपके से की मदद

'इंडियाटुडे' की रिपोर्ट के मुताबिक, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी राजपाल की चुपके से मदद की है और 10 लाख रुपये भिजवाए हैं। इसके बाद गुरु रंधावा ने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर राजपाल की मदद की बात कही। दरअसल, राजपाल और गुरु रंधावा ने साथ में एक म्यूजिक वीडियो में काम किया है, जो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसकी पेमेंट भी अभी क्लियर नहीं हुई थी, पर राजपाल यादव की हालत देख गुरु रंधावा ने उन्हें एडवांस पेमेंट देने का ऐलान किया है।

इसके साथ, FWICE (फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एंप्लॉय्ज) ने भी बुधवार, 11 फरवरी को सभी प्रोड्यूसर्स से अपील की है कि वो जल्द से जल्द राजपाल यादव की मदद करें।

इंडस्ट्री के बड़े एक्टर मदद को आए आगे

वहीं, हाल ही में राजपाल यादव के मैनेजर गोल्डी ने 'द स्क्रीन' को दिए इंटरव्यू में बताया कि सलमान खान अजय देवगन और वरुण धवन भी एक्टर की मदद को आगे आए हैं और आर्थिक मदद की है। हालांकि अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि उन्होंने कितनी राशि की आर्थिक मदद दी है।

सिंगर मीका और अनूप जलोटा ने भी की आर्थिक मदद

सिंगर मीका सिंह ने भी राजपाल के सामने मदद का हाथ बढ़ाया। सिंगर मीका सिंह ने 11 लाख रुपये की मदद देने का एलान किया। उन्होंने कहा, 'राजपाल जी, मैं आपके साथ खड़ा हूं।'

वहीं सिंगर अनूप जलोटा ने भी आज 12 फरवरी को एक वीडियो शेयर कर राजपाल की मदद की बात कही। उन्होंने कहा, 'उतार-चढ़ाव जीवन का हिस्सा हैं। हमें हमारे दोस्तों की मदद करना चाहिए। मुझे पता है कई लोग उनकी मदद को आगे आएं हैं। मैं भी 5 लाख रुपये उन्हें भेज रहा हूं। उम्मीद है इनसे उन्हें मदद मिलेगी।

इसके साथ टीवीएफ (द वायरल फीवर), जो कि एक डिजिटल एंटरटेनमेंट कंपनी और प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने भी एक पोस्ट शेयर कर राजपाल की मदद की बात कही है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा- 'हम आपके साथ खड़े हैं और आपका समर्थन करते हैं।'

क्या है मामला?

साल 2010 से जुड़े एक पुराने चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव इस समय जेल में हैं। दरअसल, उन्होंने अपनी फिल्म 'अता पता लापता' के निर्माण और निर्देशन के लिए एक कंपनी से करोड़ों रुपये का कर्ज लिया था। बताया जाता है कि तय समयसीमा के भीतर राशि वापस नहीं चुकाई जा सकी। अदालत की ओर से कई अवसर दिए गए, लेकिन भुगतान न होने पर सख्त रुख अपनाया गया।

इसके बाद कोर्ट ने उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का निर्देश दिया। अदालती आदेश के पालन में राजपाल यादव ने 5 फरवरी को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। यह मामला करीब 9 करोड़ रुपये की देनदारी से जुड़ा हुआ है, जिस पर कानूनी प्रक्रिया जारी है।

'मेरा तो 14 फरवरी का प्लान फिक्स'; डेटिंग रूमर्स के बीच बोलीं शमिता शेट्टी

अभिनेत्री शमिता शेट्टी ने बीते दिनों अपना जन्मदिन मनाया। उनके बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटोज में उनके एक दोस्त की झलक दिखी। इसके बाद उनकी डेटिंग को लेकर अफवाहें शुरू हो गईं। बाद में शमिता ने डेटिंग संबंधी अफवाहों को खुद खारिज किया। मगर, इस बीच उन्होंने अपना वैलेंटाइन डे प्लान शेयर किया है।

बोलीं- 'मेरा तो प्लान फिक्स है'

शमिता शेट्टी ने आज गुरुवार को इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है। इसके साथ उन्होंने कैप्शन लिखा है, 'तैयारी पूरी है'। वीडियो में एक्ट्रेस कहती दिख रही हैं, 'मेरा तो 14 फरवरी का प्लान एकदम फिक्स है। किसी भी कपल को देखूंगी तो जोर-जोर से चिल्लाऊंगी कि भाई कल वाली अच्छी थी। फिर वो जाने और उसकी बंदी जाने'।

इस शख्स के साथ जोड़ा गया शमिता का नाम

बता दें कि बीते दिनों अभिनेत्री शमिता की डेटिंग लाइफ को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। दरअसल, उन्होंने 02 फरवरी को अपना जन्मदिन मनाया। इस जश्न में उनके साथ बहन शिल्पा शेट्टी और जीजू राज कुंद्रा भी मौजूद रहे। सोशल मीडिया पर सामने आईं शमिता के जन्मदिन के सेलिब्रेशन की तस्वीरों में एक शख्स ऐसा भी नजर आया, जिसके साथ शमिता का नाम जोड़ा गया। ये शख्स टेक्नो आर्टिस्ट-बिजनेसमैन दीपेश शर्मा थे। हलांकि, डेटिंग को लेकर शुरू हुई अफवाहों को शमिता ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए खारिज कर दिया।

शमिता ने क्या कहा था?

दीपेश शर्मा के साथ अफेयर की अफवाहों पर शमिता ने इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर कर लिखा था, 'सिंगल और शांत। सच्ची दोस्ती को गलत तरीके से समझने वाले रूढ़िवादी बनना बंद करो। ये सरासर बकवास है'। बता दें कि शमिता ने साल 2000 में फिल्म 'मोहब्बतें' से डेब्यू किया था।

सनी देओल और प्रीति जिंटा की फिल्म 'लाहौर 1947' अगस्त में रिलीज होगी

सनी देओल और प्रीति जिंटा की मुख्य भूमिकाओं वाली फिल्म 'लाहौर 1947' आगामी 13 अगस्त को रिलीज होगी। यह विभाजन के दौर की पृष्ठभूमि पर आधारित एक फिल्म है।

एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आमिर खान के प्रोडक्शन बैनर 'आमिर खान प्रोडक्शंस' के तहत निर्मित इस फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है। फिल्म में शबाना आजमी भी अहम भूमिका में हैं।

आमिर खान ने दिवंगत अभिनेता और सनी देओल के पिता धर्मेंद्र को याद किया। खान ने कहा कि यह उनकी पसंदीदा पटकथाओं में से एक थी।

खान ने एक बयान में कहा, यह धरमजी की पसंदीदा पटकथाओं में से एक थी।

यह फिल्म सनी देओल और प्रीति जिंटा की जोड़ी को एक बार फिर पर्दे पर वापस लाएगी। इससे पहले दोनों 'फर्ज' (2001) और 'द हीरो: लव स्टोरी ऑफ अ स्पाय' (2003) जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं।

सनी देओल की हालिया फिल्म 'बॉर्डर 2' है। यह फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

आगामी फिल्म 'लाहौर 1947' से प्रीति जिंटा भी बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं। उन्हें आखिरी बार 2018 में रिलीज हुई फिल्म 'भैयाजी सुपरहिट' में देखा गया था।

न्यूज इन ब्रीफ

वंदे मातरम् पर सरकार का आदेश असंवैधानिक, वापस नहीं हुआ तो न्यायालय जाएंगे: पर्सनल लॉ बोर्ड

नयी दिल्ली: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के सभी छह अंतरों को गाए जाने संबंधी सरकार के आदेश को 'असंवैधानिक' करार देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि यदि सरकार ने यह आदेश वापस नहीं लिया तो वह न्यायालय का रुख करेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि जब भी राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' और राष्ट्रगान 'जन गण मन' एक साथ गाए या बजाए जाएं तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए राष्ट्रगीत के सभी छह छंद पहले गाए जाएं।

इस तरह के शीर्षक से किसी वर्ग को अपमानित नहीं किया जा सकता: न्यायालय ने 'घूसखोर पंडत' मामले पर कहा

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने 'घूसखोर पंडत' शीर्षक पर अप्रसन्नता जताते हुए फिल्म निर्माता नीरज पांडे से बृहस्पतिवार को कहा कि आप इस तरह के शीर्षक का इस्तेमाल करके समाज के किसी वर्ग का अपमान नहीं कर सकते। न्यायालय ने ओटीटी मंच 'नेटफ्लिक्स' पर मनोज बाजपेयी अभिनीत फिल्म की रिलीज पर रोक लगाए जाने संबंधी याचिका की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने फिल्म के खिलाफ दायर याचिका पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और पांडे को नोटिस जारी किये।

ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा 18 फरवरी को पांच दिवसीय यात्रा के लिए भारत आएंगे

नयी दिल्ली: ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा 18 फरवरी को भारत की पांच दिवसीय यात्रा पर आएंगे। इस दौरान वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से व्यापक वार्ता करेंगे और एआई प्रभाव सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लूला की राजकीय यात्रा से दोनों देशों की द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। साथ ही द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों पर सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी।

गलती होने की किसी भी आशंका को कम से कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए : उच्चतम न्यायालय

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश की शीर्ष अदालत होने के नाते, यह प्रयास करना चाहिए कि ऐसी किसी भी गलती की आशंका को कम से कम किया जाए जिसका राष्ट्र के विकास और प्रगति पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने आगाह किया कि यह संदेश नहीं दिया जाना चाहिए कि न्यायिक प्रणाली में पूर्वानुमान का कोई तत्व नहीं है। पीठ ने परियोजनाओं को पूर्व प्रभाव से दी गई पर्यावरणीय मंजूरी से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणियां कीं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, 'हमें देश पर इसके समग्र प्रभावों और परिणामों पर भी विचार करना चाहिए। उच्चतम न्यायालय में, हमें ऐसी किसी भी गलती की आशंका को कम से कम करना चाहिए जिसका देश के विकास, प्रगति या पर्यावरण पर दूरगामी और विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है।'

उपमुख्यमंत्री शिंदे ने महाराष्ट्र में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया

मुंबई : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन्होंने अधिकारियों को मुंबई और महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने का निर्देश दिया है। शिंदे ने मुंबई जिला योजना एवं विकास समिति (डीपीडीसी) की बैठक में यह निर्देश जारी किया। यह निर्देश महानगर की नवनिर्वाचित भाजपा महापौर द्वारा यह कहे जाने के एक दिन बाद दिया गया कि शहर की सड़कों पर अतिक्रमण करने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों को निर्वासित करना उनकी प्राथमिकताओं में से एक होगा। शिंदे मुंबई जिले के प्रभारी मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है।

खरगे समेत कई विपक्षी सांसदों ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ संसद परिसर में प्रदर्शन किया

नयी दिल्ली: विपक्षी सांसदों ने बृहस्पतिवार को भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और सरकार पर भारतीय हितों का 'समर्पण' करने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश, द्रमुक नेता के टी.आर. बालू, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव और जया बच्चन, भाकपा-(माले) लिबरेशन के सांसद सुदामा प्रसाद सहित अन्य नेताओं ने संसद के मकर द्वार के पास प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उन्होंने एक बड़ा बैनर ले रखा था जिस पर 'ट्रैप डील' लिखा हुआ था। विपक्षी सांसदों ने 'नरेन्दर सरेंडर' लिखे हुए पोस्टर भी ले रखे थे। विपक्षी सांसदों ने देश को बेचना बंद करो जैसे नारे लगाए। बाद में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने कई अन्य कांग्रेस सांसदों के साथ मकर द्वार की सीढ़ियों पर खड़े होकर इस व्यापार समझौते के खिलाफ प्रदर्शन किया।

मुझ पर मुकदमा हो या विशेषाधिकार हनन, किसानों के लिए लड़ूंगा: राहुल

नयी दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर देश और किसानों को अमेरिका के हाथों बेचने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार उनके खिलाफ चाहे मुकदमा दर्ज करवाए या विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाए, वह किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी ने 'एक्स' और अपने व्हाट्सएप चैनल पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा, 'प्राथमिकी हो, मुकदमा दर्ज हो या विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएं, मैं किसानों के लिए लड़ूंगा। कोई भी ऐसा व्यापार समझौता जो किसानों की रोज़ी-रोटी छीने या देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करे, वह किसान-विरोधी है। किसान-विरोधी मोदी सरकार को अन्नदाताओं के हितों से समझौता नहीं करने देंगे।' लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, 'किसान विरोधी नरेन्द्र मोदी ने देश के अन्नदाताओं को, उनके खून-पसीने को ट्रम्प (अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप) के हाथों बेच दिया है। आखिर क्यों वह हमेशा किसानों की ही कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं?' उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री पहले अपने अरबपति मित्रों के मुनाफ़े के लिए काले क़ानून लाए थे, अब 'अपने गले से अमेरिकी शिकंजा हटाने' के लिए ट्रम्प के अमेरिका के सामने भारतीय खेती के दरवाज़े खोल दिए।

भारत परमाणु क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर, अपनी समयसीमा स्वयं तय कर रहा : सिंह

नयी दिल्ली: प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार देश में परमाणु संयंत्रों के चालू होने के संबंध में निर्धारित समयसीमा और सुरक्षा उपायों का पालन कर रही है। उन्होंने बताया कि कुडनकुलम परमाणु संयंत्र की तीसरी इकाई के 2026 तक और चौथी इकाई के 2027 तक पूरी होने की संभावना है। सिंह ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताया कि देश की परमाणु क्षमता 2031-32 तक लगभग तीन गुना बढ़कर 22,380 मेगावाट और 2047 तक 100 गीगावाट हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत का परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है और यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृढ़ विश्वास और 'लीक से हटकर सोच' के कारण ही संभव हो पाया है कि परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया गया है। सिंह ने कहा, 'करीब पांच साल पहले तक यह अकल्पनीय था। मुझे लगता है कि राष्ट्र और समाज ने यह स्वीकार कर लिया था कि हमें गोपनीयता के पर्दे के पीछे काम करना होगा। मुझे लगता है कि पहली बार हमने वैश्विक रणनीति अपनाई है। मंत्री ने बताया कि दो दिन पहले ही, 'हमने एक और रिकॉर्ड बनाया - रावतभाटा स्थित राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना ने 10 फरवरी को सुबह 5:30 बजे सफलतापूर्वक अपनी 700 मेगावाट की निर्धारित क्षमता हासिल कर ली।'

एअर इंडिया विमान दुर्घटना की जांच जारी है, कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है: एएआईबी

नयी दिल्ली : विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि पिछले वर्ष हुए एअर इंडिया विमान हादसे की जांच अभी जारी है और इस संबंध में कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। एएआईबी ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि दुर्घटना की जांच पूरी हो जाने संबंधी मीडिया रिपोर्ट गलत व अटकलों पर आधारित हैं। उल्लेखनीय है कि एअर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में 241 यात्रियों समेत कुल 260 लोगों की मौत हो गई थी। एएआईबी ने एक बयान में कहा, जांच अभी जारी है। कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। इसने यह भी कहा कि विमान दुर्घटना की जांच एक तकनीकी और साक्ष्य-आधारित प्रक्रिया होती है, जिसका उद्देश्य मूल कारणों का पता लगाना और विमानन सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले जारी की गई प्रारंभिक रिपोर्ट उस समय उपलब्ध तथ्यों पर आधारित थी। बयान में कहा गया, अंतिम जांच रिपोर्ट जांच पूरी होने के बाद निर्धारित अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रकाशित की जाएगी, जिसमें निष्कर्ष और सुरक्षा संबंधी सिफारिशें शामिल होंगी।

एअर इंडिया ने अंतिम मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की

नयी दिल्ली: एअर इंडिया ने विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को अंतिम मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया के तहत मुआवजा स्वीकार करने के इच्छुक लोगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे भविष्य में विमानन कंपनी, मूल उपकरण निर्माताओं और सरकारी एजेंसियों के खिलाफ इस घातक दुर्घटना के संबंध में कोई दावा नहीं करेंगे। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एअर इंडिया अंतरिम मुआवजे के तौर पर प्रति मृतक 25 लाख रुपये का भुगतान करने की प्रक्रिया में है। सूत्रों ने बृहस्पतिवार को बताया कि यदि अंतिम मुआवजे की राशि अंतरिम मुआवजे के रूप में भुगतान की गई 25 लाख रुपये से कम होती है, तो उन परिवारों को प्रति मृतक अतिरिक्त 10 लाख रुपये की पेशकश की जाएगी।

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लेह में हिंसा नियंत्रण में आई: केंद्र ने न्यायालय को बताया

नयी दिल्ली: केंद्र ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले साल 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा में भीड़ को उकसाने वाले मुख्य शख्स थे। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज ने न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ को बताया कि वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन और हिंसा नियंत्रण में आ गयी। नटराज ने पीठ को बताया, वह हिंसा को मुख्य रूप से उकसाने वाले थे। इस हिंसा में चार लोग मारे गए थे और 60 लोग घायल हुए थे। हिरासत आदेश में स्पष्ट संबंध दिखता है, इसमें स्पष्ट रूप से सोची-समझी रणनीति का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा, उनकी गिरफ्तारी के बाद आंदोलन और हिंसा नियंत्रण में आ गई। इसलिए यह साबित हो गया कि गिरफ्तारी का आदेश एक सटीक आदेश था जो उस स्थिति में उचित था।

भारतीय वायुसेना ब्रिटिश शाही सेना के पायलटों को प्रशिक्षित करेगी

नयी दिल्ली: भारतीय वायुसेना पहली बार ब्रिटेन की शाही वायुसेना के पायलटों को प्रशिक्षण देने जा रही है। यह निर्णय बृहस्पतिवार को नयी दिल्ली में आयोजित 19वीं ब्रिटेन-भारत वायुसेना वार्ता में लिया गया। ब्रिटेन द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, 'नवीनतम समझौते के तहत, भारतीय वायुसेना तीन योग्य उड़ान प्रशिक्षकों (क्यूएफआई) को ब्रिटेन में शाही वायुसेना (आरएएफ) वैली में तैनात करेगी - जो ब्रिटिश लड़ाकू विमानों के पायलटों के लिए प्रशिक्षण केंद्र है।' इसमें कहा गया, 'यह पहली बार है कि भारतीय योग्य उड़ान प्रशिक्षक आरएएफ वैली में ब्रिटिश पायलटों को लड़ाकू विमानों का प्रशिक्षण देंगे। यह तैनाती शुरू में दो साल की अवधि के लिए होगी।' यह घटनाक्रम इस वर्ष जनवरी में भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी की शाही वायुसेना महाविद्यालय क्रैनवेल में प्रशिक्षक के रूप में पहली बार तैनाती के ठीक बाद हुआ है। यह वायु अकादमी आरएएफ अधिकारियों की अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करती है। विज्ञप्ति के मुताबिक, इस नयी पहल के तहत अब तीनों ब्रिटिश सैन्य अकादमियां संबंधित सेवाओं के भारतीय अधिकारियों को प्रशिक्षक के रूप में आमंत्रित कर रही हैं। शाही वायुसेना के सहायक प्रमुख एयर वाइस मार्शल इयान टाउनसेंड ने कहा, 'इस समझौते पर हस्ताक्षर करना ब्रिटिश शाही वायुसेना और भारतीय वायुसेना के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।'

देश में विमान, हेलीकॉप्टर के 25,001 पायलट हैं : सरकार

नयी दिल्ली: सरकार ने बृहस्पतिवार को लोकसभा को बताया कि देश में विभिन्न श्रेणियों के लाइसेंस रखने वाले 65 वर्ष से कम आयु के पायलट की कुल संख्या 25,001 है, जिनमें 10,261 'एयरलाइंस ट्रांसपोर्ट लाइसेंस' (एपीटीएल) धारक शामिल हैं। नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कि 65 वर्ष से कम आयु के और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा जारी विभिन्न श्रेणियों के लाइसेंस रखने वाले पायलट की संख्या 25,001 है। आंकड़ों के अनुसार, इनमें से 10,051 पायलट 'एयरलाइंस ट्रांसपोर्ट लाइसेंस' धारक विमानों के और 210 हेलीकॉप्टर के हैं। वहीं, केवल हवाई जहाज और केवल हेलीकॉप्टर परिचालन के लाइसेंस धारक पायलट की संख्या क्रमशः 12,480 और 777 है। इसके अलावा, आंकड़ों से पता चला कि 1,477 पायलट के पास निजी पायलट लाइसेंस (विमान) और छह पायलट के पास हेलीकॉप्टर परिचालन के लिए निजी पायलट लाइसेंस है।

केंद्र यूएई में अभिनेत्री सेलिना जेटली के भाई से बातचीत करे: अदालत

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में एक साल से अधिक समय से हिरासत में रखे गए अभिनेत्री सेलिना जेटली के भाई मेजर (सेवानिवृत्त) विक्रांत जेटली से बातचीत करे और उनके लिए राजनयिक पहुंच की व्यवस्था करे। अदालत ने विक्रांत को विधिक सहायता उपलब्ध कराए जाने के मुद्दे पर यह बात कही। न्यायालय ने केंद्र से यह भी कहा कि विक्रांत जेटली ने अपनी बहन द्वारा सुझाई गई कानूनी फर्म को नियुक्त करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई उनकी राय पर निर्भर करेगी। उच्च न्यायालय सेलिना जेटली की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने अपने भाई के लिए प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व का अनुरोध किया था। सेलिना के भाई को छह सितंबर, 2024 से संयुक्त अरब अमीरात में 'अवैध रूप से अगवा करके हिरासत में' रखा गया है। केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि भारतीय अधिकारी विक्रांत जेटली के साथ नियमित संपर्क में हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बहन से बात करने से इनकार कर दिया है। वकील ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों ने 13 फरवरी को विक्रांत जेटली से बातचीत का अनुरोध किया था। केंद्र के वकील ने कहा कि सेवानिवृत्त सेना अधिकारी के अनुसार, विक्रांत की पत्नी ही उनकी ओर से निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं।

दूरदर्शन की पूर्व समाचार वाचिका सरला माहेश्वरी का निधन

नयी दिल्ली: दूरदर्शन की पूर्व समाचार वाचिका सरला माहेश्वरी का बृहस्पतिवार को यहां निधन हो गया। वह 71 वर्ष की थीं। वह 1980 और 1990 के दशक में टीवी समाचार जगत के सबसे जाने-माने चेहरों में से एक थीं और जिनकी शांत शैली आज के टेलीविजन समाचार बुलेटिन के शोरगुल से बिल्कुल अलग थी। माहेश्वरी 1976 से लेकर 2005 तक टीवी समाचारों का जाना-पहचाना चेहरा थीं। उनके साथ सलमा सुल्तान, मीनू तलवार, शम्मी नारंग, गीतांजलि अय्यर, नीति रविंद्रन और अन्य भी थीं। उनका नाम सुनते ही भारत के प्रसारण जगत और उसके श्वेत-श्याम से रंगीन प्रसारण में परिवर्तन की यादें ताजा हो जाती हैं। उस समय प्रसारण दिन में कुछ घंटों तक ही सीमित होता था और देखने के लिए केवल एक ही चैनल होता था। माहेश्वरी के निधन की जानकारी सबसे पहले उनके सह-समाचार वाचक और मित्र शम्मी नारंग ने दी। उनके निधन पर उनके सहयोगियों, दोस्तों, कांग्रेस और पुराने दर्शकों ने शोक व्यक्त किया और उनकी शांत, सौम्य और विशिष्ट 'सीधा पल्ला' साड़ी को याद किया। नारंग ने 'एक्स' और इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, 'मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि दूरदर्शन में मेरी पूर्व सह-समाचार प्रस्तोता सरला माहेश्वरी का निधन हो गया है... वह न केवल दिखने में सुंदर थीं बल्कि हृदय से भी कहीं अधिक उदार थीं, भाषा पर उनकी अद्भुत पकड़ थी और वह ज्ञान का भंडार थीं।'

हवाई अड्डों पर विमानों से पक्षियों के टकराने की घटनाएं 2025 में बढ़कर 1,782 हुईं : मंत्री

नयी दिल्ली: सरकार ने बृहस्पतिवार को लोकसभा को बताया कि देश के हवाई अड्डों पर विमानों से पक्षियों के टकराने की घटनाओं की संख्या 2024 के 1,278 से बढ़कर पिछले साल 1,782 हो गईं। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने लाइसेंस प्राप्त हवाई अड्डों पर वन्यजीवों से होने वाले संभावित खतरे से निपटने के लिए नियम बनाये हैं और दिशानिर्देश जारी किये हैं। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल द्वारा एक प्रश्न के लिखित उत्तर में साझा किये गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में देश के हवाई अड्डों पर विमानों से पक्षियों के टकराने की 6,337 घटनाएं हुईं। पिछले साल इस तरह की घटनाओं की संख्या 1,782 थी, जबकि 2024 में यह संख्या 1,278 थी। वहीं, 2023 में यह संख्या 1,371 और 2022 में 1,131 तथा 2021 में 775 थी।

दार्जिलिंग की मशहूर टॉय ट्रेन को 145 वर्षों में पहली बार महिला टिकट परीक्षक मिली

दार्जिलिंग: संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा विश्व धरोहर घोषित की गई दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे (डीए-चआर) को 145 वर्ष के उसके इतिहास में पहली महिला टिकट परीक्षक मिली है। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (एनएफआर) की अनुभवी कर्मचारी सरिता योलमो ने पांच फरवरी को अपनी नयी भूमिका में पहली बार न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक टॉय ट्रेन में सफर किया। योलमो ने 'पीटीआई-भाषा' को फोन पर बताया, 'दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की टॉय ट्रेन के इतिहास में पहली महिला टीटीई होने पर मुझे गर्व है।' डीएचआर की अधिकारी प्रतीक्षा छेत्री ने इसकी पुष्टि की कि योलमो टॉय ट्रेन सेवा में पहली महिला टीटीई के रूप में कार्यरत हैं। योलमो ने कहा कि जब उन्हें यूनेस्को की विरासत रेलवे सेवा में काम करने का अवसर मिला तो उन्हें रोमांच महसूस हुआ और जिम्मेदारी का भी एहसास हुआ। योलमो ने कहा, 'मैं दार्जिलिंग से हूं, लेकिन मुझे डीएचआर में काम करने का कोई पूर्व अनुभव नहीं था।' उन्होंने कहा कि वह पहले एक यात्री के रूप में टॉय ट्रेन में यात्रा कर चुकी हैं। वह वर्तमान में एनजेपी-दार्जिलिंग मार्ग पर एकमात्र महिला टीटीई हैं, यह यात्रा एक तरफ से लगभग आठ घंटे की होती है और रास्ते में देरी के कारण कभी-कभी इसमें अधिक समय भी लग सकता है।

दवा-प्रतिरोधी टीबी के लिए छोटी अवधि का दवा उपचार सस्ता, अधिक प्रभावी: आईसीएमआर

नयी दिल्ली: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के एक अध्ययन में पाया गया है कि बहु-दवा प्रतिरोधी (एमडीआर) और रिफैम्पिसिन-प्रतिरोधी तपेदिक (टीबी) के लिए छह महीने की दवा (गोली) आधारित उपचार योजना किफायती है। यह भारत में वर्तमान में प्रयुक्त की जा रही लंबी उपचार योजनाओं की तुलना में बेहतर स्वास्थ्य परिणाम प्रदान करती है। आईसीएमआर के राष्ट्रीय तपेदिक अनुसंधान संस्थान (एनआईआरटी) द्वारा किए गए आर्थिक मूल्यांकन को 'इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च' (आईजेएमआर) में प्रकाशित किया गया था। इसमें राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के तहत उपयोग में लाई जाने वाली नौ से 11 माह और 18 से 20 माह की बेडाक्विलिन युक्त उपचार योजनाओं की तुलना में बेडाक्विलिन-आधारित छोटी उपचार योजनाओं - बीपीएएल (बेडाक्विलिन, प्रेटोमैनिड और लाइनजोलिड) और बीपीएएलएम (मोक्सीफ्लोक्सासिन के साथ) की लागत-प्रभावशीलता का आकलन किया गया।

प्रधानमंत्री मोदी आज सेवा तीर्थ, कर्तव्य भवन 1, 2 का उद्घाटन करेंगे

नयी दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री कार्यालय की नयी इमारत सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का शुक्रवार को उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि यह उद्घाटन भारत की प्रशासनिक शासन संरचना में मील का पत्थर है और यह आधुनिक, कुशल, सुलभ एवं जन-केंद्रित शासन प्रणाली के निर्माण के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बयान में कहा गया है कि दशकों तक, कई प्रमुख सरकारी कार्यालय और मंत्रालय सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर बने और पुराने बुनियादी ढांचे से संचालित होते रहे हैं। बयान में कहा गया कि कार्यालयों के एक साथ नहीं होने के कारण परिचालन में अक्षमताएं, समन्वय संबंधी चुनौतियां, रखरखाव लागत में वृद्धि और कार्य के उचित वातावरण की समस्या पैदा हुई।

राज्यसभा ने तीन प्रमुख संसदीय समितियों के सदस्यों के नामांकन संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दी

नयी दिल्ली: राज्यसभा ने बृहस्पतिवार को तीन प्रमुख संसदीय समितियों के सदस्यों के नामांकन संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। ये सदस्य एक मई, 2026 से, एक वर्ष के लिए नियुक्त होंगे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने सभापति सी पी राधाकृष्णन की अनुमति से तीन अलग-अलग प्रस्ताव पेश किए, जिन्हें सदन ने मंजूरी दे दी। पहला प्रस्ताव लोक लेखा समिति से संबंधित है। सदन ने एक मई, 2026 से 30 अप्रैल, 2027 तक के लिए इस समिति में सात राज्यसभा सदस्यों को नामांकित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सदस्यों का चुनाव सभापति के निर्देशन में किया जाएगा। इसी तरह, लोकसभा की सिफारिश के अनुसार, राज्यसभा के सात सदस्यों को सार्वजनिक उपक्रम समिति में नामांकित करने के प्रस्ताव को भी सदन ने मंजूरी दी।

श्रमिक संगठनों की देशव्यापी हड़ताल: पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में व्यापक प्रदर्शन

चंडीगढ़: केंद्रीय श्रमिक संगठनों के संयुक्त मंच के आह्वान पर बृहस्पतिवार को देशव्यापी हड़ताल के तहत पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कर्मचारियों और श्रमिकों ने केंद्र सरकार की श्रम सुधार और आर्थिक नीतियों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र की नीतियों को 'कॉरपोरेट समर्थक' बताते हुए इन्हें श्रमिक-विरोधी करार दिया। चंडीगढ़ के सेक्टर-17 में बड़ी संख्या में कर्मचारी धरना-प्रदर्शन में शामिल हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनके हाथों में हम श्रम संहिताओं को खारिज करते हैं और हम श्रमिक-विरोधी श्रम संहिताओं का विरोध करते हैं जैसे संदेश लिखे पोस्टर थे। लुधियाना में पंजाब बैंक इम्प्लॉयीज फेडरेशन (पीबीईएफ) ने भारत नगर चौक पर विशाल रैली आयोजित की। हरियाणा के सोनीपत, रोहतक और हिसार सहित कई जिलों में भी प्रदर्शन हुए। हालांकि अधिकांश स्थानों पर बैंक और राज्य परिवहन की बस सेवाएं सामान्य रहीं। सोनीपत में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि बस अड्डा परिसर में आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। उन्होंने दावा किया कि मानेसर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, बावल और धारूहेड़ा के औद्योगिक क्षेत्रों के श्रमिक भी हड़ताल में शामिल हुए। आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं ने भी समर्थन दिया। श्रमिक संगठनों की प्रमुख मांगों में वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थितियां संहिता 2020 सहित चारों श्रम संहिताओं को रद्द करना शामिल है। इसके अलावा बीज विधेयक, बिजली संशोधन विधेयक के मसौदे और 'शांति' अधिनियम को वापस लेने की मांग की गई। मनरेगा की बहाली और 'विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025' को निरस्त करने की मांग भी उठी। पीबीईएफ के महासचिव पी.आर. मेहता ने आरोप लगाया कि नई श्रम संहिताएं हड़ताल के अधिकार को सीमित कर 'हायर एंड फायर' को बढ़ावा देती हैं। विभिन्न स्थानों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। संयुक्त मंच में इंटक,

आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस में 2,800 से अधिक पद रिक्त: सरकार

नयी दिल्ली: राज्यसभा में सरकार ने बृहस्पतिवार को बताया कि तीन अखिल भारतीय सेवाओं- आईएएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) में 2,800 से अधिक पद रिक्त हैं, जिनमें अकेले भारतीय प्रशासनिक सेवा में 1,300 अधिकारियों की कमी है। उच्च सदन में कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि एक जनवरी, 2025 को संकलित सिविल सूची के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में 1,300 रिक्तियां, भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में 505 और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) में 1,029 रिक्तियां हैं। सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार, आईएएस में रिक्तियों की दर लगभग 18.9 प्रतिशत है। स्वीकृत 6,877 पदों में से 1,300 पद रिक्त हैं। आईपीएस में लगभग 9.9 प्रतिशत रिक्तियां हैं, जिनमें स्वीकृत 5,099 पदों में से 505 पद खाली हैं। आईएफओएस की स्थिति सबसे खराब है, जिसमें स्वीकृत 3,193 पदों में से 1,029 पद रिक्त हैं, यानी रिक्तियों की दर लगभग 32.2 प्रतिशत है। कुल मिलाकर, तीनों अखिल भारतीय सेवाओं में स्वीकृत 15,169 पदों में से 2,834 पद रिक्त हैं, जो लगभग 18.7 प्रतिशत की कुल रिक्तियों को दर्शाता है। सभी कैडरों में आईएएस अधिकारियों की कुल स्वीकृत संख्या 6,877 है, जिनमें से 5,577 अधिकारी कार्यरत हैं। आईपीएस में, स्वीकृत संख्या 5,099 के मुकाबले 4,594 अधिकारी कार्यरत हैं, जबकि भारतीय वन सेवा में, स्वीकृत 3,193 पदों के मुकाबले 2,164 अधिकारी कार्यरत हैं। सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये कैडर-वार आंकड़ों से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में आईएएस पदों की स्वीकृत संख्या 652 है, जिनमें सर्वाधिक 571 अधिकारी कार्यरत हैं। मध्यप्रदेश में स्वीकृत संख्या 459 के मुकाबले 391 आईएएस अधिकारी कार्यरत हैं, जबकि महाराष्ट्र में स्वीकृत 435 पदों के मुकाबले 359 अधिकारी कार्यरत हैं। इसी प्रकार, आईपीएस में, बिहार, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी स्वीकृत संख्या और कार्यरत अधिकारियों के बीच कमी देखी गई है। भारतीय वन सेवा में विशेष रूप से अधिक रिक्तियां हैं, और कई राज्यों में स्वीकृत और भरे गए पदों के बीच काफी अंतर है।

न्यूज ब्रीफ

भारतीय अंडर-17 पुरुष टीम दूसरे मैत्री मैच में मेजबान तुर्किये से हारी

नयी दिल्ली : भारत की अंडर-17 पुरुष फुटबॉल टीम को बृहस्पतिवार को अंताल्या में हुए दूसरे मैत्री मुकाबले में मेजबान टीम तुर्किये से 1-6 से हार गई। भारत को मंगलवार को पहले दोस्ताना मुकाबले में 0-1 से पराजय का सामना करना पड़ा था। भारतीय टीम इन मैत्री मैच का इस्तेमाल एएफसी अंडर-17 एशियाई कप सऊदी अरब 2026 की तैयारी के लिए कर रही है जो मई में होगा। इसमें भारत ग्रुप डी में उज्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और उत्तर कोरिया से भिड़ेगा।

अर्जेंटीना ने हॉकी प्रो लीग में भारत को 8-0 से रौंदा

राउरकेला : भारत को बृहस्पतिवार को यहां एफआईएच पुरुष प्रो लीग के राउरकेला चरण में अर्जेंटीना से 0-8 से हार का सामना करना पड़ा। अर्जेंटीना के लिए टॉमस डोमेने ने चार गोल दागे। डोमेन (15, 20, 26, 60वें मिनट) के अलावा टॉमस रुइज (14वें मिनट), लुसियो मेंडेज (22वें मिनट), इग्नासियो इबारा (25वें मिनट) और निकोलस डेला टोरे (30वें मिनट) ने भी गोल किए। भारत ने शुरुआत में बढ़त बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर तक दबदबे के बाद उन्होंने पहले क्वार्टर के अंत में पेनल्टी स्ट्रोक मिलने पर बढ़त लेने का सुनहरा मौका गंवा दिया।

अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने पीएसएल नीलामी से नाम वापस लिए

कराची : अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) के 11वें चरण से पहले हुई खिलाड़ियों की नीलामी से अपने नाम वापस ले लिए। पीएसएल में यह नीलामी पहली बार कराई गई थी। एक फ्रेंचाइजी के मालिक ने शुरू में पुष्टि की थी कि मुजीबुर रहमान, सेदीकुल्लाह अटल, मुहम्मद नबी, वकार सलामखेल, फजल हक फारूकी जैसे खिलाड़ियों ने बुधवार को लाहौर में हुई नीलामी के लिए पंजीकरण कराया था।

इशान, पंड्या और चक्रवर्ती चमके, भारत ने नामीबिया को 93 रन से रौंदा

नयी दिल्ली : सलामी बल्लेबाज इशान किशन और हरफनमौला हार्दिक पंड्या के तूफानी अर्धशतकों के बाद वरुण चक्रवर्ती की घातक फिरकी से भारत ने आईसीसी टी20 विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में नामीबिया को 93 रन से करारी शिकस्त देकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 209 रन बनाए। जवाब में नामीबिया की टीम 18.2 ओवर में 116 रन पर सिमट गई। चक्रवर्ती ने सात रन देकर तीन विकेट झटके, जबकि जसप्रीत बुमराह (21 रन पर दो विकेट) और अक्षर पटेल (20 रन पर दो विकेट) ने भी अहम योगदान दिया। नामीबिया के लिए लॉरेन स्टीनकैंप (29) और जेन फ्राइलिंक (22) ही कुछ देर टिक सके। इशान ने 24 गेंद में 61 रन (5 छक्के, 6 चौके) ठोकते हुए तिलक वर्मा (25) के साथ दूसरे विकेट के लिए 31 गेंद में 79 रन जोड़े। उन्होंने छठे ओवर में लगातार चार छक्के जड़ते हुए 20 गेंद में अर्धशतक पूरा किया और भारत को विस्फोटक शुरुआत दिलाई। भारत ने पावर प्ले में 86 रन बनाए और 6.5 ओवर में टीम का स्कोर 100 रन पहुंच गया, जो पुरुष टी20 विश्व कप इतिहास के सबसे तेज शतकों में से एक है। मध्य ओवरों में कप्तान गेरहार्ड इरास्मस (चार ओवर में 20 रन पर चार विकेट) ने कसी हुई गेंदबाजी से भारत की रफ्तार थामी, लेकिन पंड्या ने शिवम दुबे (23) के साथ 39 गेंद में 81 रन की साझेदारी कर अंतिम ओवरों में स्कोर 200 के पार पहुंचाया। पंड्या ने 28 गेंद में 52 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए नामीबिया ने पावर प्ले में 57 रन जोड़े, लेकिन चक्रवर्ती ने स्टीनकैंप को बोल्ड कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और टीम अंतिम आठ विकेट 30 रन के भीतर गंवा बैठी। भारत अब 15 फरवरी को कोलंबो में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगा, जिस मुकाबले पर सभी की नजरें टिकी हैं।

आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने विंडहोक में स्टेडियम बनाने में मदद की: क्रिकेट नामीबिया के अध्यक्ष

नयी दिल्ली : क्रिकेट नामीबिया के अध्यक्ष रूडी वैन वुरेन ने गुरुवार को कहा कि विंडहोक में नए क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का श्रेय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के चेयरमैन जय शाह को जाता है। नामीबिया 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप का सह मेजबान है। वैन वुरेन ने एसोसिएट सदस्य देशों को सशक्त बनाने और उनके क्रिकेट बुनियादी ढांचे में सुधार करने के प्रयासों के लिए शाह की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा, ''आईसीसी ने एसोसिएट सदस्य देशों को सशक्त बनाने की नीति अपनाई है। जय शाह वास्तव में इसमें महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आए हैं। वह विंडहोक में हमारे नए स्टेडियम का दौरा करने आए थे। आईसीसी ने उस स्टेडियम के निर्माण में हमारी बहुत मदद की।''

श्रीलंका ने ओमान को 105 रन से हराया

पाल्लेकल : श्रीलंका ने टी20 विश्व कप में बृहस्पतिवार को ओमान को 105 रन से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। ग्रुप बी के मैच में जीत के लिये 226 रन के लक्ष्य के जवाब में ओमान की टीम नौ विकेट पर 120 रन ही बना सकी। श्रीलंका के लिये दुष्मंता चामीरा और महीष तीक्षणा ने दो दो विकेट लिये।

इटली ने नेपाल को 10 विकेट से रौंदकर टी20 विश्व कप में पहली जीत दर्ज की

मुंबई : टी20 विश्व कप में पदार्पण कर रही इटली ने ग्रुप सी मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए नेपाल को 44 गेंद शेष रहते 10 विकेट से हराकर आईसीसी टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इटली के स्पिनरों ने अनुशासित गेंदबाजी करते हुए नेपाल को 19.3 ओवर में 123 रन पर समेट दिया। कृशन कालुगामागे ने 18 रन देकर तीन विकेट चटकाए, जबकि बेन मानेंटी ने नौ रन देकर दो विकेट हासिल किए। सटीक लाइन-लेंथ और चुस्त क्षेत्ररक्षण के कारण नेपाल के बल्लेबाज दबाव में नजर आए। नेपाल की ओर से आरिफ शेख (27) और कप्तान रोहित पौडेल (23) ही कुछ हद तक टिक सके। 124 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इटली के सलामी बल्लेबाज एंथोनी मोस्का और जस्टिन मोस्का ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की। दोनों के बीच अटूट शतकीय साझेदारी हुई और टीम ने 12.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। एंथोनी ने 32 गेंद में नाबाद 62 रन (6 छक्के, 3 चौके) बनाए, जबकि जस्टिन ने 44 गेंद में नाबाद 60 रन (3 छक्के, 5 चौके) जोड़े। नेपाल ने अपने प्रमुख स्पिनर संदीप लामिचाने को देर से गेंदबाजी पर लगाया, तब तक इटली के बल्लेबाज 58 रन जोड़ चुके थे। नेपाल को इस मैच में जीत का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन इटली ने हर विभाग में बेहतर खेल दिखाते हुए एकतरफा जीत दर्ज की।

होटल बुकिंग नहीं, पाकिस्तानी हॉकी खिलाड़ियों ने सड़क पर गुजारे कई घंटे

कराची : पाकिस्तान हॉकी टीम के सदस्यों को कैनबरा पहुंचने पर कई घंटे सड़क पर बिताने पड़े क्योंकि धन के अभाव में पाकिस्तान हॉकी महासंघ होटल के बिल का भुगतान नहीं कर सका जिससे होटल बुकिंग रद्द हो गई। पाकिस्तानी टीम होबर्ट में एफआईएच प्रो लीग के दूसरे चरण के मैच खेलने आस्ट्रेलिया में है। टीम के सूत्रों के अनुसार खिलाड़ियों और टीम अधिकारियों को घंटों तक सड़क पर रहना पड़ा। एक सूत्र ने बताया ,'' खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिये कैनबरा में एक चार सितारा होटल में कमरे बुक किये गए थे। उन्हें बताया गया था कि पाकिस्तान खेल बोर्ड और पीएचएफ ने कैनबरा में उनके रहने के लिये सारे भुगतान कर दिये हैं।'' सूत्र ने कहा ,'' लेकिन पिछले सप्ताह कैनबरा पहुंचने पर पता चला कि उस होटल में कोई बुकिंग थी ही नहीं। टीम के मुख्य कोच ताहिर जमान टाइम जोन अलग होने के कारण पीएसबी और पीएचएफ अधिकारियों से संपर्क नहीं कर सके।'' सूत्र ने कहा ,'' ताहिर ने उन्हें इस स्थिति के बारे में बताया कि लाहौर से लंबा सफर करके आये खिलाड़ियों के पास आराम करने की कोई जगह नहीं है।'' हॉकी पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है और टीम प्रो लीग में आस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसी शीर्ष टीमों से खेल रही है।

भारत 2026 एएफसी अंडर-17 एशियाई कप के ड्रॉ में उज्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और उत्तर कोरिया के साथ

नयी दिल्ली : भारत को बृहस्पतिवार को कुआलालंपुर में एएफसी हाउस में कराए गए 2026 एएफसी अंडर-17 एशियाई कप के फाइनल ड्रॉ में ग्रुप डी में उज्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और उत्तर कोरिया के साथ रखा गया। यह टूर्नामेंट सऊदी अरब में पांच से 22 मई तक खेला जाएगा। भारत ने एएफसी अंडर-17 एशियाई कप के इतिहास में 10वीं बार क्वालीफाई किया। टीम क्वालीफायर में ईरान, लेबनॉन, फलस्तीन और चीनी ताइपे से आगे रही। भारतीय अंडर-17 टीम अपने अभियान की शुरूआत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगी जिसके बाद उज्बेकिस्तान और कोरिया के खिलाफ मुकाबले होंगे। उज्बेकिस्तान गत चैंपियन है जिससे उसने स्वत: ही टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई कर लिया। ऑस्ट्रेलिया को 2025 चरण में ग्रुप चरण से बाहर होना पड़ा था। उसने जॉर्डन, भूटान और फिलीपींस पर जीत के बाद 2026 चरण के टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई किया। दो दफा की पूर्व चैंपियन उत्तर कोरिया 2025 में सेमीफाइनल तक पहुंची थी, जिससे वह मौजूदा चरण में स्वत: ही क्वालीफाई हो गई। ग्रुप ए में मेजबान सऊदी अरब को ताजिकिस्तान, थाईलैंड और म्यांमा के साथ रखा गया है। ग्रुप बी में जापान, इंडोनेशिया, चीन और कतर शामिल हैं।

खेलो इंडिया शीत खेलों का दूसरा चरण 23 से 26 फरवरी तक गुलमर्ग में

नयी दिल्ली : खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का दूसरा चरण 23 से 26 फरवरी तक गुलमर्ग में खेला जायेगा जिसमें करीब 400 खिलाड़ी भाग लेंगे। खेलमंत्री मनसुख मांडविया ने बृहस्पतिवार को यह घोषणा की। पहला चरण 20 से 26 जनवरी के बीच लद्दाख में खेला गया था। मांडविया ने एक विज्ञप्ति में कहा ,'' गुलमर्ग चरण शीतकालीन ओलंपिक के ठीक बाद हो रहा है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के आयोजन के लिये यह बिल्कुल सही समय है। लेह में पहला चरण काफी कामयाब रहा था जिसमें फिगर स्केटिंग को शामिल किया गया था।'' गुलमर्ग में चार पदक खेलों स्की पर्वतारोहण, अल्पाइन स्कीइंग, नोर्डिक स्कीइंग (क्रॉसकंट्री) और स्नोबोर्डिंग की स्पर्धायें होंगी।

अभिषेक अब भी कमजोरी महसूस कर रहे, पाकिस्तान के खिलाफ खेलने पर अनिश्चितता

नयी दिल्ली : भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है लेकिन 15 फरवरी को कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले महत्वपूर्ण टी20 विश्व कप ग्रुप मुकाबले में उनके खेलने को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। पेट के संक्रमण से जुड़ी समस्या से जूझ रहे अभिषेक को तेज बुखार और पेट दर्द की शिकायत के बाद दो दिन के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। उन्हें बुधवार को दिल्ली के एक अस्पताल से छुट्टी मिल गई। लेकिन बृहस्पतिवार को जब भारतीय टीम ने कोटला मैदान पर अभ्यास किया, तब अभिषेक ने ट्रेनिंग नहीं की क्योंकि वे अब भी थोड़ा कमजोरी महसूस कर रहे हैं। उनका थोड़ा वजन भी कम हुआ है और पेट के गंभीर संक्रमण की स्थिति में पूरी तरह स्वस्थ होकर शीर्ष स्तर का क्रिकेट खेलने लायक ताकत और सहनशक्ति हासिल करने में समय लगता है। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने संकेत दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उनका खेलना संदिग्ध हो सकता है।

सोना 400 रुपये टूटा, चांदी स्थिर

नयी दिल्ली : कमजोर वैश्विक रुख और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में कटौती की उम्मीद कम होने के बीच बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें 400 रुपये टूटकर 1.6 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम रह गईं। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 400 रुपये या 0.25 प्रतिशत टूटकर 1,60,900 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी कर मिलाकर) रह गया। बुधवार को यह 1,61,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। हालांकि, स्थानीय सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतें 2,68,500 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी कर मिलाकर) पर स्थिर रहीं।

बिहार में 5,000 करोड़ का निवेश करेगी श्याम स्टील, गया में 10 लाख टन का कारखाना लगाएगी

पटना : बिहार में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार की पहल पर श्याम स्टील ने राज्य में 5,000 करोड़ रुपये का निवेश करने पर सहमति जताई है। कंपनी गया-डोभी रोड स्थित प्रस्तावित औद्योगिक गलियारे में एक अत्याधुनिक स्टील कारखाना स्थापित करेगी। यह जानकारी बृहस्पतिवार को उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने दी। उन्होंने बताया कि श्याम स्टील इस परियोजना के तहत 10 लाख टन सालाना क्षमता की स्टील विनिर्माण इकाई लगाएगी। इस परियोजना से राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलने के साथ-साथ लगभग 8,000 लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। डॉ. जायसवाल ने बताया कि निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने बेहतर प्रोत्साहन औद्योगिक नीति बनाई है, जिसके तहत निवेशकों को राज्य में लाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं।

रोजगार बिना वृद्धि संप्रग सरकार की कहानी, हमारी नहीं: सीतारमण

नयी दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में 2026-27 के बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि भारत मजबूत आर्थिक वृद्धि और निम्न बेरोजगारी दर के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि रोजगार के बिना वृद्धि संप्रग सरकार की कहानी थी, वर्तमान सरकार की नहीं। सीतारमण ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना अर्थव्यवस्था को मृत बताने वाली टिप्पणी को नकारात्मक करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान देश की जनता के योगदान का अपमान हैं, जो भारत की वृद्धि में सक्रिय भागीदारी कर रही है। मध्यम वर्ग पर कर बोझ बढ़ने के आरोपों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि व्यक्तिगत आयकर संग्रह का कॉरपोरेट कर से अधिक होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि मध्यम वर्ग को दबाया जा रहा है। उन्होंने आंकड़े देते हुए बताया कि 2013-14 में करदाताओं की संख्या 5.26 करोड़ थी, जो 2024-25 में बढ़कर 12.13 करोड़ हो गई है। पिछले 11 वर्षों में करदाताओं की संख्या दोगुनी हुई है, जो सालाना औसत 7.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। उन्होंने कहा कि आयकर सीमा सभी के लिए 12 लाख रुपये तथा वेतनभोगी वर्ग के लिए 12.75 लाख रुपये तक बढ़ाई गई है। मानक कटौती में वृद्धि और नई कर व्यवस्था के जरिए रिटर्न प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अगर 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कर नहीं देना पड़ता, तो मध्यम वर्ग को दबाने की बात कहां है, उन्होंने कहा। मुद्रास्फीति पर बोलते हुए सीतारमण ने कहा कि भारत में महंगाई कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम है और वर्तमान में कोई संकट नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों और स्थिरता के कारण मुद्रास्फीति नियंत्रित स्तर पर बनी हुई है। कल्याणकारी योजनाओं में कटौती के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की राशि 'मुफ्त भंडार' नहीं है, बल्कि जनता के कर से प्राप्त संसाधन हैं। उन्होंने बताया कि पिछले दस वर्षों में 14 सामाजिक योजनाओं में केवल 37,000 करोड़ रुपये बिना खर्च के रहे, जबकि संप्रग काल में यह राशि 94,000 करोड़ रुपये थी। सीतारमण ने कहा कि डीबीटी के माध्यम से 48 लाख करोड़ रुपये से अधिक सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजे गए हैं, जिससे 4.31 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई। उन्होंने कहा कि देश 'वृहद आर्थिक संतुलन' की दुर्लभ स्थिति में है, जहां उच्च वृद्धि दर और कम मुद्रास्फीति साथ-साथ बनी हुई हैं।

अधिक आयकर संग्रह का मतलब मध्यम वर्ग को दबाना नहीं, यह उनके आगे बढ़ने का सबूत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा कि व्यक्तिगत आयकर संग्रह बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि देश में मध्यम वर्ग को दबाया जा रहा है। उन्होंने 2026-27 के केंद्रीय बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि देश में मध्यम वर्ग को दबाने का कोई सबूत नहीं है, बल्कि उनके आगे बढ़ने के सबूत जरूर हैं। सीतारमण ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना अर्थव्यवस्था को मृत बताने वाले उनके बयान को नकारात्मक करार देते हुए कहा कि वह देश की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं, जो वास्तव में भारत के वृद्धि में अपना योगदान दे रही है।

सरकार ने नई सीपीआई श्रृंखला जारी की; जनवरी में खुदरा मुद्रास्फीति 2.75 प्रतिशत

नयी दिल्ली : वर्ष 2024 को आधार वर्ष मानते हुए जारी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) की नई श्रृंखला के तहत जनवरी में खुदरा मुद्रास्फीति 2.75 प्रतिशत रही है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी की गई नई श्रृंखला में वस्तुओं की संख्या 259 से बढ़ाकर 308 और सेवाओं की संख्या 40 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है, ताकि मूल्य स्थिति की बेहतर तस्वीर पेश की जा सके। खाद्य मुद्रास्फीति जनवरी में 2.13 प्रतिशत और आवासीय मुद्रास्फीति 2.05 प्रतिशत रही। वर्ष 2012 को आधार वर्ष मानने वाली पुरानी श्रृंखला के तहत जनवरी, 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति 4.26 प्रतिशत जबकि दिसंबर में 1.33 प्रतिशत रही थी। एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल मुद्रास्फीति दर 2.73 प्रतिशत और शहरी भारत में 2.77 प्रतिशत रही। नई सीपीआई श्रृंखला के अनुसार, तेलंगाना में महंगाई दर सबसे अधिक 4.92 प्रतिशत रही। इसके बाद केरल और तमिलनाडु का स्थान रहा। आंकड़ों के अनुसार, जनवरी में सबसे कम महंगाई वाली शीर्ष पांच वस्तुएं लहसुन, प्याज, आलू, अरहर, तुअर दाल और मटर रहीं। दूसरी ओर चांदी के आभूषण, टमाटर, नारियल खोपरा, सोना, हीरा, प्लैटिनम के आभूषण और नारियल तेल महंगे हुए।

सरकार ने आंशिक रूप से चालू राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर टोल दरों में कटौती की, 15 फरवरी से लागू

नयी दिल्ली : सरकार ने आंशिक रूप से चालू राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे के उपयोगकर्ताओं के लिए टोल शुल्क कम करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों में संशोधन किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा कि संशोधित नियम 15 फरवरी से लागू होंगे। बयान में कहा गया कि सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 में संशोधन को अधिसूचित किया है। मंत्रालय ने कहा कि इसके तहत यदि कोई राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे शुरू से अंत तक पूरी तरह चालू नहीं है, तो उसके केवल तैयार हिस्से पर सामान्य राष्ट्रीय राजमार्ग के अनुसार कम दर से टोल शुल्क लिया जाएगा। बयान में कहा गया कि वर्तमान में राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर उपयोगकर्ता शुल्क पूरी लंबाई के लिए सामान्य राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ता शुल्क से 25 प्रतिशत अधिक लिया जाता है क्योंकि वे तेज और निर्बाध यात्रा अनुभव प्रदान करते हैं।

भारत अगले साल नवंबर में करेगा विश्व डेयरी सम्मेलन की मेजबानी

नयी दिल्ली : भारत अगले साल नवंबर में अंतरराष्ट्रीय डेयरी महासंघ (आईडीएफ) के विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन (डब्ल्यूडीएस) की मेजबानी करेगा। मुंबई में होने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर के 1,500 प्रतिनिधि शामिल होंगे। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) ने बृहस्पतिवार को जारी बयान में कहा कि सम्मेलन का आयोजन भारतीय राष्ट्रीय समिति-आईडीएफ की तरफ से जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर (जेडब्ल्यूसीसी), मुंबई में किया जाएगा। एनडीडीबी के अध्यक्ष मीनेश शाह और आईडीएफ के महानिदेशक लॉरेंस राइकेन ने भारत में वर्ष 2027 का शिखर सम्मेलन आयोजित करने संबंधी समझौते का आदान-प्रदान किया। यह आदान-प्रदान केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान की उपस्थिति में भारतीय डेयरी संघ के 52वें डेयरी उद्योग सम्मेलन के दौरान हुआ। बयान के मुताबिक, इस वैश्विक सम्मेलन में 1,500 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। इनमें नीति-निर्माता, डेयरी किसान, सहकारी संस्थाएं, प्रसंस्करण इकाइयां, शोधकर्ता, वित्तीय संस्थान, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता शामिल होंगे। भारत ने इससे पहले वर्ष 2022 में दिल्ली-एनसीआर में इस वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की थी।

रुपया 17 पैसे बढ़कर 90.61 प्रति डॉलर पर

मुंबई : विदेशी कोषों के निवेश से निवेशकों का उत्साह बढ़ने से अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में बृहस्पतिवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे बढ़कर 90.61 पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि विदेशी कोषों का प्रवाह हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन इसने एक मनोवैज्ञानिक सहारा दिया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक यह पक्का कर रहा है कि बैंकिंग प्रणाली में नकदी की स्थिति भरपूर बनी रहे। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में, डॉलर के मुकाबले रुपया 90.55 पर खुला, और कारोबार के दौरान 90.40 के दिन के उच्चतम स्तर तक गया और 90.65 के निचले स्तर तक आया।

किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा बढ़ाने के लिए आरबीआई ने जारी किया मसौदा संशोधन

मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन और एकीकरण के लिए बृहस्पतिवार को मसौदा जारी किया जिसका उद्देश्य कवरेज का विस्तार, परिचालन प्रक्रियाओं का सरलीकरण और कृषि क्षेत्र की उभरती जरूरतों का ध्यान रखना है। केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा कि विनियमित संस्थाएं, आम लोग और अन्य हितधारक छह मार्च, 2026 तक मसौदे पर टिप्पणियां और सुझाव दे सकते हैं। आरबीआई ने केसीसी ऋण की स्वीकृति और पुनर्भुगतान कार्यक्रम में एकरूपता लाने के लिए फसल सत्रों की अवधि को मानकीकृत करने का प्रस्ताव भी रखा है। इसके तहत कम अवधि में तैयार होने वाली फसलों को 12 माह के चक्र और लंबी अवधि वाली फसलों को 18 माह के चक्र के रूप में परिभाषित किया गया है। लंबी अवधि की फसलों के चक्र के अनुरूप ऋण अवधि तय करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की कुल अवधि छह वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया है।

आईटी शेयरों में भारी बिकवाली से शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 559 अंक फिसला

मुंबई : अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कमजोर पड़ने और कृत्रिम मेधा (एआई) से व्यवधान की आशंकाओं के बीच सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) शेयरों में बिकवाली से बृहस्पतिवार को घरेलू शेयर बाजार नुकसान के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 559 अंक लुढ़क गया जबकि निफ्टी 147 अंक के नुकसान में रहा। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 558.72 अंक यानी 0.66 प्रतिशत टूटकर 83,674.92 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 716.97 अंक के नुकसान के साथ 83,516.67 अंक तक आ गया था। एनएसई का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी भी 146.65 अंक यानी 0.57 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,807.20 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में सबसे ज्यादा दबाव आईटी शेयरों पर रहा। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) में लगभग छह प्रतिशत की गिरावट आई। इसके अलावा एचसीएल टेक्नोलॉजीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, इंडिगो, कोटक महिंद्रा बैंक और अदाणी पोर्ट्स भी नुकसान में रहे। दूसरी तरफ बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एशियन पेंट्स, लार्सन एंड टुब्रो, भारती एयरटेल और टाटा स्टील के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ''अमेरिका में रोजगार के मजबूत आंकड़े आने के बाद फेडरल रिजर्व द्वारा नीतिगत दर में कटौती की संभावना कम होने और एआई से सेवा क्षेत्र की आय पर दबाव की आशंका से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई है।''

वर्ष 10, पूर्णांक 3502 अंक 312 RNI No WBHIN/2016/66788, सर्वांग प्रकाशन के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सरोज राय द्वारा रजि. 17, बालमुकुन्द मक्कर रोड, 2सरा तल्ला, कोलकाता-700 007 से प्रकाशित। एल. एस. पब्लिकेशन्स प्रा. लि. 4, कैनल वेस्ट रोड, कोलकाता-700 015 से मुद्रित। सम्पादक- अनिल कुमार राय (पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी), कॉर्पोरेट आफिस : 230, चित्तरंजन एवेन्यू, कोलकाता-700 006, विज्ञापन एवं प्रसार-9874555256/7044444522, ई-मेल news@samagya.in